खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-01) / अंक-47

बृहस्पतिवार 9 मार्च, 2017 / 18 फाल्गुन, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

पांचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-05 (भाग-01) में अंक 44 से अंक 48 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (1) बृहस्पतिवार, 9 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-47

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1 श्री शरद कुमार
2 श्री संजीव झा
3 श्री पंकज पुष्कर
4 श्री पवन कुमार शर्मा
5 श्री अजेश यादव
6 श्री महेंद्र गोयल
7 श्री वेद प्रकाश
8 श्री सुखवीर सिंह दलाल
9 श्री ऋतुराज गोविंद
10 श्री संदीप कुमार
11 श्री रधुविन्द्र शौकीन
12 श्रीमती बंदना कुमारी
13 श्री जितेंद्र सिंह तोमर
14 श्री राजेश गुप्ता
15 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16 श्री सोमदत्त
17 सुश्री अलका लाम्बा
18 श्री आसिम अहमद खान
19 श्री विशेष रवि
20 श्री हजारी लाल चौहान
21 श्री शिव चरण गोयल
22 श्री गिरीश सोनी

23 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)

24 श्री राजेश ऋषि

25 श्री महेंद्र यादव

26 श्री नरेश बाल्यान

27 श्री आदर्श शास्त्री

28 श्री गुलाब सिंह

29 कर्नल देवेंद्र सहरावत

30 सुश्री भावना गौड़

31 श्री सुरेंद्र सिंह

32 श्री विजेंद्र गर्ग

33 श्री प्रवीण कुमार

34 श्री मदन लाल

35 श्री सोमनाथ भारती

36 श्रीमती प्रमिला टोकस

37 श्री नरेश यादव

38 श्री करतार सिंह तंवर

39 श्री प्रकाश

40 श्री अजय दत्त

41 श्री दिनेश मोहनिया

42 श्री सौरभ भारद्वाज

43 सरदार अवतार सिंह कालकाजी

44 श्री सही राम

45 श्री नारायण दत्त शर्मा

46 श्री अमानतुल्लाह खान

47 श्री राजू धिांगान

48 श्री मनोज कुमार

49 श्री नितिन त्यागी

50 श्री एस. के. बग्गा

51 श्री अनिल कुमार बाजपेयी

52 श्री राजेंद्र पाल गौतम

53 श्रीमती सरिता सिंह

54 मो. इशराक

55 श्री श्रीदत्त शर्मा

56 चौ. फतेह सिंह

57 श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-05 बृहस्पतिवार, 9 मार्च, 2017/18 फाल्गुन 1938 (शक) अंक-47

सदन अपराह्न 2.05 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अधयक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह जी का जन्मदिन है, जरनैल जी आए तो हैं, नहीं! मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। धान्यवाद।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

अब सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले सदन में उठाए जाएंगे। श्री प्रवीण कुमारजी, नहीं हैं, प्रकाश जारवाल जी, संदीप कुमार जी, सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अधयक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धान्यवाद कि आपने मुझे नियम 280 के तहत मुद्दा उठाने दिया।

अधयक्ष महोदय, पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली का हर निवासी बहुत आभारी है जल बोर्ड का और इस सरकार, इन्होंने अभूतपूर्व काम किए हैं, जल के क्षेत्र में। अब तक 309 अनॉथराइज कालोनियों के अंदर पाइप लाइन बिछाया

गया और बहुत कुछ किया गया। लेकिन मेरी कन्स्टीट्यूएंसी मालवीय नगर में कुछ मुसीबतें ऐसी हैं, जनका समाधाान नहीं हो रहा है। पिछले दो साल से मैं लगातार जल बोर्ड के अधिाकारी वादा भी कर रहे हैं लेकिन वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय केजरीवाल साहब ने जल बोर्ड की मीटिंग में बाकायदा कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि रात को उठ-उठकर के लोग पानी भरें। उसके बावजूद अभी तक जल बोर्ड की तरफ से सप्लाई की टाइमिंग्स को न तो सुधाारा गया है, न ही पानी, जो एक वक्त सप्लाई हो रहा है, उसको दो वक्त किया गया। बड़ी पीड़ा होती है! क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर के जल बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है; जो डिपार्टमेंट्स अपने हैं, कम से कम वो तो हमें सुख सुविधाा दे दें। मालवीय नगर के अंदर दो वक्त का सप्लाई बहुत समय से हम बात कर रहे हैं, बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि भई, अभी वहां की महिलाओं को, बेटियों को, मां, बहनों को उठना पड़ता है रात को ढाई बजे, दो बजे। कोई वक्त है सप्लाई का? हम कह रहे हैं कि भई, 5 से 8 सवेरे कर दो, 5 से 8 शाम को कर दो। दो साल से कह रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा।

अध्यक्ष महोदय तो मेरी आपके माधयम से सरकार से गुजारिश है कि हमारे क्षेत्र में सप्लाई की टाइमिंग्स दो वक्त की जाए। 5 से 8 सवेरे, 5 से 8 शाम को और चूंकि वाईस चेयरमैन बैठे हैं यहां पर जल बोर्ड के, अगर वो चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं और तीन घंटे की सप्लाई सवेरे, तीन घंटे की सप्लाई शाम को कर दें।

अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो सप्लाई है, जो यूजीआर हे अंडर ग्राउंड रिजर्वायर, वो डीयर पार्क में है। वहां से सप्लाई

सबका होता है; महरौली का भी होता है, छत्तरपुर का भी होता है, मुनिरका का भी होता है। उनके यूजीआर से सप्लाई होता है। लेकिन मेन यूजीआर से मेरे यहां घरों को डॉयरेक्टली सप्लाई होता है। इस कारण रात का टाइमिंग्स है। मैंने बार बार कहा कि सैपरेट यूजीआर बना दिया जाए। हमारे लिए बनाया नहीं गया अभी तक।

अध्यक्ष महोदय, बहुत पीड़ा होती है। ये कह के कि इतनी दिल्ली के अंदर इतने अच्छे-अच्छे काम कर रहा है। जल बोर्ड, लेकिन मेरे यहां कुछ पता नहीं, क्या मुसीबत है!

अध्यक्ष महोदय, ये 24 घंटे का जो जरनैल भाई ने अभी सारे में कहा है 24 घंटे में सप्लाई हमारे यहां हुआ, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। उससे क्या हुआ? 24 घंटे की सप्लाई तो हो गया। एक छोटी सी कालोनी गीतांजली एन्कलवे में गया, नवजीवन बिहार में हो गया लेकिन उसके चक्कर में पूरे क्षेत्र से ही ये मांग आ रही है कि 24 घंटे हमारे यहां कब होगा। आप एक जगह 24 घंटा गया और बाकी क्षेत्र के अंदर दो घंटा, तीन घंटा ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो बहुत मुसीबत हो रही है। किसी ने एप्रिशिएट करने का प्रयास किया?

अध्यक्ष महोदय, साथ में आपके माधयम से, मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं, सरकार को प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बहुत समय से पेंडिंग है कि स्लम्स के अंदर इंडिविजुअल वाटर कनेक्शंस मिलें, वो बहुत पुरानी मांग रही है और अभी तक हमें कहा जा रहा है कि भई, हमें केबिनेट में पास करना है थोड़ा, सदन के पटल पे ले के आना....पता नहीं कब होगा। पिछले वक्त के अंदर स्लम्स के अंदर खासकर के मेरे यहां दो स्लम्स हैं, उनके पास

पुरानी पाइपों से हर घर में कनेक्शन था, अब लीगल था, इल्लीगल था, इसकी कोई चिंता नहीं करता। अब जो नए पाईप लाइन डले हैं, उसमें से इंडिविजुअल कनेक्शन लेने के लिए मना कया जा रहा है। कह रहे हैं कि भई, कोई कानून का प्रावधाान लाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी पहले था, माननीय केजरीवाल साहब ने बड़े खुले शब्दों में जल बोर्ड को आदेश दिया था कि जो कुछ पहले था, उससे इम्प्रूव करना है। (210) ये नहीं क जो पहले था, उसे खराब कर देना। भई, आप पूरी दिल्ली के अंदर अच्छा कर रहे हैं, बहुत-बहुत मुबारकबाद, धान्यवाद, लेकिन साथ में जिन-जिन क्षेत्रों के अंदर जो कुछ भी सहूलियतें थी, उससे आगे बढ़ाना है। भई, हमारे यहां पहले 2 वक्त सप्लाई हुआ करता था, उसको वापस कर दीजिए। हमारे यहां जो भी इस तरह की सुविधाएं थी, उसको वापिस कर दीजए। आपके माधयम से मैं ये विनती करना चाहता हूं सरकार को कि कृपया करके इस पर प्रकाश डालें और हमारी मुसीबतों का समाधाान करें। धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : असीम अहमद जी।

मो. आसिम अहमद खान : धान्यवाद, अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी सोमनाथ भाई ने कहा, मेरी बात भी पानी से रिलेटिड है, जल बोर्ड से रिलेटिड ही है। मैं पिछल दो सालों से, जल बोर्ड से इस बात का निवेदन कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी बढ़ा दिए जाए। पानी की बहुत किल्लत है। दो साल में मैंने सीईओ जल बोर्ड से लेकर माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी से भी मीटिंग की। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, उल्टा ये हुआ कि आज से 10 दिन पहले मेरे क्षेत्र का पानी काट दिया गया और जो सप्लाई मेरे क्षेत्र में 11 फीट के लगभग हमारी यूजीआर में पानी का लेबल आया

करता था, वो पिछले 10-12 दिन से सिर्फ साढ़े सात फीट हो गया और इससे हमारे आधो एरिये के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई है। आधो ही लोगों को पानी मिल रहा है। पिछले 10 दिन से। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माधयम से ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि पानी हमारा किस वजह से कम कर दिया? भई, एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड अखबारों में बड़े-बड़े इश्तेंहार दे रहा है कि दिल्ली में आने वाली गर्मी में पीन की कोई कम नहीं होगी। अभी गर्मी की शुरूआत भी नहीं हुई, और हमारा पानी 11 फीट से साढ़े सात फीट कर दिया गया है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां, मेरे क्षेत्र बड़ा कंजस्टिड क्षेत्र है। वहां पर बड़ी बोरिंग नहीं हो पाती। पिछले दो साल से मैंने माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी से भी उसकी गुजारिश की थी बोरिंग के लिए और सीईओ जल बोर्ड से भी की थी। लेकिन अभी तक एक भी बोरिंग, दो साल के अंदर हमारे क्षेत्र में एक भी सिंगल सेलो बोरिंग नहीं हो पाई। तो अध्यक्ष जी, मैं इसमें चाहता हूं कि पानी की जैसे कि आगे गर्मी आ रही है, बहुत दिक्कत पानी की होने वाली हैं तो इसमें आप जल बोर्ड को आदेश करें कि हमारे पानी का लेवल किस वजह से, किन कारणों से 11 फीट से साढ़े सात फीट कर दिया गया है। सिर्फ एक घंटा एरिया के अंदर पानी की सप्लाई हो रही है धान्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लांबा : धान्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे 280 नियम के तहत अपनी बात क्षेत्रीय समस्या रखने को कहा।

अध्यक्ष जी, हम विधाायकों को 4 करोड़ रूपये का सालाना फंड मिलता है जिसमें से एक करोड़ रूपये दिल्ली जल बोर्ड हमसे पहले ले लेता है बाकी बचता है पूरे साल का 3 करोड़ रूपये। अध्यक्ष जी, जो 3 करोड़ रूपया मुझे क्षेत्रीय विकास के लिए विधाायक एमएलए लेड फंड में मिला, जामा मस्जिद वार्ड से मैंने तीन करोड़ में से दो करोड़ रूपया, लगभग दो करोड़ रूपया सिर्फ नगर निगम को दे दिया, एक जामा मस्जिद वार्ड के लिए। मुझे दूसरे वार्ड वालों से बहुत शिकायतें आई कि मैंने भेद-भाव किया है लेकिन दु:ख की बात ये है कि जामा मस्जिद की जो संकीर्ण गलियों की हालत थी, बड़े-बुजुर्ग, बच्चे गिरकर घायल हो रहे थे और नगर निगम अपने फंड से उन गलियों को बनाने को तैयार नहीं था, यह हालत 5-6 साल से चल रही थी। लेकिन मैंने फिर भी लोगों की समस्याओं को देखते हुए, नगर निगम का पैसा ना होने का रोना वो रोते रहे। लेकिन मैंने फिर भी एमएलए लेड फंड से इस साल का दो करोड़ रूपया दिल्ली नगर निगम को दिया। अध्यक्ष जी, 10-11-2016 चार महीने पहले सेंक्शन आर्डर दिया गया एक 1,63,04,300 रूपया दिल्ली नगर निगम को चार महीने पहले दिया। चार महीने हो गए पैसे लए हुए 1,63,04,300 रूपए जामा मस्जिद वार्ड के लिए, अध्यक्ष जी अभी तक एक रूपया खर्च नहीं किया और गलियों की जो हालत है, वो उसी तरह आज भी बदतर बनी हुई है। अध्यक्ष जी, उसके बाद दो गलियों का और बजट इन्होंने मुझे बनाकर दिया। लोगों के निवेदन पर नगर निगम मेमं ये मुझे दिया 6 फरवरी का जिसको एक महीना हो गया 27,85,200 रूपये दिया हुआ है। अध्यक्ष जी, एक भी नहीं, उसके अलावा गली काजीवाड़ा जामा मस्जिद, गली नीलकंठ, जामा मस्जिद गली शंकर वाली, चांदनी चौक तीन गलियों का पैसा लेने के बाद इन्होंने काम यूं शुरू किया कि गलीको खोद दिया और खोदने

के बाद आज तक वो गलियां नहीं बन पा रही है। ये अलग बजट की गलियां हैं। तो अध्यक्ष जी, में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं जो नार्थ दिल्ली एमसीडी है, जिसने एमएलए लेड फंड से हमने सिर्फ इसलिए पैसा दिया कि लोग बहुत परेशान हैं, नगर निगम काम नहीं कर रहा, नगर निगम पार्षद जो है, सरकार बीजेपी की है, पर पार्षद कांग्रेस के हैं। पिछले 10 सालों से वही पार्षद है और वही बीजेपी की सरकार नगर निगम में है और पिछले दो सालों में हमने अपने बहुत से काम रोके अध्यक्ष जी, हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगाना था, हमने स्ट्रीट लाईट भी लगानी थी हमने फिर भी इसको प्राथमिकता दी कि नहीं ये गलियां बनना बहुत जरूरी है। रोज घटनाएं हो रही है, संकीर्ण गलियां है। ल ेकिन आज दु:ख की बात है कि मेरे एमएलए लेड फंड का जो दो करोड़ रूपया है, सिर्फ जामा म स्जिद वार्ड के लिए, नगर निगम उसे अपनी जेब में रखकर मुझे लग रहा है सिर्फ ब्याज खा रही है और इन अधि ाकारियों को, मैं आपसे इस सदन के माधयम से कहना चाहूंगी, कि जरूर जवाब दें कि दो करोड़ रूपया लेकर उन्होंने क्या किया? सिर्फ ब्याज खाया है, खर्च नहीं किया तो क्यों नहीं किया? उसके कारण बताने होंगे और जो गलियां खोद दी है आधाी, वो कब तक बन जायेंगी, जिन तीन गलियों के मैंने नाम लिए हैं।

अध्यक्ष जी, जरूर, क्योंकि नगर निगम का चुनाव आ रहा है जनता को हमें जवाब देना है और मुझे लग रहा है साजिश के तहत ही ये काम नहीं किए जा रहे हैं ताकि हम विधाायकों को घेरा जाए। जबकि ये जो सेंक्शन फंड की कापी है, मैंने पूरे अपने जामा मस्जिद वार्ड में बांट दी है कि एमएलए जो कर सकता था, अपने विधाायक निधि से फंड 50 कामों को रोककर हमने दिए हैं। अगर ये नहीं करते तो जवाबदेही विधाायक की है या नगर निगम

की है, ये जवाबदेही तय हो ताकि जनता को नगर निगम के चुनावों को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस पार्षद, वहां गुमराह करना बंद करें। धान्यवाद अध्यक्ष जी।

श्रीमती सरिता सिंह : पूरे मृद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। नगर निगम के चुनाव हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है सारे के सारे पैसे एमसीडी....

....(व्यवधाान)

अध्यक्ष महोदय : अभी एक बार बैठेंगे? एक बार बैठिए, ऋषि जी प्लीज। सरिता जी बैठिए, एक बार, मेरी बात सुनिए। एक बार बैठिए, प्लीज। सोमनाथ जी, बैठिए, प्लीज बैठिए। एक बार धयान से सुन लें जरा।

भावना गौड़ जी के नेतृत्व में एक कमेटी यहां बनी हुई है; कारपोरेशन की कमियों को धयान में रखने के लिए। एक बार तो सभी विधाायकों से मेरी प्रार्थना है कि आज उनको लिखकर के दें। सरिता जी, एक बार सुन तो लें दो मिनट। आप बैठिए, तो सही प्लीज, आप बैठिए, दो मिनट बैठिए। आप दो मिनट बैठेंगे।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि स्वाभाविक तौर पर विधाानसभा में कमेटी बनाई है, दिल्ली नगर निगम की कमेटी। बहुत सारे पत्र भी लिखे लेकिन वहां कम लोग मेरे पास तक पहुंच पाए हैं। मैं लगातार सभी साथियों से बोल रही थी कि वो पत्र मुझे दें। जिन लोगों के पत्र मेरे पास आए, मैंने कमिश्नर को बुलाकरा उस पर चर्चा की थी। उनके ऊपर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए मेरा सदन से निवेदन है कि जैसे सरिता जी कह रही हैं कि एक दिन के लिए....(220)

....(व्यवधाान)

अध्यक्ष महोदय : चलिये, मैं बात करता हूं उस विषय पर। भई, देखो, इसमें मेरी प्रार्थना है, एक सेकेंड रूकिये प्लीज। ये 280 पूरा होने दें।

श्री सहीराम : अध्यक्ष महोदय, पीछे एक कमेटी ने फैसला लिया था तीनों कमिश्नर का बुलाने का। उन्होंने हाथ खड़े कर दिये कि हमें आदेश नहीं है। बीजेपी की सरकार है। मेयर ने और स्टेंडिंग कमेटी चेयरमैन ने हमें साफ मना कर दिया कि हम आपकी मीटिंग में नहीं आयेंगे। उस कमेटी का क्या करेंगे बताइए आप!

अध्यक्ष महोदय : मैं करता हूं इसको, इस पर बात करता हूं। चर्चा के लिए मेरा ये कहना है, बजट पर जब चर्चा होगी तो इस पर व्यक्तिगत तौर पर इस विषय पर चर्चा के दौरान अपने यहां की समस्या को उठा सकते हैं। बाकी सरिता जी मैं इस चीज को देखता हूं। मैं इसको देखता हूं कैसे करना है। मैं इसको देखता हूं क्या कर सकता हूं इस पर। कल मैं जानकारी दूंगा पूरी। विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपके माधयम से सरकार का ध यान उस वायदे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं एक संवाददाता सम्मेलन में ये कहा था कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जो शराब की दुकानें हैं, वहां से बंद की जायेंगी, वहां से शिफ्ट की जायेंगी और दिल्ली की बस्तियों में, गलियों में, रिहायशी इलाकों में जो शराब की दुकानें हैं, वहां का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होता है। छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं के जीवन पर इसका सीधाा असर पड़ता है और वहां का जो माहौल उसके

कारण स्थापित हो रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। इस मामले में वहां पर शराब की दुकानों के कारण रहने वालों का जीवन दूषित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। लेकिन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य सरकार के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अपना प्रतिनिधित्व लिख-लिखाकर दे रहे हैं और सरकार ने ये जो घोषणा की थी और योजना के तहत की थी कि इनको यहां से हटायेंगे औरबाकी जगह उनको स्थानांतरित भी किया जा सकता है, तो सवाल ये है कि इस संबंधा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माधयम से सरकार को ये भी धयान दिलवाना चाहता हूं कि आपने कहा था कि जो लोग सड़कों पर शराब पीते हैं, गाड़ी में बैठकें शराब पीते हैं, पार्कों में बैठ के शराब पीते हैं क्योंकि ये जो रिहायशी इलाकों में दुकानें हैं, वहां भी यही होता है कि लोग पास-पड़ोस के पार्क में, बाजार में खड़े होकर, किसी दुकान पर बैठकर, गाड़ी में बैठकर वहां शराब पीते हैं। 5000 रूपये जुर्माना होगा। बहुत इसकी पब्लिसिटी भी की गयी। बहुत जगह इसके हार्डिंग भी लगे और शुरू में जब ये प्रचार हुआ, इस पर कुछ कार्रवाई भी सुनने को आयी लेकिन मैं देख रहा हूं अध्यक्ष जी, आपक माधयम से मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं क अब उसतरह की कार्रवाई मानो जैसे है नहीं। लोगों के हौसले उसी तरह बुलंद हैं। उसी तरह की स्थितियां हैं। उसी तरह जो रेहड़ियां हैं ऐसी जहां पर चोरी से शराब बेंची जाती हैं। वो काम भी उसी तरह से प्रारंभ हो चुका है, जारी है। हालांकि सरकार बार-बार दावा करती रही है कि हम दिल्ली में शराब को प्रोत्साहित नहीं करेंगे लेकिन सरकार ने समय-समय पर लाईफलाइन की बात की। 25 वर्ष से कम आयु पर शराब रेस्टोरेंट में मिल सकेगी, इसकी बात की। प्रिलिज मोहल्लों में, गली मोहल्लों में, दुकानों पर प्रिविलेज की बात की और जिसके कारण सरकार का रेवेन्यू

भी बढ़ा। नई दुकानें बहुत बड़ी तादाद में खोली गयीं लेकिन मैं उस चर्चा को उस मोड़ पर नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं स्पेसिफिकली दोनों विषयों पर अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो जुर्माने की योजना है, सरकार इस पर निश्चित रूप से सदन को अवगत कराये कि अब कितने चालान हो रहे हैं, कितने लोगों के जुर्माने लगाये गये हैं और कौन सी दुकानें....और जो दुकानें हटायी जायेंगी, वो किस तरह से हटायीं जायेंगी। उनका रोडमैप क्या होगा और कितने समय में रिहायशी क्षेत्रों से ये दुकानें हटायीं जायेंगी? ये सदन इस बात को जानना चाहेगा क्योंकि मुझे लगता है इस समस्या से अधिाकांश हमारे साथी प्रभावित होंगे। क्षेत्र की जनता उनके पास आती होंगी। आन्दोलन होते हैं, ध ारने गते हैं और लोग आवाज उठाते हैं। महिलाएं विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं और सरकार इस ओर धयान दें, ये मेरा सरकार से अनुरोधा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयल : धान्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया। अलका लांबा जी ने जो आवाज उठायी, मैं उसका समर्थन करता हूं कि हम लोग पैसे देते हैं एमसीडी को जनहित के कार्यों के लिए। लेकिन एमसीडी न तो एमएलए लैड के फंड से कोई भी काम कर रही है। यही पोजिशन मेरे साथ है और जो लाईटों के नाम पर स्ट्रीट लाईट होती है, उसकी पोजिशन ये कर रखी है कि सभी की सभी लाईटें जब से हम चुनाव जीतकर आयें हैं, तब से सैक्टरपांच और छः के अंदर ये एक भी सिंगल लाईट एमसीडी की वहां पर जल नहीं रही है। वो एनडीपीएल को पेमेंट नही कर रही है और एनडीपीएल ने वो लाईटें काटी हुई हैं। खंभों पर वो लाईटें एज इट इज लगी हुई हैं और ये पहले भी कई बार कह चुका हूं,

डीसी सहाब के नॉलेज में कई बार लेकर आया। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो एमसीडी का है, उसको कई बार कहा, लेकिन आज तक ये लाईटें चालू नहीं हुई।

मैं आपके माधयम से ये कहना चाहता हूं कि इन लाईटों को चालू करवाया जाये क्योंकि वहां पर चोरी की वारदातें हुत बढ़ रही हैं। जहां पर अंधोरा होता है, वहां पर खड़े होकर शराब पी जाती है। चाकूबाजी बहुत हुई है। यदि आज विजय विहार थाने का रिकार्ड उठा के देखें तो चोरी की घटना इतनी हुई हैं और हो रही हैं दिन पर दिन, सिर्फ इस अंधोरे का फायदा उठाकर। तो आपके माधयम से मैं यही कहूंगा एमसीडी के कमिश्नर साहब को कि हमारे जोन के जो डीसी हैं, उसको बुलाकर आप ये हिदायत दें कि इन लाईटों को चालू करें ताकि जनता आराम की जिंदगी जी सके। धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : धान्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माधयम से दिल्ली सरकार का धयान दिल्ली सरकार के स्कूलों के कुप्रबंधान के कारण हो रही जन-समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली सरकार पांच सौ नये स्कूल खोलने के लक्ष्य में पूरी तरह विफल रही हैं। अभी दो वर्षों में केवल दो नये स्कूल भी पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाये हैं। लगभग तीन हजार अधयापकों, प्रधानाचार्य सॉरी तीस हजार अधयापकों, प्रधानाचार्यों तथा स्पेशल एजूकेटरों के नियमित पद भरने के लिए शुरूआत तक नहीं की गयी है। दिल्ली सरकार, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को रोकने में विफल रही हैं। सरकार ने अधयापकों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु 102 करोड़ रूपये का बजट आमंत्रित किया था परंतु सरकार अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह विफल रही है। नौंवी कक्षा में एक लाख

से अधिाक विद्यार्थी फेल हो गये और एक सर्वे के अनुसार छठीं कक्षा में पढ़ने वाले 90 प्रतिशत छात्र अपना नाम तक नहीं लिख-पढ़ पाते। महोदय, इसका क्या कारण क्या है? इसका निदान क्या है? इसके शीघ्र समाधाान करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इन सबका कारण मैं समझता हूं सरकार गुमराह कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका धयान दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा निदेशालय द्वारा 18 जनवरी, 2016 को 9623 अध्यापकों की भर्ती के आदेश जारी किये गये थे। सरकार सदन के माधयम से जनवरी के सत्र में उत्तर उपलबधा करवाया था कि इनकी भर्तियां शीघ्र डीडीसीएल के माधयम से जनवरी के सत्र में इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जायेाग। सरकार स्पष्ट करे के क्या दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग कर दिया गया है? (230) ईडीसीआईएल इंडिया द्वारा अधयापकों की भर्ती के आदेश, स्थायी अधयापकों की भर्ती हेतु या गेस्ट टीचर्स के लिए थे? सरकार बताये कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ न करने के क्या कारण हैं और यह प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जाएगी? सरकार यह भी बताये कि भर्ती की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और भर्तियां कब तक पूरी हो जाएंगी?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोधा करता हूं कि वो शीघ्र ही इस संबंधा में आवयश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी करें। धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धान्यवाद। सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्त : धान्यवाद, अध्यक्ष महोदय। हर एक विधाायक का चार करोड़ रूपये का एमएलए लैड फंड विकास कार्यों के लिए होता है और मैं

दिल्ली सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि पहले हर साल एक करोड़ रूपये कंपलसरी दिल्ली जल ोर्ड को दिया जाता था, जो अब की बारी इस फाइनेंशियल ईयर से यह क्लॉज खत्म कर दी गई है तो हम चार का चार करोड़ रूपये कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस काम के लिए सबसे पहले मेरी तरफ से बधाई।

दूसरा, मेरी असेम्बली में लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं और चार वार्ड है। कई हजारों गलियां हैं और चार करोड़ रूपये का फंड मुझे लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। बहुत थोड़ा सा फंड है यह, जिससे सारे काम नहीं कराये जा सकते। इसमें हमें सड़कें भी बनवानी होती हैं, लाइटें भी लगवानी होती हैं, बैंच, बिजली के काम, बहुत तरह के काम होते हैं। चार करोड़ रूपये चार वार्ड में अगर बांटते हैं तो एक करोड़ रूपये एक वार्ड के हिस्से में आता है और यह बहुत छोटा एमाउंट है। इससे सारे काम नहीं हो सकते। इस साल भी ऐसा ही हुआ। दिसंबर तक सारा चार का चार करोड़ रूपये सैंक्शन हो गया। अभी जनवरी, फरवरी और मार्च के तीन महीने से लोग अपने काम लेकर आ रहे हैं। फंड्स हमारे पास हैं नहीं। मेरी यह प्रार्थना है कि चार करोड़ रूपये के इस एमाउंट को कम से कम दस करोड़ रूपये करना चाहिए ताकि पूरे एरिया की उन हजारों गलियों में और बहुत सारे विकास के काम जो एमएलए लैड फंड के तहत् हम करवा सकते हैं, वो सारे काम किये जा सकें, क्योंकि चार करोड़ बहीुत कम एमाउंट है। बहुत सारे काम इसमें बचे रह जाते हैं इसलिए मेरा इस सदन से, आप सबसे अनुरोधा है कि इस मांग को आगे बढ़ाया जाये और चार करोड़ की जगह एमएलए लैड फंड को कम से कम दस करोड़ किया जाए। धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धान्यवाद। जो विधाायक अभी नहीं आये थे मैं दोबारा नाम पढ़ रहा हूं श्री प्रवीण कुमार जी, नहीं आये, अभी भी। श्री प्रकाश जारवाल जी, नहीं आये। श्री संदीप कुमार जी।

श्री संदीप कुमार : धान्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धयान अपनी विधाान सभा क्षेत्र में जो मंदिर है जो दिल्ली सरकार के कंझावला के एसडीएम हैं, उन्होंने पिछले महीने खूब तोड़-फोड़ की, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के और अभी परसों ही कुछ लोगों के छज्जे बाहर निकले हुए थे, पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत वो लोग काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। छोटी-छोटी गलियां हैं और बहुत ज्यादा संकरे मकान बने हुए हैं वहां पर, लेकिन एसडीएम कभी भी आता है गुंडों की तरह, वहां पर तोड़-फोड़ मचाकर चला जाता है। इस बात की शिकायत माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से भी चार-पांच दिन पहले की थी ओर यह जो मंदिर है, जितने भी टारगेट किए जा रहे हैं इनमें ज्यादातर बौद्ध विहार और वाल्मीकि मंदिर है। सब लोग धार्म निरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन टारगेट इस देश में सिर्फ दलित, मुसलमान और पिछड़ों को किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आपको बड़ी गंभीरता से नम्र निवेदन करता हूं कि इन लोगों की तरफ थोड़ा धयान दिया जाये और एसडीएम को सख्त से सख्त निर्देश दिए जाएं कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई, जो आपको लगता है कि अनधिाकृत कब्जा है तो कम से कम वहां के विधाायक से पूछें, जिस भी एरिया में जाते हैं, वो आपको बतायेंगे। ये घुस जाते हैं कभी भी, तोड़-फोड़ मचाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो अधिाकारी हैं, हम ऐसे ही करेंगे। सरकार ने ऑर्डर कर रखे हैं। अब सरकार ऑर्डर करे तो हमारे भी संज्ञान में होना चाहिए।

अब पता नहीं यह किस तरह के ऑर्डर हैं, क्या है! आपसे निवेदन है कि इस एसडीएम को थोड़ा बुलायें और बुलाकर समझाएं। हम जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के लिए काम करते हैं। किसी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो जनता को परेशान करने का काम इन अधिकारियों का का नहीं है। हां, यह बात समझ में आती है कि अगर एमसीडी तोड़ती तो बात समझ में आती, बीजेपी वाले तोड़ते तो समझ में आती, एसडीएम तो दिल्ली सरकार का ही है, हमारे ही लगाये हुए हैं और वो बिना पूछे कभी भी घुस जाते हैं। हमारी विधाानसभा में; वाई. ब्लॉक में, मंगोलपुरी में भी तोड़-फोड़ की उन्होंने, कई झुग्गियां तोड़ीं और अभी सुल्तानपुरी में बहुत बुरे हाल हैं। मंदिर ही इतने तोड़ दिए इन्होंने, वहां पर अब लोग कह रहे हैं कि झाड़ू वालों को वोट नहीं देंगे। इतनरा बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने वहां पर। हम लोगों को समझा-समझा कर परेशान है कि यह तो एक षड्यंत्र है और इसमें सरकार का कोई वो नहीं है यह अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है मैं एक और बात की तरफ आपका धयान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी विधाान सभा क्षेत्र में पानी की बड़ी तगड़ी समस्या चल रही है। पता नहीं हैदरपुर जो प्लांट है, वहां से पानी का स्तर कर दिया या क्या है, रोज के रोज लोग परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत बुरा हाल है। आपसे नम्र निवेदन है कि इस पर थोड़ा धयान दें और उस एसडीएम को एक नोटिसजारी कर दें। आपसे निवेदन है आप बता दें उसको कि आगे से कभी भी विधाान सभा में कोई प्रॉब्लम आती है तो एमएलए को इन्वॉल्व करे। पूछे कि वहां पर यह प्रॉब्लम है, क्या यह वाकई में है या नहीं है। धान्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : 11वां श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : धान्यवाद अध्यक्ष महोदय।

महोदय, एक बार पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं सदन में, मैं दोबारा से बात रखना चाहता हूं। यहां पर जिक्र एमसीडी का कई बार हो चुका है। मेरी विधाान सभा में एक पुल बनाया गया था 'डाबरी पालन वाला' और उस पर अनाधिाकृत कब्जा एमसीडी के माधयम से हो रखा है और उस अनाधिाकृत कब्जे के ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई एमसीडी, मैं कमिश्नर से मिला, डीसी से मिला, यहां तक कि वहां से पार्षदों से मैंने भी बोला उसक बावजूद भी....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आदर्श जी, एक सेकेंड। आपने सीवर लाइन का लिख कर दिया हुआ है।

श्री आदर्श शास्त्री : कौन सा?

अध्यक्ष महोदय : सीवर लाइन।

श्री आदर्श शास्त्री : मैं माफी चाहूंगा, मुझे मालूम नहीं था। मेरे पास उसकी कॉपी नहीं आयी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सीवर लाइन की कॉपी है।

श्री आदर्श शास्त्री : ठीक है, तो सीवर लाइन वाली समस्या है, मैं आपके माधयम से बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां दिल्ली जल बोर्ड लगभग 87 करोड़ रूपये से 73 किलोमीटर की सीवर लाइन डाल रही है। यह पूरा प्रोजेक्ट जुलाई, 2017 यानि कि अब से तीन महीने बाद में समाप्त होना था। इस 73 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के बदले में उन्होंने अभी तक केवल 23 किलोमीटर की सीवर डाली है। जुलाई, 2017 में पूरा होना है और अभी तक 23 किलोमीटर किया है। लगभग 50 किलोमीटर अभी बाकी है। पहला सवाल तो यह है कि जुलाई की समय सीमा तो नहीं वो लोग मिला पायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं आपके माधयम से कि जल बोर्ड इस काम को कब तक पूरा करने का अनुमान लगा रही है, पहली बात और दूसरी बात, जहां पर यह 23 किलोमीटर ये लोग कर रहे हैं काम, जो अभी 50 किलोमीटर शुरू नहीं किया, जो 23 कर रहे है। उस 23 किलोमीटर में भी कम से कम जो गली वगैरह खोद रखी हैं, उन गलियों को भरकर कम से कम उस 23 किलोमीटर में जल बोर्ड सीवर चालू कर दे। यह मेरा आग्रह है आपके माधयम से जल बोर्ड को कि यह आदेश जारी किया जाये। बहुत-बहुत धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी समस्या आप उठाना चाहते हैं तो उठा दें।

श्री आदर्श शास्त्री : जी।

अध्यक्ष महोदय : जो अभी बोल रहे थे।

श्री आदर्श शास्त्री : जी।

अध्यक्ष महोदय : बोल दीजिए।

श्री आदर्श शास्त्री : जी, मैं वो भी बात देता हूं, एमसीडी की, जो मैं बता रहा था आपको।

अध्यक्ष महोदय, इसमें समस्या यह है कि मेरे यहां जो पुल बनाया गया, नाला ढका गया, उसके ऊपर पुल बनाया गया। यह जो नाला है यह एमसीडी की देख-रेख में आता है और पिछले डेढ़ वर्षो से मैं एमसीडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, लगातार मेयर, स्टेंडिंग कमेटी सब के पास जा रहा हूं, सबसे मिल रहा हूं, दिल्ली पुलिस से भी मिल चुका और उसके बावजूद भी वहां पर यह अनाधिाकृत कब्जा है, इसको खाली नहीं कराया जा रहा है। वहां पर रेहड़ी-पटरी वाले खराब और पुरानी गाड़ी छोड़ देते हैं। मैं अगर पूछता हूं तो यह बताया जाता है कि रोज का रेहड़ी वाला जो है 60 रूपये एमसीडी के अधिाकारियों को, एमसीडी के पार्षदों को देता है और तीस रूपया दिल्ली पुलिस को जाता है। लगभग तीन हजार ऐसी रेहड़ियां इसपटरी पर लगी हैं। इसके माधयम से आप समझ सकते हैं कि वहां पर यातायात के लिए यह सबसे बड़ी सड़क है ढाई किलोमीटर की, यह सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। रेहड़ी-पटरी वालों का कब्जा है। एमसीडी इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। मेरा आपके माधयम से यह अनुरोधा है कि एमसीडी को बुलाया जाये और पूछा जोय कि डेढ़ साल में मिनट्स में उनके पास नोट है, कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बहुत-बहुत धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध न्यवाद करना चाहता हूं और एक बहुत गंभीर विषय मेरी विधाान सभा का है, मैं आज वो उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, गांधी नगर विधान सभा में एसडीएम कार्यालय हुआ करता था। आज से कुछ साल पहले वो एसडीएम कार्यालय नंद नगरी ट्रांसफर कर दिया गया। आज मेरी विधान सभा में यदि किसी व्यक्ति को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, किसी को मैरिज सर्टिफिकेट लेना हो तो कम से कम 10 से 1 2 किलोमीटर वो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सीलमपुर मेरी विध ान सभा में आता है और मेरी विधान सभा के अंदर सीलमपुर और उसके बगल के इलाके का एसडीएम कार्यालय खोल दिया गया। मैंने कई बार और जो उस समय वहां के मंत्री थे, मुख्यमंत्री साहिबा थी, उन्होंने अपनी हठ और जिद्द के कारण वहां पर एसडीएम ऑफिस करा दिया गया। एक बहुत बड़ा माफिया है जो नंद नगरी में इस तरीके का काम कर रहा है। हमारे यहां केसारे लोग परेशान हैं। चार लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं सर, वहां 1 2 बजे तक पहुंचते हैं। कोई डायरेक्ट कन्वेंस नहीं है, कोई आदमी वहां पहुंच नहीं सकता। 12 बजे तक लाइन में लगेगा, उसके बाद काउंटर पर कह देंगे कि यह कागज की कमी है, आप कल आ जाइयेगा

मेरा आपसे अनुरोधा है कि हमारा ये एक मानवीय पक्ष है, लोगों के मन में बहुत पीड़ा है। 12 किलोमीटर लोग वहां से जा रहे हैं या तो जो सीलमपुर के अंदर एसडीएम ऑफिस है, उसको तुरंत शिर्टि कराया जाए नंद नगरी और उसको खाली करा दिया जाये और वहां गांधी नगर का ऑफिस बना दिया जाये और अगर वो नहीं शिफ्ट होता है। (240) तो एसडीएम जहां पर पहले एसडीएम गांधीनगर हुआ करता था, वहां पर जगह खाली पड़ी है, वहां पर एसडीएम आफिस गांधी नगर हुआ करता था, वहां पर जगह खाली पड़ी है, वहां पर एसडीएम आफिस गांधी नगर का शुरू करा दिया जाए।

सर, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि सरकार हमारी है, आप सब लोग हमारे हैं पब्लिक हम से रोज कहती है, ''बताओ बैठना कहां पर है?'' ये लेकिन कहीं न कहीं मन में पीड़ा है, इसलिए नहीं बैठ पाते हैं। सर, लेकिन अगर ये मामला ज्यादा दिन खिंचा तो निश्चय मुझे भी सारे लोगों के साथ धारना या भूख हड़ताल पर बैठना पड़गा। इसके लिए मैं धयान दिलाना चाहता हूं आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया।

...;(व्यवधाान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं। ये देखिये, मैंने 12 प्रश्न ले लिये। नहीं, अब मेरे पास और भी रिक्वेस्ट आई हुई हैं लेकिन नियम के अनुसार जो लिख के भेजे गये हैं, मैं उन्हें को टेकअप कर सकता हूं। नहीं, जो मेरे पास नहीं आये हैं, उनको नहीं प्लीज। कल के लिए आप लिखकर दे दीजिये। नहीं, ठीक है। वो देखिये, अजय दत्त जी, आपकी स्लिप मेरे पास है। मेरी बात सुनिये। मैं नियम के अनुसार जो....

श्री अजय दत्त : नहीं आज रोज मर्डर हो रहे हैं करीब महीने में सात मर्डर हो गये। रोज चाकूबाजी हो रही है। पहले भी आपके संज्ञान में लाया था मैं ये बात यहां पर।

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी, नहीं मेरी बात समझिये देखिये कल आपने मेरे संज्ञान में लाया मैंने आपके सामने कमिश्नर आफ पुलिस को फोन किया, नहीं एक बात सुनिये मेरी बात पुरी उनका उसी वक्त रिप्लाई आया उस वक्त सीट पर नहीं थे बाद मेमं उनका फोन आया, आपके सामने ही फोन आ गया मैंने उनको बोला, एक दिन तो इंतजार करें और मुझे लिख के दे दें मेरे आफिस में।

....(व्यवधान)

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी इतनी जिद नहीं की आपसे, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर हैं ये अंबेडकर नगर में करीबन 6-7 महीनों से त्राहि-त्राहि मची हुई है और 6 महीने के अंदर 18 मर्डर हो चुके हैं और जनवरी से अब तक 7 से 8 मर्डर हो चुके हैं, हरेक हफ्ते कम से कम एक मर्डर है। गोलियां चलती हैं, चाकूबाजी होती है, लोगों को लूट लिया जाता है, उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती और इसके बारे में मै।ने डीसीपी पुलिस को कई बार कहा, वहां के थाने के लोगों को कहा, उनसे बिल्कुल भी कानून और व्यवस्था को चला नहीं जा रहा है। वहां पर नशे के व्यापार चलाये जा रहे हैं। उसके बारे में भी मैंने लिख कर दिया उनको, ऑन रिकार्ड कराया। वहां पर सट्टाचलाया जा रहा है, वहां पर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, कोई नहीं पता। अगर आज जनता हमसे पूछती है कि भई, हमारे आम आदमी पार्टी को वोट देने के बाद कानून व्यवस्था को क्या हुआ? हम उनको सीधाा कहते हैं, ''पुलिस हमारे हाथ में नहीं है।'' हमें पता है कि पुलिस सेंटर के पास है। हमें पता है कि पुलिस बीजेपी के लोगों के पास है। हमें पता है कि ये मोदी की पुलिस है। अगर पूरे देश में मोदी जी दिल्ली, जिसको राजधाानी कहते हैं, उसमें कानून व्यवस्था को नहीं बना सकते तो ये पूरे देश में क्या करेंगे? मेरा ये प्रश्न बीजेपी से है, मेरा प्रश्न ये मोदी जी से है कि जिसे राजधाानी कहा जाता है वहां पर 7-7 हत्याएं हो रही हैं, उसके बारे में क्या काम किया जाए? मैं आपके माधयम से यह बात रखना चाहता हूं कि आप पुलिस कमिश्नर को बुलाइये और उन्हें कहये कि वहां पर कार्रवाई की जाए और डीसीपी रिस्पांड करे,

एसीपी रिस्पांड करे और वहां पर लोगों की हत्या न हो क्योंकि वहां ` लोग अब एक तरीके के भय के माहौल में जी रहे हैं। हमें कहा जा रहा है, ''भइया, आप बाहर न निकलो। नहीं तो गोली लग जाएगी।''

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी आप कंक्ल्यूड करिये प्लीज।

श्री अजय दत्त : मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि उन्हें बुलाकर यह कहा जाए, एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट करा हूं मैं आपके माधयम, मैं राजनाथ जी को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि दिल्ली राजधाानी को आप करप्शन फ्री तो बना नहीं पाए कम से कम पुलिस से व्यवस्था तो बना दीजिये। हमें सुरक्षित रहने का माहौल तो बना दीजिये, इतना ही मैं कहना चाहता था। ध ान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धान्यवाद, श्री मनीष सिसोदिया जी की ओर से श्री सत्येंद्र जैन जी कार्यसूची के बिंदु....

....(व्यवधान)

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी एक बार ये पूरा करने दो। श्री मनीष सिसोदिया जी की ओरसे श्री सत्येंद्र जैन जी कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 2 में दर्शाये गये दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री सत्येंद्र जैन (स्वास्थ्य मंत्री) **:** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री जी की ओर से आपकी अनुमति से अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का वित्त वर्ष 2014-15 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन[1] तथा दिल्ली सहकारी आवास

वित्त निगम लिमिटेड का वित्त वर्ष 15-16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की हिंदी तथा अंग्रेगजी प्रतिया[2] सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : अब बताइये क्या कह रहे हैं आप?

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, चूंकि पूरी दिल्ली के अंदर जितने विधाायक हैं, मेरा ख्याल है कि तीन छोड़कर के सबके पास ही मुसीबतें यह हैं कि एमसीडी को जो हमने पैसे विधाायक फंड से दिये हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, फंड पर वो बैठ गये हैं, न तो वो काम कर रहे हैं न फंड वापस कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी अभी एमसीडी की बात हुई है, मैं इस पर बात....

श्री सोमनाथ भारती : ये सबकी मुसीबतें हैं। सदन के अंदर बैठे हर विधाायक के मन में ये पीड़ा है कि एमसीडी का चुनाव आने वाला है और ये इतना जितनी जनता है, उनके मन में गुस्सा है। हमारे मन में पीड़ा है और ये इतना जितनी जनता है, उनके मन में गुस्सा है। हमारे मन में पीड़ा है और गुस्सा भी है क्योंकि जो हमारा 4 करोड़ का फंड है, उसमें से अधिाकांश फंड हमने एमसीडी को दिया था और उस सारे फंड के ऊपर वो बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं न फंड वापस कर रहे हैं। मैं आपके माधयम से सदन को गुजारिश करता हूं कि आप सब मिलकर के इस मुद्दे को बड़ा

1. पुस्तकालय में संदर्भ सं. .....पर उपलब्धा।
2. पुस्तकायल में संदर्भ सं. .....पर उपलब्धा।

बनायें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव के अंदर हमको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : धान्यवाद।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, एमसीडी के बारे में एक बात तो मुझे कहनी है, वो सबसे जुड़ी हुई है। हमारी एक कालोनी में जहां 33 परसेंट से ज्यादा एससी रहते हैं उसके लिए एससीएसटी डिपार्टमेंट से बजट मिलता है, गोलियां, नालयां आदि बनाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि उसमें एक शर्त है कि वहां काम केवल फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन डिपार्टमेंट से ही करवाना पड़ेगा या डीएसआईडीसी से, तो जब हमने वहां से फंड ले लिया और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से हमने बनवा लिया, वहां पर टेंडर हो गया, काम शुरू हुआ तो एमसीडी ने काम को रोक दिया। सारे विधाायकों को ये समस्या आ रही है। एमसीडी कह रही है कि हम अपने यहां कोई भी किसी दूसरी एजेंसी को काम नहीं करने देंगे। तो जोए ससीएसटी पुंड जहां लगनाथा, वहां एमसीडी परमिशन नहीं दे रही है, एनओसी नहीं दे रही है। सारे केस ोर काम रूक गये हैं। कामत आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

अध्यक्ष जी, एमसीडी के कमिश्नर को इस संदर्भ में निर्देश दिये जाएं कि एससीएसटी के फंड का पूरा का पूरा काम पूरी दिल्ली का रूक गया है। उनको निर्देश दिये जाएं कि वो काम हो सकें शुक्रिया।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एमसीडी पर चर्चा के लिए मैं 5 बजे का समय निध ार्रित कर रहा हूं। आप अपने नाम चीफ व्हिप को दे दें। बजट पर चर्चा के लिए।

....(व्यवधान)

श्री संजीव झा : ये ऐसा मुद्दा है, देश से जुड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं छोटी सी बात रखकर इसे खत्म कर दूंगा। मैं अपने साथियों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रामकृष्ण ग्रेवाल जी जिन्होंने वन रेंक वन पेंशन में अपनी शहादत दी थी, दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की थी कि एक करोड़ रूपये उनको दिये जाएंगे, लेकिन माननीय एलजी साहब ने उस फाईल को वापस कर दिया है। मुझे लगता है कि चूंकि यह बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, और सदन के संज्ञान में ये बातें आनी चाहिए कि चूंकि दिल्ली सरकार के एक करोड़ की घोषणा के बाद अगर ये फाईल वापस आ जाती है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये उनकी शहादत का अपमान है और मुझे ऐसा लगता है कि....

अध्यक्ष महोदय : झा साहब, बैठिये प्लीज। नहीं, अभी आपने बात कह दी, बाप हो गई। आपकी आ गई। अब बैठिये, इस पर चर्चा नहीं प्लीज। इसकी गंभीरता को समझिये, नहीं आप बैठिये जरा, बैठिये प्लीज। सुश्री अलका लांबा जी। (250)

बजट 2017-18 पर चर्चा

सुश्री अलका लांबा : अध्यक्ष जी, धान्यवाद। आपने कल जो दिल्ली के वित्तमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया, उस पर चर्चा का मौका दिया है।

अध्यक्ष जी, ये तीसरा बजट है दिल्ली सरकार का और तीनों बार दिल्ली सरकार ने बजट के प्रति नजरिये को बदला है। पिछली बार हमेशा होता था कि जनता पर इतना खर्च किया जा रहा है। वित्तमंत्री ने अपनी सोच को बदला

और पूरी सोच हाऊस की भी दबली कि वो खर्च नहीं, वो निवेश हो रहा है। खर्चा वो होता है जो आपने खर्च कर दिया, अब आपको उससे वापस कुछ नहीं मिलेगा लेकिन सरकार ने कहा, ''ये खर्च नहीं, हम ज नता पर निवेश कर रहे हैं।'' और ये जनता पर जब पैसा खर्च किया जाता है तो उसका फायदा राज्य को दिल्ली को जरूर मिलता है तो मैं इसकी तारीफ करती हूं और कल फिर बजट को एक नये नजरिये से पेश किया गया। हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट जो है, एक आउट कम बजट होगा अब हमने सबने समझना चाहा, ये आउट कम बजट क्या है। अध्यक्ष जी, हम भी यही सोचते थे कि हमारे विधाायकों को तीन से चार करोड़ रूपया एमएलए लैड फंड मिलता है और विधाायक बड़े गर्व से कहते थे कि हमने अपना सारा विकास का फंड पूरा इस बार सौ प्रतिशत जनता में खर्च कर दिया। हम भी वहीं पर संतुष्ट हो जाते थे लेकिन कल जो दिल्ली के वित्तमंत्री ने कहा कि नहीं, हमें इतने पर ही संतुष्ट नहीं होना है। अब आउट कम बजट पर चर्चा होगी। अब आउट कम बजट क्या है, उन्होंने उदाहरण दिया कि हमने एक अस्पताल में दस करोड़ रूपया खर्च करके एक मशीन खरीदी है। अब वो मशीन खरीद कर हमने अपना दस करोड़ का जो बजट था, मशीनों पर सरकारी अस्पतालों में खर्च कर दिया। अब देखना ये है कि क्या वो मशीनों से फायदा आम गरीब जनता को जो मुफ्त ईलाज, मुफ्त जांच की बात है, उसका उठाया जा रहा है या उन दस करोड़ की मशीनों को खरीदकर सिर्फ ये दिखाया गया है कि बजट सौ प्रतिशत इस्तेमाल हो गया और मशीनों को तालों में बंद कर दिया गया।यही हम लोगों ने भी अपना नजरिया बदला और एमएलए लैड फंड में हमने भी देखा अपना फंड सड़कों में, सीवर में, नाली पर लगाया लेकिन लगा तो सही, क्या उसका फायदा या नई पानी की लाईन तो डल गई लेकिन

क्या उस नई पानी की लाईन को डलने के बाद घर-घर में पीने का पानी स्वच्छ पानी जो दिल्ली सरकार मुफ्त दे रही है, वो भी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। मुझे लगता है, ये नजरिया अब बदला और मुझे लगता है पूरे देश की सरकारों को इस आउट कम बजट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। खाली ये मकसद नहीं है कि सौ करोड़ रूपया आपने किसी बजट के लिये दिया और वो पूरा आपने उसको खर्च कर दिया लेकिन उसका फायदा अगर लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा उसको नजरिये को बदलने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी महिला आयोग, बाल आयोग पहले से ही दो आयोग दिल्ली और देश में चल रहे हैं पर पहली सरकार है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग के बारे में भी सोचा है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से वरिष्ठ नागरिक अपनी पेंशन को लेकर, अपनी रिटायरमेंट के बाद की पेंशन को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर क्योंकि हमने देखा कि बहुत से अपराधा जो घर में अगर बड़े बुजुर्ग अकेले हैं और सुरक्षा के अभाव में हैं तो वे भी अपराधा का शिकार होते हैं। मैं दिल्ली सरकार की सराहना करती हूं कि इस बजट में उन्होंने तीसरा आयोग; 'वरिष्ठ नागरिक आयोग' जो है, उसका गठन करके हमारे वरिष्ठ नागरिकों के हक, अधिाकारों की और उनकी सुरक्षा की बात को रखने का काम किया है।

अध्यक्ष जी, कल 8 मार्च था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबने मनाया। सब लोगों ने महिलाओं को बहुत बड़े-बड़े वायदे किये, महिलाओं को दुर्गा, सरस्वती से पूजा लेकिन किया कितने लोगों ने? मुझे खुशी है कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने कल दिल्ली महिला आयोग का तीन गुणा बजट बढ़ाते हुए, बीस करोड़

रूपया दिल्ली महिला आयोग को दिया है। मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि जो महिला अपने हक, अधिकार और अपनी सुरक्षा की बात, मांग को लेकर महिला अ ायोग के दफ्तर जाती थी, महिला आयोग के दफ्तरों में बहुत सी कमियों को देखा भी जाता रहा, लेकिन उम्मीद है कि ये 20 करोड़ का जो फंड दिल्ली महिला आयोग को दिया गया, वो एक महिला की सुरक्षा, उसके हक, अधिकारों की उसकी लड़ाई लड़ने में दिल्ली महिला आयोग को मदद करेगा।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा एक और बड़ी बात है, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपना बजट पेश किया और बजट पेश करने के बाद अभी पता लगा कि 85 रूपये सबसे ज्यादा अगर गैस की कीमत कभी बढ़ी इस देश में, वो इस बार बढ़ी मोदी सरकार के तहत बढ़ी। सीधाा सिलेंडर के दाम जो हें, वो 85 रूपये कर दिये गये। ये महंगाई का नारा लेकर आये थे क बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार ने भी एक और मार मारी, 85 रूपये एकदम से महंगा कर दिया। वहीं कल दिल्ली के वित्तमंत्री जब बजट पेश कर रहे थे, जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने जो पेंशनें थी, जो गरीबों को, बुजुर्ग को, विकलांग और विधावा महिलाओं को मिलती है, उनकी पेंशन एक झटके में ही एक हजार रूपया बढ़ा दी। तो ये दो सरकारें हैं जो महंगाई का, खोखले नारे देकर सिलेंडर के दाम बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ इस महंगाई में राहत देने का काम दिल्ली की सरकार ने किया और पेंशनों में जो है, वो एक हजार रूपये की राहत लाई।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के जो कांग्रेस के सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और अभी प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने आज अखबारों में कहा कि आम आदमी की सरकार को गवर्नेंस करना नहीं आता और गर्वनेंस

उनसे सीखिये। अध्यक्ष जी, उनकी गवर्नेंस का एक उदाहरण इस बजट के माध यम से भी आपके सामने मैं रख देती हूं। इनी गवर्नेंस ये थी कि 2012-13, 2013-14 में जब दिल्ली में कांग्रेस की, इन्हीं की सरकार थी, जो गवर्नेंस हमें सिखाने की बात करते हैं, इनके टाईम पर जो ग्रोथ रेट था, एग्रीकल्चर में था वो - माइनस 1 3.7 था और जब अमा आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है 2014-15 के आंकड़े बताते हैं कि जो माइनस 13 था वो प्लस 20 प्रतिशत पर पहुंच गया है। अध्यक्ष जी, ये पीआरएस की रिपोर्ट को मैं मेंशन कर रही हूं। ये जो हमें गवर्नेंस सिखाने चले हैं, जिनकी 15 साल दिल्ली में सरकार थी जिनके अध्यक्ष आज बहुत बड़े प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। इन्हें बताना चाहती हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में इनके समय पर जो ग्रोथ थी वो 14 प्रतिशत थी 2012-13 में और वहीं हमारी सरकार में जो हमीर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है 14 से 20 प्रतिशत पर आज है वहीं पर सर्विस सैक्टरमें जो कांग्रेस की सरकार में जो ग्रोथ थी, सर्विस सैक्टर में वो 5.2 थी और आज आदमी पार्टी सरीकार में 5.2 से 7.5 हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता हमें गवर्नेंस आपसे सीखने की कोई भी जरूरत है और वहीं बीजेपी के जो भाजपा के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने पिछले दो सालों में कोई काम नहीं किया तो जब उनसे पूछा गया कौन सा काम नहीं किया, तो उनका इशारा यही था ये तो बहुत बड़ा जो है, वो काम नहीं बताते हैं कि कौन से काम नहीं किये। शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में हम लोगों ने 17 राज्यों के आंकड़े पीआरएस की रिपोर्ट बताती है। अध्यक्ष जी,

17 राज्यों में जिस पर भाजपा शासित सबसे ज्यादा राज्य हैं, अगर उन राज्यों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने शिक्षा पर खर्च किया है तो वो दिल्ली की आमआदमी पार्टी सरकार के 17 राज्यों में कुल बजट का 22 प्रतिशत जो

है, वो आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। ये लोग जो कहते हैं काम नहीं किया, इन्हें ये भी बताना चाहूंगी कि हेल्थ सैक्टर में 17 राज्यों की जब तुलना करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा राज्य भाजपा शासित हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा 1 1.2 प्रतिशत जो है, कुल बजट का सबसे ज्यादा अगर कोई खर्च कर रहा है स्वास्थ्य के ऊपर, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है।

अध्यक्ष जी मैं यही कहूंगी किसी भी राज्य की तरक्की और उन्नति, वो कितना शिक्षित राज्य है, कितना स्वास्थ्य राज्य है, इस पर निर्भर करता है, अगर वो राज्य दिल्ली जैसा शिक्षित और स्वस्थ राज्य है तो यकीनन वो देश की तरक्की और उन्नति में अपना बहुत बड़ा उसका एक रोल रहता है लेकिन दु:ख की बात ये है कि नगर निगम को भी भरपूर पैसा पिछले बजट से भी ज्यादा दिया है लेकिन दु:ख की बात ये है कि सारा पैसा जो है, वो आज भ्रष्टाचार में जा रहा है। इनका दर्द क्या है कि आम आदमी पार्टी के पास इतना पैसा आ कैसे रहा है। पहला बजट हमारा जो हुआ करता था, वो 38 हजार करोड़ के करीब था पिर 46 हजार करोड़ और इस बार का जो बजट पेश किया गया, वो 48 हजार करोड़ का पेश किया गया। इनको भी समझ नहीं आ रही है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त पानी, आधो दामों पर बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त, एक हजार रूपया पेंशन बढ़ाने के बावजूद भी, इतना खर्च करने के बाद भी आम आदमी पार्टी सरकार के पास इतना पैसा क्यों हो रहा हे! ये पैसा कहां से आ रहा है, इसमें भी इन्हें बहुत बड़ा घोटाला दिख रहा है क्योंकि ये पैसाजनता भी पूछ रही है कि ये फायदा हमें आज तक क्यों नहीं मिला जो हमें एक हजार पेंशन आम आदमी पार्टी सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने एक हजार बढ़ा दिया, वो 15 सालों में शीला दीक्षित सरकार क्यों

नहीं बढ़ा पाई। एक साल तक राष्ट्रपति शासन में बीजेपी ने भी राज किया है, उस समय क्यों नहीं बढ़ पाया? आज आम आदमी के पास पैसा कहां से आ रहा है सरकार के पास? सर, उसका एक ही जवाब है कि जो जनता टैक्स देती है, वो नेताओं की जेब में, दलाली में नहीं जा रहा है, जनता का पैसा घूम के जनता की जेब में जा रहा है। ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है।

अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली सरकार को दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसौदिया जी को जिस बदले नजरिये से इन्होंने बजट को पेश किया है, मैं उनकी तारीफ करती हूं लेकिन एक छोटी सी उम्मीद मैं इस बजट में जरूर करती हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि मेरे यहां पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और यमुना पुश्ता पूरा पड़ता है, बहुत से लोग उमसें जो है औरब च्चे भी आप देखेंगे, नशे का शिकार हैं, बजट में सरकार ने कहा है कि हम लोग पांच नये 'नशा मुक्ति केंद्र' खोलने जा रहे हैं और प्रति नशा म मुक्ति केंद्र में पांच बिस्तर होंगे यानि कि 25 सिर्फ 25 लोग इस नशामुक्ति केंद्र का एक समय पर फायदा उठा पायेंगे। मेरा वित्तमंत्री जी से निवेदन है कि दिल्ली में जो नशे की लत में है, उन्हें इस तरह के नशामुक्ति केंद्रों की बहुत जरूरत है। कृपया इसकी संख्या को बढ़ाया जाये और इसमें अगर बिस्तरों की संख्या को भी इन केंद्रों में बढ़ाया जा सकता हो तो अध्यक्ष जी, मेरा वित्तमंत्री से निवेदन है मेरा ये निवेदन स्वीकार करें। धान्यवाद। जयहिंद। (300)

अध्यक्ष महोदय, : धान्यवाद, श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : धान्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बहुत ही खूबसूरत मैं कहूंगा, बजट कल पेश हुआ है ऐसा जो शायद सबाके साथ में लेकर चलने

वाला बजट जिसे कहते हैं। एक बहुत अच्छे विजन के साथ में, विजन एक अच्छी सोच की वजह से आता है और अच्छी सोच एक अच्दी नीयत की वजह से आती है, ये तो साफ है। क्योंकि जब तक कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई थी, उससे पहले जितने भी बजट बनते थे और प्रदेशों में बनते हैं या केंद्र में भी मैंने देखा, बनते हैं, उनमें विजन कहीं नहीं है। किसी भी प्रकार से कि कैसे पूरे के पूरे समाज को उठाकर और उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए, इसके बारे में कोई सोच नहीं है। कैसे देश को आप 21वीं सदी से 22वीं सदी में कल को ले जाओगे, देश को सुपर पॉवर बनाओगे, क्या सिर्फ हथियारों से बनाओगे या बुलट ट्रेन से बनाओगे या देश की जनता को भी आगे बढ़ाओगे, इस तरीके का विजन और किसी बजट में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार में ये विजन आता है वो विजन एक बहुत अच्छी सोच की वजह से आता है और एक बहुत अच्छी नीयत की वजह से आता है। ये तो साफ हो गया और अजीब सा लगता है ये कहते हुए कि क्या केंद्र में भी किसी के पास इतनी अच्छी नीयत नहीं है!

पहली चीज जो बजट में एकदम से जो स्ट्राइक करती है, वो करती है बजट को सिम्पलीफाई करने के एक आइडिया को। क्यों जरूरत पड़ती है बजट को सिम्पलीफाई करने की? क्योंकि आंकड़े हर एक आदमी को समझ में नहीं आते। ये jargon ये definitions, ये बड़े-बड़े शब्द जो आज आ जाते हैं, वो आम आदमी को घुमाकर रख देते हैं। उसका इंट्रेस्ट खत्म हो जाता है बजट में से। जो हुआ, हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखी जाएगी। पर बहुत जरूरी है कि आम आदमी के अंदर बजट के प्रति या उसके लिए इस बजट के अंदर क्या है, वो इसके लिए जिज्ञासु रहे और वो तभी रह पाएगा जब वो उसको समझ पाएगा। उसके लिए बजलट को सिम्पलीफाई करना बहुत जरूरी

है। बजट को प्लेंड अनप्लेंड से हटाकर उसको डिफाइन करना कि ये पैसा आया और यहां पर खर्च करने का प्लान बनाया है, इसको बजट की तरह से दिखाने में लोगों को सिम्पलीफाई करने से समझ में आता है। लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो बहुत दूर तक चल पाएंगे। नपहीं तो कुछ साल बाद फिर टंगड़ी लग जाती है, औरों को भी, तीन ही रह जाते हैं। इसके बाद में सिम्पलीफाई किया पर अपने ऊपर ही एक चेक बिठाने के लिए 'आउट कम बजट' जैसी चीज लेकर आए, देश में पहली बार! सर, इसके लिए तो बहुत ज्यादास सराहनीय ये बात है कि हमारे उपमुख्यमंत्री साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मनीष सिसौदिया जी की कि अपने ऊपर ही चेक लगाया कि ये जो पैसा खर्च कर रही है, सरकार इससे किसको, कितनों को और कितना फायदा पहुंचव रहा है, ये बहुत जरूरी है। वरना हम तो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। सर, आप भी ईस्ट दिल्ली में ही रहते हैं। याद होगा कॉमन वैल्थ गेम्स के टाइम पे एक फुटओवर ब्रिज बना था, जो पुश्ते की तरफ से शुरू होता था और डिवाइडर पर उतर जाता था। वो बाद में अभी तुड़वाया भी गया है। वो 'आउट कम बजट' में तो वो बिल्कुल जीरो आता। वो 3 महीने में चैक करवा लो, 6 महीने में करवा लों एक भी आदमी उस पे आज तक नहीं चढ़ा, सिर्फ चढ़े तो पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्टर लगाने वाले लोग चढ़े, उसके अलावा कोई नहीं चढ़ा। ऐसे खर्चे ना हों, वैसी फिजुलखर्ची ना हो। सोच समझकर टारगेट ओरियेंटिड ऑप्टीमम रिटर्नस, इंवेस्टमेंट किया है तो रिटर्नस की बात है। रिटर्न है जनता का सेटिसफेकशन ही एक रिटर्न है। उस रिटर्न को देखते हुए एक बजट बनाया गया जिसको 'आउट कम बजट' का नाम भी दिया गया। पहला 'आउट कम बजट' है।

सर, एक हैट्रिक की गई कि तीसरे साल लगातार टैक्स लैस बजट दिया गया। किसी के ऊपर टैक्स थोपा नहीं गया बल्कि कई जगह पर अैक्स कम किया गया। सबका सपना होता सर एक अच्छा सा घर बना लें, वो घर बनाते हुए जो भी, उसमें कभी मार्बल लगता है, तो कभी ग्रेनाईट लगता है, तो कभी सेंडस्टोन लगता है, कभी कुछ लगता है, इन सब पे दाम कम होते हैं। ये कम्पीटेंटिव जमाना है, आसपास के स्टेट्स से कम्पीटीशन ना हो जाए। यहां के व्यापारी वर्ग को भी फायदा पहुंचे, यहां के व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचेगा, वो अपने आप दाम सस्ता करेगा तो जनता को फायदा पहुंचेगा। इस तरीके से कोम्पीटीशन लाया गया। उसका टैक्स कम किया गया, कई सारी चीजों के ऊपर और बढ़ाया कहीं नहीं गया। ये इकलौता बजट है। ये जो बार-बार, बार-बार कहकर और टैक्स बढ़ाया जाता है। अलका जी ने कहा था बीजेपी का नारा था 'बहुत हुई महंगाई की मार,अबकी बार मोदी सरकार।' पर हर चीज पर बार-बार टैक्स बढ़ाकर, बार-बार दाम बढ़ाकर, चाहे वो पेट्रोल के हों, चाहे डीजल के हों, हर 15 दिन में बढ़ जाते हैं। नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है, कहीं कमी रह गई है और अभी तो गैस के ऊपर, जब सरकार बनी थी केंद्र में, तो 440 रूपये का सिलेंडर था आज 777 रूपये का है, ऑलमोस्ट दुगना होता चला जा रहा है। खैर! हम वापस आते हैं, अपने बजट पर आते हैं।

सर, कुछ चीजें तो बजट में ऑवियसली ऐसी चल रही हैं, चाहे हम स्कूलों की बात करें या मौहल्ला क्लिनिक की बात करें, उनके बारे में तो सर, दुनिया ही बात कर रही है। मैंने सोचा कि इसके बारे में, मैं क्या बात करूं? पूरी दुनिया ही चर्चा कर रही है। इस विषय पर चर्चा की हमारे इस सदन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत नहजीं है। उसकी क्योंकि जहां पर अमेरिका हमसे

प्रेरणा ले रहा है, हमारे तो देश के प्रधानमंत्री और जगह से प्रेरणा, पता नहीं कैसी लेकर आते हैं, पर ऐसी चीजें हमारे बजट के थ्रू हो रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री कर रहे हों कि दूसरे देश हमसे प्रेरणा ले रहे हैं और पहली बार देश का सर फख्र से ऊंचा उठ रहा है कि जहां पर देश को अब से पुरातत्व काल में पूरी की पूरी दनिया का लीडर माना जाता था, अब दुबारा से ऐसा लग रहा है कि हां, अच्छी नीयत के साथ काम करो तो हमारे देश में आज भी वो पोटैंशल है कि पूरी दुनिया का लीडर बन सकती है। तो मैं अपनी जो चर्चा है, उसको सर, थोड़ा सा स्कूलों से और हैल्थ से हटाना चाहूंगा कि जहां पर दुनिया की चर्चा कर रही है, वहां पर बहुत जरूरी नहीं है कि मैं भी उसके बारे में बोलूं और जहां पर देश चर्चा कर रहा हो कि 'बिजली हाफ, पानी माफ' जहां पर देश चर्चा कर रहा हो कि 8000 स्कूल्स में, 8000 नए कमरे बन गए हों या मौहल्ला क्लिनिक खुल गई हों, इतनी सारी चर्चा देश में हो रही है, सारे चैनलों पर हुई हैं जिस भी प्रदेश में हम लोग जाते हैं, वहां पर होती है तो कुछ और बातों पर चर्चा कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छी चीज हमारे बजट में डाली इस बार। कोई तीन सौ-सवा तीन सौ गांव हैं हमारे दिल्ली के अंदर। बहुत सारे उसमें से सर, अर्बन विलेजेज हैं, मैं अर्बन विलेजेज की ही बात करूंगा, रूरल विलेजेज की बात, जो विधाायक रूरल विलेजेज जिनके यहां क्षेत्र में हैं, वो कर लेंगे। लक्ष्मी नगर में शक्कर पुर एक गांव है ऐसे ही समस्त पुर जागीर है, पास में ही मनीष जी की भी एक कोंसटीट्यूंशी पड़ती है, उसमें पटपटगंज है, मंडावली है, ये पूरे बस गए हैं यहां पर अब खेतीबाड़ी नहीं होती है। तो ना तो ये गांव की कैटगिरी में आ पा रहे हैं और न ये शहर की कैटगिरी में आ रहे

हैं। पर सच बात ये है कि यही बेस बनाकर ईस्ट दिल्ली बसी है, शक्कर पुर गांव के आसपास बसनी शुरू हुई, खुरेजी के आसपास बसनी शुरू हुई, पटपटगंज के आसपास बसनी शुरू हुई, तभी जाकर बसी। पर ये बांव पिछड़े रह गए। बाकी जगह इन्फ्रास्ट्रक्चर आ गया। सर, यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं आ पाया। इनके ऊपर काम नहीं किया गया। कभी एक गली बना दी, कभी एक जगह सीवर डाल दिया, कभी पानी की पाईप लाईन डाल दी, पर कहीं पर भी कोई तालमेल नहीं बैठता। इसलिए एक जगीह का सीवर ठीक करवाओ तो दूसरे का जाम हो जाता है। दूसरे का करवाओ तो तीसरे का जाम हो जाता है। किसी तरीके से कोई भी प्लान तरीके से काम नहीं हो सकता। जैसा कि सोम दत्त भाई ने 280 में कहा था कि हमारे पास फंड बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड फंड होता हैं उसको हम बहुत ज्यादा जगह नहीं लगा पाते तो पहली बार ऐसा हआ कि 132 करोड़ से उठाकर 600 करोड़ गांव के लिए फंड बनाया गया। तकनीबदन 2 करोड़ रूपए हर गांव के पास आएगा। गांव के जो लोग हैं, जिनकी वजह से मैं कहूंगा कि ईस्ट दिल्ली बसी है। आज की तारीख में, उन लोगों को वापस से उस गांव को वो ही गौरव दिलवाने के लिए बहुत सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बहुत काम किया है। एमसीडी को बार-बार, बार-बार फंड दिया। बार-बार एमसीडी में राजनीति के चलते स्ट्राइक करवाई गई। दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील करने की कोशिश की गई। लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। हम फिर भी बिना किसी भेदभाव जिसे फैडरल कॉरपोरेटिज्म कहते हैं, हम उसके चलते हुए हमेशा एमसीडी का, दिल्ली सरकार ने साथ दिया। जब-जब जरूरत पड़ी, चाहे उन्होंने फंड कहीं पर भी सॉइफन ऑफ कर दिया हो, पहले भी कई बार एमसीडी के लिए मैंने कहा है कि

(310) आज तक मेरी समझ में नहीं आया ये पैसे का मिस-एप्रोप्रिएशन ज्यादा अच्छा करते हैं कि मिसयूज ज्यादा अच्छा करते हैं, आज तक समझ नहीं आ पाया। तो हमेशा उनको पैसा दिया, कभी उनसे ऋण वापस नहीं लिया, इन्ट्रेस्ट भी वापस नहीं लिया और इस बार भी बहु अच्छा पार्ट, सुबह 7500 हजार करोड़ रूपये का एमसीडी को जा रहा है। अभी सारे विधाायकों ने अपनी संवेदना आपके सामने व्यक्त की थी और कोई भी विधाायक ऐसा नहीं है कि जिसको डेढ़-दो करोड़ रूपये से कम एमसीडी में फंसा हुआ हो। तो 100 करोड़ रूपये के ऊपर तो एमसीडी में दिल्ली सरकार के विधाायकों का ही फंसा हुआ है, दिया हुआ मेरे पास भी हिसाब है। सर, ढाई करोड़ यपये दे रखा है मैंने। अभी तक काम नहीं हो रहा पर इन सब फंड के बावजूद भी अगर एमसीडी काम नहीं करती और बार-बार उनके नेता सिर्फ रोना और गाना करते हैं कि पैसा नहीं, पैसा नहीं है, तो ना जाने कहां से वो पैसा आता है एमसीडी के पास, जिससे वो इतनी करोड़ों रूपये की बेवसाईट बनवा रहे हैं और करोड़ों रूपये के विज्ञापन दे रहे हैं। आज की तारीख में कुछ ही मिनटों में हर रेडियो चैनल पर एमसीडी के विज्ञापन आते रहते हैं।

सर, इसके बाद मैं आना चाहूंगा कि एक और बहुत बड़ी चीज हुई हमारे पिछले साल जिसे कहते हैं ऑड-ईवन, पूरी दुनिया में ओड-इवन जहां सक्सेसफुल नहीं हुआ दिल्ली सरकार ने ओड-इवन दिल्ली के अंदर सक्सेसफुल किया। इसके लिये पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका और बहुत सारे देशों ने उसकी तारीफ की और इतनी सक्सेस के बाद ये भी डिसाईड हुआ कि दुबारा ओड-इवन आ सकता है, ट्रांसपोर्ट को ऑगमैंट करके, ट्रांसपोर्ट को बढ़ा के, जहां पे आज तक डीएमआरसी में 180 किलोमीटर की लाईन बिछी है, वहां प रये प्रावधाान देना कि 325 किलोमीटर तक ये पहुंच जाये। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धिा है।

जहां पर बसेज आलरेडी काफी हैं, उसमें तकरीबन 750 सौ और कलस्टर बसें जोड़ के हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑगमेंट कर हरे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर पॉल्युशन के चलते, सड़कों पर चलती हुई भीड़ के चलते ये ट्रैफिक कन्जैशन बढ़ने की वजह से अगर ओड-इवन लाना पड़ता है तो हम ओर सक्सेस फुल तरीके से उसको कर पायें, पब्लिक का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ पाये, ये सर एक विजन है। मैं बार-बार बात को विजन पर इसलिये ले कर आता हूं क्योंकि मैं विजन को हमेशा नीयत से जोड़ने की कोशिश करता हूं। जब तक नीयत नहीं होती अच्छी, तब तक अच्छा विजन नहीं हो सकता। सर, ये भी और विजन है पढ़ी-लिखी जनता होगी। जहां पर केंद्र सरकार ने कहा कि 2 करोड़ नये जॉब्स देंगे और आज तक दो लाख भी नहीं दिये। पिछले तीन साल तकरीबन हो गये, उसकी वजह है। और क्यों शिक्षा के ऊपर धयान न केंद्र देती, ना ओर राज्य सरकारें देतीं, उसकी भी एक वजह है। अगर लोग पढ़ जायंगे तो सवाल उठाएंगे। अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो ये बजट भी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे कि ये यार! तुमने किया क्या है? अगर समझने लगेंगे तो आपके जो घोटाले हैं, वो भी समझ में आयेंगे। तो कोशिश ये रही कि पढ़े ही ना। जनता अगर पढ़ जाएगी तो सवाल करेगी, जनता अगर पढ़ जाएगी तो नौकरी मांगेगी। वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि नौकरी दे पाओगे, रोजगार खड़ी कर पाओगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सोच नहीं है कि स्किल सैंटर होने चाहिये, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो बजट बना हरे हैं, ये जनता के हित में है और जनता अगर समझेगी तो सराहना करेगी इस बजट की। वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वजह से ये लोग पढ़ाई पर धयान नहीं देते और मैं सराहना करूंगा शिक्षा मंत्री जी की कि जिस प्रकार से शिक्षा के ऊपर उन्होंने धयान दिया। आठ हजार कमरे तकरीबन बनने को तैयार हैं, दस हजार

कमरों पर और काम होने वाला है। इसे भी विजन कहते हैं। इसे भी विजन कहते हैं कि अगले 20 साल तक दिल्ली के अंदर ओर स्कूलों की जरूरत नहीं पड़ी। जिस तरीके से ऑलमोस्ट 9 कॉल्ज शुरू कर दिये गये हैं, 20 कालेज कावादा था सर, पर जिस तेजी से नये कॉलेज बन रहे हैं, नई सीटें बढ़ रही हैं, आशा करता हूं और पूरा विश्वास है अभी तो दो ही साल हुए हैं, अगले 3 साल के अंदर इससे कहीं ज्यादा कॉलेजिज हम लोग खोल पाएंगे, ये विजन है। स्किल सैंटर विजन है, इन्क्यूबेशन सैंटर विजन है। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि काम नहीं करते, इसके बाद कहते हैं कि गवर्नेंस नहीं आती। अरे! हो सकता है कि आपके विकास का रथ बुलेट ट्रेन के पीछे चलता हो, आप की परिभाषा बुलेट ट्रेन से शुरू होती है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का एक टिकट किसी हवाई जहाज के टिकट से भी महंगा होने वाला है। उसमें सिर्फ आपके वो उद्योगपति दोस्त बैठेंगे, जो आपको वो हवाई यात्रा करवाते रहे, जो आपको इलैक्टशन लड़वाते रहे, इसलिये आपकी विकास की परिभाषा बुलेट ट्रेन से शुरू होती है। पर हमारे को सर, गलियों में घूमने की आदत है, हमारी विकास की परिभाषा, स्वास्थ्य और शिक्षा से शुरू होती है। जब तक एक-एक घर को शिक्षित ना कर दें, दिल्ली में, एक-एक घर तक स्वास्थ्य ना पहुंचा दें, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी दिल्ली सरकार शांति से नहीं बैठेगी, हमारी परिभाषा डिफरेंट हो सकती है। कोई भी विकास तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वह लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे। आगे खड़े होने वालों से हमेशा पूछोगे कि आवाज आ रही है? हां, उनको तो आवाज आती ही है। उनके लिये माइक की जरूरत थोड़े ही होती है। माइक की जरूरत उसके लिये होती है जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। इसके लिये ये बजट बना है। आगे आने वाला तो खुशकिस्मत है, उसे तो सब कुछ मिल ही रहा

है पर जो आज तक पिछड़ा रहा है, उन सब को इन्सान मानते हुए पहली बार कोई सरकार है जो गरीब से गरीब आदमी को, जो दबे हुए को, कुचले हुए को, अपने बराबर मानती है। जो साथ में लेकर चलना चाहती है, उसे इतना योग्य बनाना चाहती है। मैं बहुत-बहुत धान्यवाद करूंगा सर, आपने मौका दिया और बड़ा कॉग्रेच्युलेशंस हमारे वित्त मंत्री साहब के लिये, थैंक्यू सर।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल वाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धान्यवाद करना चाहता हूं और दिल्ली के वित्त मंत्री माननीय मनीष सिसौदिया साहब का भी धान्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा बजट दिल्ली के लोगों को दिया है। बीजेपी के लोग तो खैर चले गये हैं लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि लोग कितना भी कुछ कहें, ये भाजपा के नेता, कांग्रेस के बोखलाए हुए लोग कुछ भी हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करें, मीडिया भी हमारे खिलाफ बहुत कुछ करता है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से पत्रकार बंधु बहुत अच्छे हैं। बहुत से जर्नलिज्म में विश्वास करने वाले लोग अच्छे हैं और ये दैनिक जागरण का अखबार और दिल्ली के सभी अखबारों में, किसी अखबार में ये नहीं आया कि बजट ठीक नहीं है। दिल्ली के सारे अखबार, दिल्ली के सारे इन्टैलैक्चुअल लोग और सड़क पर और चौराहे पर खड़े हुए वो लोग अगर ये कह रहे हों, मार्किट ऐसोसिएशन के लोग कि दिल्ली का बजट बहुत अच्छा सरकार ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है और इसके लिए मैं माननीय मनीष सिसौदिया जी को और दिल्ली सरकार को तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अलका जी ने कहा, नितिन भाई ने कहा।

एक नीं चीज आज तक दिल्ली में नहीं शुरू की गई, मैं उस ओरजरूश्र बात करना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो ये है कि सभी वर्गों के बच्चों के लिए पूरी दिल्ली के अंदर 10 अरली चाईल्डहुड लर्निंग सैंटर खोलने का प्रस्ताव है जो आज तक इतनी सरकारें दिल्ली में रही हैं, आज तक किसी सरकारने ये काम नहीं किया है। इसलिये ये सरकार बधााई की पात्र हैं। आज आपकी विधाान सभा में भी लाइब्रेरी है, कई स्कूलस में भी लाइब्रेरी हैं, लाइब्रेरी हमारे बच्चों की लाईफ का एक हिस्सा है और उस लाइब्रेरी के अंदर आज तक उनके बच्चों को मोटिवेट नहीं किया गया। इसलिये नहीं किया गया कि उनके पास फंडस की हमेशा कमी रहती थी। कम से कम इस सरकार ने सरकारी स्कूलों में, क्लास छठी से लेकर और कक्षा दसवीं तक के बच्चों के लिए 4 सौ नई लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है।

अध्यक्ष महोदय, 24 नये स्कूल खोले जाएंगे। आज अगर पुराना इतिहास उठाकर देख लें, मैं समझता हूं जो स्कूल खोलने का क्रांतिकारी कदम जो इस सरकार के द्वारा किया गया है, आज तक किसी सरकार द्वारा नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, 24 नये स्कूल, 10 हजार क्लास रूम नये बनाए जाएंगे और उनमें से 5 स्कूल, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का प्रस्ताव है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा एक नया प्रस्ताव जो दिया गया, इसके लिये दिल्ली सरकार का हम धान्यवाद करते हैं। (320) अध्यक्ष महोदय, दो हजार से अधिाक बच्चे जहां पर पढ़ते हैं, उनके लिए कम्प्यूटर लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये एक

क्रांतिकारी कदम है जो दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है। 2017-18 के अंदर आज जो प्राईवेट स्कूल के अंदर है, उनके अंदर हमारे स्कूल के बच्चे, हम लोग, उन बच्चों के पेरेंटस वो हमेशा धाक्के खाते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के द्वारा आम आदमी पार्टी की सरकारके द्वारा 2017-18 में 156 स्कूलों में नर्सरी क्लास जो है, वो खोली जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है।

कला और संगीत, हम सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आज कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर हमारी कल्चर, कला और संगीत कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है आज अगर किसी बच्चे से पूछो कि शास्त्रीय संगीत क्या है, पाश्चात्य संगीत क्या है, लोग उस पर जाते हैं। लेकिन अगर पुरानी कल्चर, संगीत की बात करें तो कहीं न कहीं उसे हम भूल रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा कला संगीत की शिक्षा की स्थापना उर्दू और पंजाबी क्लब की स्थापना, जनरैल सिंह भाई बैठे हुए हैं। आज मैं बताना चाहूंगा कि इनकी विधाान सभा में भी अगर आप चले जाइए, बहुत ऐसे आपको क्लब नहीं मिलेंगे, जहां लोग पंजाबी सीखना चाहते हैं, लेकिन क्लब नहीं है। पंजाबी के लिए टीचर्स नहीं हैं। लेकिन उर्दू और पंजाबी क्ल्ब का खोला जाना, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है और मैं सरकार को इसके लिए बधााई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, संजीव भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पूर्वांचल के लोग एक बड़ी संख्या में हैं। हमेशा ये मांग उठती रही है कि छठ घाट कम पड़ रहे हैं और कम से कम और सरकारें तो सिर्फ दिखावा करती थीं, आज भी एक पार्टी के अध्यक्ष जो पूर्वांचल के नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन मैं सर, बताना चाहता हूं कि पिछली

सरकारों ने पूर्वांचल के लोगों के लिए कोई कुछ नहीं किया। कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार ये है कि छठ घाट बनाने के लिए 30 करोड़ रूपये का प्रावधाान और जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए इक्कीस सौ आठ करोड़ रूपये इस सरकार ने दिये हैं। इसके लिए मैं धान्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात करते हैं। कल हमारे माननीय मुख्य मंत्री साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। मैं पंजाब में था। वहां पर जब हम लोग गलियों में घूमते थे तो हम उनसे पूछते थे कि आपके यहां पंजाब में बिजली की यूनिट कितने रूपये की मिलती है। वो कहते हैं 8 रूपये 40 पैसे के हिसाब से मिलती है। आज गुजरात के अंतदर हमारे सीएम साहब ने बोला था कि 400 यूनिट अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो आपको 2700/- रूपये को बिल गुजरात के लोगों को देना पड़ता है। जो माननीय प्रधानंत्री साहब का अपना गृहक्षेत्र है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर दिल्ली के अंदर अगर आप 400 यूनिट बिजली अगर आप यूज करते हैं तो आपको 1370/- रूपये का बिल आपको पे करना पड़ता है। ये इेस बात को दर्शाता है कि अगर गुजरात में 400 यूनिट अगर आप बिजली खर्च करेंगे तो 2700/- रूपये देंगे और दिल्ली का कन्जूमर अगर 400 यूनिट बिजली खर्च करेगा तो 1370/- रूपये देगा। बचत कितने की हुई? 1330/- रू. की। ये एक क्रांतिकारी कदम है और पिछली कांग्रेस की सरकारों में, हम लोग जअ आरडब्ल्यूए में थे, खूब दिल्ली सरकार के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ आंदोलन करते थे। हर बार छः महीने में तीन महीने में कांग्रेस की सरकारें रेट बढ़ाया करती थी लेकिन कम से कम हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार ने आज भी हमने कोई भी एक रूपया, एक चार आने पच्चीस पैसे के रेट हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाएं हैं। ये दिल्ली सरकार का बजट का क्रांतिकारी कदम है।

अध्यक्ष महोदय, आज मोहल्ला क्लीनिक की बात हम लोग करते हैं। पंजाब में था। वहां पर काफी एनआरआई लोग मिले। उनके बीच में संवाद करने को मौका मिला। चुनाव के चार दिन पहले यूएनओ के जरनल सैक्रेट्री कोफी अनान साहब का एक पंजाबी अखबार में और इंगलिश के अखबार में लेख छपा था और उसके अंदर यूएनओ के जनरल सैक्रेट्री ने अरविदं जी की तारीफ की। आज आपके कोई रिलेटिव कोई न कोई सब लोग कहीं न कहीं फॉरन में जरूर रहते होंगे। आज मोहल्ला क्लीनिक एक ऐसा मॉडल है, जहां 2 12 तरीके के टैस्ट फ्री किये जाते हैं। मेरी विधाान सभा से 10 साल मंत्री रहा वहां का और 15 साल का एमएलए था, एक भी मोहल्ला क्लीनिक, एक भी सरकारी डिस्पेंसरी मेरे क्षेत्र में नहीं खोली गई। माननीय सत्येंद्र जैन साहब काभी धान्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक भी डिस्पेंसरी नहीं थी और एक डिस्पेंसरी थी किराए की वो भी वहां के मंत्री ने किसी लेदन की वजह से वहां से शिफ्ट करा दी। लेकिन मैं धान्यवाद करना चहूंगा पोली-क्लीनिक खोलने के लिए दिल्ली सरकार का। दिल्ली का पहली पॉली-क्लीनिक सेंटर मेमरे क्षेत्र कान्ती नगर में खोला गया और आज मोहल्ला क्लीनिक और आज पॉली-क्लीनिक और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे इस बात की भी खुशी है कि माननीय जैन साहब मेरे क्षेत्र में अभी छः करोड़ रूपये के सीनियर सिटीजन सेंटर का का उद्घाटन करने के आए थे, इन्होंने कहा कि आज मैं घोषणा करता हूं इसबात की पॉली-क्लीनिक के अंदर भी अगर कोई मरीज आएगा तो उसको एमआरआई और सीटी स्कैन कराने के लिए अब उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और कम से कम उसका इलाज एमआरआई और सीटी स्कैन किसी भी प्राईवेट अस्पताल में हो जाएगा। ये हमारी सरकार का काम है जो हमारी सरकार ने किया है।

वृद्ध नागरिकों के लिए आयोग का गठन करना। बल्कि एक बात रह गई है कहीं न कहीं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माधयम से कहना चाहूंगा कि अगली बार जब इस तरीके के कोई बजट प्रावधानर होगा तो डिस्एबल्ड लोगों के लिए भी जो हमारे विकलांग भाई हमारे हैं, उनके लिए भी एक आयोग गठित होना चाहिए, ये मेरी एक आपसे प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना को दिल्ली सरकार तक आप पहुंचाइएगा।

आज बहुत सी बातें हैं। एक और बहुत बड़ी बात है जिसके लिए हम आज गौरवान्वित हैं और मैं नतमस्क हूं दिल्ली सरकार का, माननीय उप-मुख्य मंत्री साहब का कि हम वो लोग नहीं हैं, जो झूठ बोलकर जनता के बीच में चले जाएं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इशारा गुरू गोविंद साहब के नाम पर विश्व विद्यालय, गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय जो 271 करोड़ रूपये माननीय उप-मुख्य मंत्री साहब ने दिये हैं। मैं उनको तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस लए शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मेरे जमना पार के अंदर उन शहीदों के नाम पर कोई युनिवर्सिटी खुलने जा रही है। मैं इसलिए सरकार का धान्यवाद करना चाहता हूं। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि हम झूठ बेालने वाले लोग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2013 के अंदर देश की भूतपूर्व शिक्षा मंत्री माननीया स्मृति इरानी जी ने आग के नाम पर एक शिलान्यास किया था गुरू गोविंद सिंह विश्वविद्यालय पर। वहां के सांसद माननीय महेश गिरी साहब भी वहां पर उपस्थित थे। बड़ा प्रचार किया गया। पूरे जमना पार को, भाजपा के लोगों ने सब झंडे, बैनर, पोस्टर सारे से लाद दिया गयाव वहां पर। जिस रोड पर जाइए भाजपा के लोगों के द्वारा गुरू गोविंद सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास पर काफी लोग उसमें गए थे। सारे लोग खुश थे कि कम से कम चलो भाजपा के लोगों ने एक अच्छा काम तो

किया। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, विजेंद्र गुप्ता जी सदन में नहीं है, लेकिन वो मेरी बात जरूर सुन रहे होंगे। एक बात सुन लीजिएगा कि हम लोग प्रचार नहीं करते और जिस तरीके से भाजपा का भगवाकरण कर दिया गया, उसका रिजल्ट क्या रहा? आज गुरू गोविंद सिंह साहब ऊपर हैं ईश्वर के पास मौजूद हैं, कहीं न कहीं उनकी आत्मा जरूर कचोटती होगी कि कम से कम मेरा भी राजनीतिकरण आज भाजपा के लोगों ने कर दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। हम लोग भगवाकरण नहीं करते हैं हम लोग राजनीति की बात नहीं करते हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने कम से कम ये तो कियाहै कि 271 करोड़ रूपया आज उस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए दिया है। ये काम हम लोगों ने किया है और अब भी वक्त है भाजपा के लोग, आदरणीय गुप्ता जी और जो लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को कि अब भी चेत जाइए और आज इस लिए भी अपने आप को गौरान्वित महसूस कर रहे है जमना पार के लोग। दिल्ली में जाते थे, नार्थ कैम्पस में, दिल्ली में जाते थे। कहां जा रहे हो? कि नार्थ कैम्पस में पढ़ने जा रहे हैं। नार्थ कैम्पस में जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? कि साउथ कैम्पस मेमं जा रहे हैं। लेकिन जमना पार के लोगों को तो बिल्कुल रद्दी की टोकरी की तरह से निकाल कर फेंक दिया गया था। कम से कम हमारी सरकार ने एक काम तेा किया है कि हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लोगों के लिए, जमना पार में गुरू गोविंद सिंह साहब ने नाम पर एक यूनिवर्सिटी दे दी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय सिसौदिया जी का ध न्यवाद करना चाहता हूं और जितने एमएलए हमारे यहां पर जमना पार के मौजूद हैं, मनोज भाई मौज्द हैं, बग्गा जी मौजूद हैं, बहन सरिता हैं, नितिन त्यागी जी हैं, कम से कम इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि और अंत

में सरिता जी इशारा कर रही हैं कि अध्यक्ष महोदय भी वहां से हैं। अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से सारी चीज कही गई है। अध्यक्ष महोदय, अंत में यह कहना चाहूंगा कि बगल का विधाान सभा क्षेत्र लगा हुआ है, मैं चाहूंगा सरिता सिंह से, बग्गा जी से और मनोज जी से कि जितने लोग हमारे विध ाायक हैं, खड़े होकर ताली बजाकर कम से कम इस चीज का स्वागत करें। कम से कम ये काम होना चाहिए। (330)

अध्यक्ष महोदय, एक खुशी की बात ओर है कि ये बात सही कही कि कम से कम ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं डेमोक्रेसी तो है। साथी कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं। मैं चाहूंगा सारे लोग एक बार खड़े हो जाएं तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी और अगर ताली बजाएंगे तो।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आप माननीय मंत्री गोपाल राय जी का नाम भूल गए, वो मुस्कुरा रहे हैं मन मन, बहुत मुस्कुरा रहे हैं मन मन।

श्री अनिल वाजपेयी : सर जी, अभी शुरू है। सर, अभी तो खत्म कहां हुआ है सर। अभी तो सर, आपका नम्बर ही नहीं आया अभी। साथियो, अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आदरणीय गोपाल राय साहब का नंबर नहीं आया, देखिए सर, अभी तो हम इधार वाली बॉर्डर लाइन की बात कर रहे हैं, उध ार वाली तो शुरू नहीं की अभी और सबसे बड़ी बात ये है कि जब किसी चीज का कोई बजट अध्यक्ष महोदय, बनाया जाता है तो कम से कम उस क्षेत्र के जो हमारे मंत्री हैं, उनको कहीं न कहीं कांफिडेंस में जरूर लिया जाता है और जमुनापार में इस तरीके का ऐतिहासिक कदम हो और आदरणीय गोपाल राय साहब को उसकी जानकारी न हो या उनका विश्वास अगर न हासिल हो, ये तो सर, असंभव है लेकिन फिर भी आपने कहा है, मैं आदरणीय गोपाल

राय साहब का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं खुद मेज थपथपा के उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। ऑलरेडील मनीष भाई हमारे बीच में आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले होते तो ज्यादा अच्छा रहता सर। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा मनीष जी, इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मनीष जी कि आज पूरा जमुनापार आपका आभार प्रकट करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका ऋणी हूं। यहां जितने यमुनापार के विधाायक हैं और माननीय मनीष जी मैं एक बात और ह देना चाहता हूं, आपके आने से पहले जब कह रहा था तो लोग कह रहे थे यमुनापार की बात मत करिए, पूरी दिल्ली के एमएलए आपके साथ हैं। आज उधार से भी लोग कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ है हमारे और सारे लोग कह रहे हैं कि आज सारे दिल्ली के सारे विध ाायक आपका सर, धान्यवाद इसलिए भी करते हैं कि आज गुरू गोबिंद सिंह के नाम पर जमुनापार के लोगों को आपने इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी दी है। हम आपके ऋणी हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं और एक अपील आपसे और करनी है एक अपील, एक अपील और आपसे करते हैं कि जो 2013 में स्मृति ईरानी ने झूठा शिल्यानाश करके दे दी, कम से कम आज 271 करोड़ रूपये आपने हम लोगों को दिया है कि उस यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी काम की शुरूआत हो जाए ताकि अगली बार जब हमारा बजट सैशन हो तो हम लोगों से कह सकें और जो भाजपा क लोगों ने राजनीतिकरण किया है, जिन भाजपा के लोगों ने गलत प्रचार किया है, कम से कम उनसे हम कह सकें कि आज अगर हमने 271 करोड़ रूपये दिया है तो अगली बार जब हम आऐंगे बजट सेशन में तो विजेंद्र गुप्ता जी, जगदीश प्रधान जी, आपको भी धान्यवाद करना चाहिए कि ये अच्छा काम है ये कम से कम आप लोग खड़े होकर ये कहे कि हमारी सरकार ने कोई अच्छा काम किया है।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी ने जब आप बोल रहे थे, वो बजट की पुस्तक उठाकर उसको ढूंढा है।

श्री अनिल वाजपेयी : सर, जगदीश जी तो हमारे पुराने मित्र भी हैं और मैं इनका धान्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे हर अच्छे काम के लिए ये हमेशा एप्रिशिएट कर सकते हैं, मैं इनका भी धान्यवाद करना चाहूंगा और ओम प्रकाश जी तो सदन से बाहर हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आप उनको जरूर और ओक प्रकाश जी तो सदन से बाहर हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आप उनको जरूर बताएं कि ओम प्रकाश जी, अगर आप ने भी अध्यक्षमा उस कार्यक्रम की थी, उनका विधाानसभा क्षेत्र है, एक बार आज मनप में पीड़ा ये है कि मान लो अगर मैं उस क्षेत्र का विधााय हूं और अगर उस क्षेत्र में कोई काम होता है और अगर न हो, तो हमारी सरकार के लोग भी क्यों न हों, हम अपनी सरकार के लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। लेकिन मन में पीड़ा है माननीय विधाायक ओम प्रकाश शर्मा जी ने एक बार भी हाउस के अंदर, एक बार भी कहीं जाकर ये नहीं कहा, जब कि सरकार उनकी है। विधाायक आप उन्हीं की पार्टी के हैं। एक बार तो कहना चाहिए था स्मृति ईरानी जी को, एक बार तो महेश गिरी से कहना चाहिए था कि आपने जो उदघाटन कराया है, कम से कम, कहीं न कहीं, इसको पूरा करेंगे। मैं अंत में आदरणीय अध्यक्ष जी का, भाई मनीष जी का बहुत बहुत धान्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सरिता सिंह जी। सब कुछ तो बाजपेयी जी बोल गए।

श्रीमती सरिता सिंह : मैं यमुनापार से शुरू करने वाली थी शुरूआत। एंड ही कर दिया उन्होंने तो। बहुत-बहुत धान्यवाद स्पीकर महोदय और बहुत ही हर्ष के साथ जो यमुनापार की बात इन्होंने शुरू की थी, उसका जब कल

बजट पेश हुआ तो दिमाग में यही आर हा था कि ऐसी क्या चीज है। जो मनीष जी के दिमाग में चलती है। ऐसी क्या चीज है जो जनता हमें आ कर कहती है और हमारे बजट में वही चीज नजर आती है, मतलब सच में, मतलब जब हम लोग उस बजट को सुन रहे थे, उस बजट को जब घर जाके अध ययन किया तो ये लगा ये तो मेरी ही आवाज थी, ये तो मेरे दिमाग में था। जब क्षेत्र के लोगों से बात हुई, आपके बजट में ये भी है, ये तो हमारी आवाज थी। मतलब इसी को बोलते हैं कॉमन मैन बजट, इसी को बोलत हैं कि आम आदमी जब बजट बनाता है तो अपने पॉकेट को, अपने सिस्टम को, अपनी फैमली को कैसे चलाएगा! जब मनीष जी ने पिछली बार बजट शुरू किया था तो उन्होंने ये बोला था कि मुझे एक परिवार चलाना है तो इस परिवार के लिए क्या-क्या प्राथमिकताएं हैं, मैं पहले उसके लिए इन्वेस्ट करूंगा और फिर उसी लग्जरी के लिए सोचूंगा। तो इस बार भी जो बजट था, वो वही था कि जो भी हमारी नेसेसिटीज थी, वो सब कुछ इस बजट में है जो भी कुछ हम सोचते थे। चाहे हम एक महिला विधाायक हों तो हमेशा महिलाओं के लिए जो आवाज उठाती रही है और कल सुबह ही जब हम सब 6 की 6 महिला विधाायक आप भी स्पीकर सर वहां पर थे, जब हम महिला आयोग के प्रोग्राम में गए थे और उसी समय स्वाति मालीवाल जी ने जो अपनी महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने ये बात रखी थी कि बहुत अच्छा काम दिल्ली महिला आयोग कर रही है पर अगर और फंड मिलता तो और काम होता और दोपहर में ज वो बजट आया तो उसमें 20 करोड़ रूपया जो पहली बार हुआ है, ट्रिपल द अमाउंट, तीन गुना पैसा महिला आयोग को दिया गया और क्यूं दिया गया? क्योंकि महिला आयोग ने पिछले दो सालों में वो काम किया। महिला ओयाग ने आज शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि नेशनल

विमन्स कमीशन की चेयरपर्सन कौन है, पर आज देश के, दिल्ली के नहीं, देश के बच्चे-बच्चे को ये पता है कि स्वाति मालीवाल कौन है। क्योंकि उन्होंने वो काम किया है। वो निष्पक्षता से, वो स्वतंत्रता से उन्होंने काम किया है और जो 20 करोड़ रूपये कल उनको महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया गया, ये सबसे सराहनीय काम है। एक महिला विधाायक, एक महिला जनप्रतिनिधि ाहोने के नाते मैं पूरी दिल्ली की महिलाओं की तरफ से अपने वित्तमंत्री का तहेदिल से धान्यवाद करूंगी। क्योंकि अग कहीं न कहीं वो जो महिला पंचायत का सपना था, हर मौहल्ले, हर गली, हर विधाान सभा क्षेत्र में एक महिला पंचायत हो। कम से कम महिला जो आईटीओ नहीं जा सकती है, जो कहीं नहीं जा पा रही है, वो कहीं न कहीं अपनी विधाान सभा, अपने क्षेत्र में अपनी निजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हमने परसों ही डिस्कस किया था गुरमेहर कौर को और उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा था साइबर क्राइम, जिसमें साइबर क्राइम में ये कहा गया था के गुरमेहर कौर को जो धामकियां मिली वो फेसबुक और वॉट्सएप और ट्विटर के थ्रू मिली। उसने इंटरनेट में अपनी आवाज उठाई और इंटरनेट जब भी दिल्ली पुलिस से बात होती है, दिल्ली पुलिस यह कहती है कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते और कल स्वाति मालीवाल जी ने ये बोला था कि हमत साइबर क्राइम में काम करना चाहते हैं, महिला पंचायत में काम करना चाहते हैं। हम वन प्वाइंट सेंटर यानि एक जगह जहां पे महिला जाए और उसके सारे प्रॉब्लम्स का निवारण किया जाए। तो कहीं न कहीं वो जो क्राइम अगेंस्ट मिवन की बात थी, उसमें दिल्ली सरकार ने केवल कहा हनीं है, उसमें किया है और उसके लिए सबसे पहले एक महिला विधाायक होने के नाते मैं उनका धान्यवाद देना चाहती हूं। सबसे बड़ी बात जो महिलाओं के लिए हुई है, वो हुई शायद बहुत बड़ा नहीं होगा पर एक महिला हूं इसलिए

फील कर सकती हूं कि जो मिड डे मील में जो स्पेशली छात्राओं को जो बेनिफिट मिला है, वो छात्राओं को जो बेनिफिट मिला है, वो छात्राओं को बेनिफिट दिया जाएगा, उससे जो फायदा मिलने वाला है, हमारे समाज को बनाने में कहीं न कहीं एक राइट टू इक्वालिटी की जो बात हम करते हैं, कहीं न कहीं वो स्टेब्लिस्ट होगा। वो लोगों के दिमाग में आ गया है कि अब सरकार जब महिलाओं के लिए सीरियस है, सरकार जब बच्चियों के लिए सीरियस है तो हमें भी अपनी बच्चियों को आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं मनीष जी का और एक्चुली मैंने ये सोचा था कि मैं ईस्ट कैम्पस की बात करूंगी, मैं डीटीयू की बात करूंगी जो डीटीयू हमारे ईस्ट कैम्पस में हो रहा। जब हम यमुनापार वाले लोग बात करते हैं तो कहीं न कहीं....एक दिन एक अधिकारी से बात की थी, उस अधिकारी ने कहा कि आप वहां पे ये काम करना चाहते हो, पर शाहदरा तो बहुत गंदा इलाका है। मतलब आई वाज शोक्ड टू लिसन दिस कि लोग यमुनापार को किस नजरिये से देखते हैं और हमारी सरकार ने उस नजरिए को बदलने का एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और यमुनापार से आने के नाते मैं अपनी पूरी की पूरी केबिनेट को यहां पे और मैं शायद पता नहीं पर हमारे तीन मंत्री हैं, वहां पे और इसलिए यमुनापार की आवाज इतनी मजबूत है तो मैं इनका बहुत बहुत धान्यवाद देना चाहूंगी यमुनापार को अपने बजट में इतना इम्पोर्टेंट प्ेस देने के लिए। मजदूरों की बात हम करते हैं हम ये कह रहे हैं कि हमने अपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के लेवल पर ला के खड़ा कर दिया। अभी तक बस एक कमी थी कि नस्र्री में एडमिशन नहीं होता था इस बार नर्सरी में एडमिशन भी होने लगे और ये एक आम आदमी की आवाज थी जो हमारे पास आके कहते थे कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं

होता, आप सरकारी स्कूलों में नर्सरी शुरू करवा दोक न हम सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे। दो साल पहले की ये बात थी कि लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे और शायद आज सब विधायक ये चीज कहीं न कहीं महसूस करते होंगे कि आज हमारे पास जो लोग एडमिशन के लिए आ रहे हैं उसमें सरकारी स्कूलों की मात्रा ज्यादा है। लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और नर्सरी का जो एडमितशन हमने शुरू किया, ये अपने आप में रिमार्केबल स्टेप है। This has made us come at par with the private schools. क्या अब हमारे ये स्कूलों में नर्सरी के बच्चे ही पढ़ेंगे और मैं बस यही कहना चाहती हूं कि सरकारी स्कूल में जाता कौन है, मोहल्ला क्लीनिक में जाता कौन है, (340) पेंशन की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको होती है? वो उनको ही होती है जो मजदूर या उस वर्ग के लोग आते हैं और हमारी सरकार ने ये साबित किया है कि हमने अपने नारों में बहुत बड़े-बड़े वादे नहीं किए थे, हमने कोई जुमलेबाजी की सरकार नहीं बनाई थी। हमने एक्चुअली में आम आदमी की सरकार बनाई और जो मिनिमम वेजिज में 37 परसेंट का इजाफा हुआ है, जो बढ़ाया गया है, ये केवल हम उनको एक एकॉनोमिक पावर नहीं दे रहे हैं। हम केवल उनको पैसे से समृद्ध नहीं बना रहे हैं, हम उनको एक सोशल स्टेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उनके जीने के स्तर को बढ़ा रहे हैं। जब उनकी सेलरी बढ़ेगी तो वो अपने घर में अच्छा खाना भी खा पायेंगे, वो अच्छा कपड़ा भी पहन पायेंगे, वो अच्छा सोच भी पायेंगे। वो एक तनावमुक्त जिंदगी जियेंगे और यही सपना आम आदमी पार्टी सरकार का था और शायद यही सपना जो तनावमुक्त जिंदगी लोगों को देने का था शायद बजट के पहले अमारी जो केबिनेट है, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, शायद यही सोचते होंगे। इसलिए इतना कॉमन बजट, जहां पर टैक्स बढ़ाने

की बात तो दूर हम टैक्स घटाते हैं। 1 2.5 परसेंट से 5 परसेंट लेके आते हैं, टैक्स फ्री बजट बनाते हैं, आउटकम बजट बनाते हैं जिसमें हम ये तय करते हें कि अगर यहां पर इतना पैसा लगता है, अगर उसे इतनी परसेंट जनता सेटिस्फाईड है तो हमारा बजट सक्सेसफुल है तो हमारी सरकार उस डायरेक्शन में काम कर रही है और इसलिए काम कर रही है क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहुत जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल गैकग्राउण्ड होगा, जिसकी अपनी कोई मंशा होगी। इसीलिए सरकार, इसीलिए हमारी केबिनेट मैं दिल से अपनी केबिनेट, अपने वित्त मंत्री जी का धान्यवाद देना चाहूंगी कि ये जो बजट आया है, ये सच में हर आम आदमी की आवाज है। हम जब चर्चा करेंगे कि ये जो बजट आया है, ये सच में हर आम आदमी की आवाज है। हम जब चर्चा करेंगे तो सच में ये सब प्रपोजल जो हमारे बजट में है, वो सब कुछ उनकी आवाज थी जो इस बजट में है तो आपका बहुत-बहुत ध ान्यवाद और रिमार्केबल बजट। थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राजेंद्र पाल जी को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व इस सदन को एक जानकारी देना चाह रहा हूं।

माननीय उपराज्यपाल का संदेश

माननीय सदस्यगण, मुझे उपराज्यपाल महोदय से दिनांक 8 मार्च, 2017 का संदेश प्राप्त हुआ है इसके अंतर्गत उन्होंने ये सूचित किया है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय ने न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधान विधोयक 2015 (वर्ष 2015 का विधोयक संख्या-13) को विधाानसभा में पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है।

श्री राजेंद्र पाल गौतम जी।

....(व्यवधान)

श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय) : अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम वेतन तो लागू हो गया है, लेकिन न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बाद भी बहुत सारी संस्थाएं जो है वो वेतन नहीं देती हैं तो उसके लिए हमने प्रावधाान ये किया था कि. ...पहले प्रावधाान है कि अगर नहीं देते हैं तो अध्यक्ष जी, उसको 6 महीन की सजा और 500 रूपये जुर्माना है। उसको हमने यहां सदन में पास किया था कि उसको बढ़ाकर के 50000 रूपये किया जाए और तीन साल की जेल किया जाए। वो प्रस्ताव यहां से केंद्र को गया हुआ था, उसके बारे में अभी सूचना आई है।

श्री महेंद्र गोयल : क्या सारी की सारी चीजें बीजेपी वालों की है? ये सारी दुकानदारी! ये आम आदमी के हित की बात कर रहे थे। कानून को ठोस करके ही तो मतलब इंप्लीमेंट होगा ना। राष्ट्रपति जी के यहां से आई है।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए महेंद्र जी, बैठिए प्लीज। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : धान्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे दिल्ली के बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया। ये जो दिल्ली का बजट है ये दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं का बजट है। ये बजट दिल्ली के गरीबों की भावनाओं का बजट है, ये बजट छात्रों की आशाओं का बजट है और ये बजट हम सबकी अभिलाषाओं का बजट हैं ये बजट अद्‌भुत है। मैं अभिभूत हूं इस बजट को देखिकर। चूंकि ये बजट आइना है दिल्ली सरकार के विजन का कि दिल्ली कैसी बने, दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर कैसा हो। दिल्ली में न्यूनतम स्तर

तक सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे। इन सब बातों को इस बजट में समावेश किया गया है। इस बजट से मैं वास्तव में अभिभूत हूं। मुझे नहीं लगता दिल्ली का कोई भी साधाारण परिवार, मधयम परिवार, निम्न परिवार ऐसा होगा जिसे महीने में कम से कम 1000-1200 रूपये का फायदा प्रतिमाह ना हो रहा हो। मुझे खुद पिछले महीने 394 रूपये बिजली के बिल में छूट मिली उससे पिछले महीने 415 रूपये मुझे बिजली में छूट मिली। पानी का बिल मेरा जीरो आ रहा है। मेरा बच्चा जिस पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, अब तीसरा सेशन आने वाला है, तब से अभी तक कोई फीस भी नहीं बढ़ी है। इसको अगर मैं जोड़ लूं तो मेरे जैसे स्तर के आदमी को भी कम से कम 1200 रूपये महीने का लाभ हमारी इस दिल्ली सरकार की योजनाओं के वजह से मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में जैसे पिछली दफा शिक्षा का बजट 23 परसेंट दिया और इस दफा शिक्षा का बजट 24 परसेंट दिया; ये दर्शाता है ठोस इरादों को। माननीय शिक्षा मंत्री जी चांस की बात है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं कितना अच्छा तालमेल उन्होंने किया कि सभी वर्गों को समान रूप से इस बजट में कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण मुझे लगी, वो लगी एक नई सोच के साथ इसबजट में एक चीज जोड़ी गई कि हम इसको आउटकम बजट कहेंगे। आउटकम बजट अब से पहले कभी सुनने को नहीं मिला, ये तो ठीक है पहले बजट अलॉट होता था, फंड मिलता था और फंड खर्च होता था। लेकिन क्या उसके आउटकम पर कभी चर्चा नहीं होती थी कि जो बजट खर्च हुआ, उसमें जनता को डायरेक्ट लाभ कितना मिला। मैं एग्जाम्ल के तौर पर कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे क्षेत्र में बल्कि मुझे लगता है दिल्ली के कई क्षेत्रों में कई

सुपरस्पेशिलिटी हास्पिटल बने, वहां हजारों....मुझे लगता है हजार करोड़ रूपया कम से कम खर्च हुआ करोड़ों रूपये की मशीन इंस्टाल हुई। लेकिन वो हॉस्पिटल अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से नहीं चल पाए। उन हॉस्पिटल्स में करोड़ों रूपये की मशीन इंस्टाल हुई है जो आज तक काम नहीं कर रही थी। पिछले तीन सालों में उनमें मशीनों ने काम करना शुरू किया है। लेकिन अभी भी कुछ मशीनें बंद हैं। लेकिन मैं धान्यवाद करना चाहूंगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कि जो आउटकम बजट की जो एक नई सोच उन्होंने दी, अब कम से कम कहां पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका लाभ जनता को कितना मिला, हर तीन महीने में अगर उसको देखा जाएगा, उस पर नजर रखी जाएगी तो ये रिजल्ट ओरिएंटिक बजट कहलाएगा जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूं कि हमने बजट बढ़ाया एजूकेशन का स्पेशियली 24 परसेंट कियाक, हमने हेल्थ का बजट भी बढ़ाया, हमने स्कूलों में 8000 कमरे पिछले वर्ष में बनाए, लगभग तैयार हैं, 1000 कमरे और बना रहे हैं, 25000 हम लोग बेडस की संख्या 10000 कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। कृपया इन सभी स्कूलों में, सभी हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा स्टाफ जरूर बढ़ाएं। अगर हम स्टाफ नहीं बढ़ाएंगे तो ये आउटकम बजट पर जब हम पहुंचेंगे तीन महीने के बाद तो वहां ये बात नजर आएगी कि हम स्टाफ की कमी की वजह से अपने उस लक्ष्य को पूरी तरह न पा सके। लेकिन अगर इस पर अभी से धयान दिया गया जाएगा, स्कूलों में अगर टीचर्स की मात्रा बढ़ाई जाएगी, हास्पिटल्स में अगर डॉक्टर्स की, लेब टैक्नीशियन्स की और स्पेशयली जो दवाई काउंटर्स है जहां बहुत लंबी भीड़ होती है, उन दवा के काउंटर्स

पर हम लोग फार्मासिस्ट की संख्या बढ़ाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और ये आउटकम बजट अपनी सही दिशा में पहुंचेगा। (350)

दूसरा एजूकेशन के साथ-साथ, एजूकेशन में तो 11300 का बजट, मुझे लगता है इतना 24 परसेंट देश के किसी कोने में, किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया और किसी भी समाज की तरक्की का अगर कोई पैमाना, मापदंड है तो उस स्टेट के एजूकेशन के लेवल को चेक करना होगा। केवल कमरा बना देना, स्कूल ज्यादा खोल देना, कालेज खोल देना, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। खुशी इस बात की है कि क्वालिटी एजूकेशन, उस पर सबसे ज्यादा धयान दिया जा रहा है इस सरकार में। खुद माननीय उपमुख्यमंत्री जी, जो एजूकेशन मिनिस्टर भी हैं....किसी प्रिंसिपल को पता नहीं होता है कब वो किस स्कूल में आकर के विजिट कर जायें। उससे जो टीचर्स के अंदर एक वातावरण, माहौल बना। उनको लगने लगा कि अब पढ़ाना पड़ेगा। पहले क्या था लैब्स के अंदर टीचर्स डिस्कसन करते रहते थे। क्लॉस में पढ़ाने नहीं जाते थे। ये जो एसएमसी को मजबूत करना, उसको ज्यादा एम्पावर करना, स्कूल, क्लासेज में नजर रखना, स्कूल्स के अंदर पानी कैसा मिल रहा है, ठीक पीने के योग्य मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सफाई ठीक ठाक है, नहीं है। प्रिंसिपल को स्पेशियली एजूकेशन तक सीमित रखना कि आप एजूकेशन का स्तर सुधाारने में धयान दीजिए। अलग से एस्टेट मैनेजर और सुपरवाईजर देना, ये दर्शाता है कि हमारे शिक्षा मंत्री क्वालिटी एजूकेशन पर ज्यादा धयान दे रहे हैं और मैं समझता हूं दिल्ली की जनता का विकास का पैमाना एजूकेशन और हेल्थ। चूंक एजूकेशन एंड हेल्थ आर दि प्राइम रिस्पॉन्सिबिल्टी ऑफ दि गवर्नमेंट....और इन दोनों ही सरकार की जिम्मेदारियों को सरकारने बहुत बखूी, बहुत ईमानदारी से निभाया है। इसलिए भी ये बजट अद्‌भुत है। इसलिए मैं अभिभूत हूं।

साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में 1506 करोड़ ट्रांसपोर्ट और रोड के लिए बजट दिया। मैं समझता हूं ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा लेकिन एक साथ में निवेदन भी है। केवल कलस्टर बसें नहीं, डीटीसी की भी बसें बढ़ें तो और ये ज्यादा अच्छा होगा। हमारे सरकार के एसेट्स बढ़ेंगे। सोशल सिक्योरिटी पर विशेष धयान सरकार ने दिया है। जैसा अभी बहन सरिता कह रही थी। मिड डे मील में बच्चों को और विशेष रूप से बच्चियों को मिड डे मील में एक येग और ऐ बेनाना, इसको शामिल करना ये दर्शाता है कि किस बारीकी तक सरकार धयान दे रही है। अच्छा केवल खाना ही नहीं, बल्कि पौष्टिक आहार भी साथ में मिले। ज्यादा मजबूती, बच्चे बचपन से ही मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनें। मैं समझता हूं दिल्ली के अगर ये बच्चे मजबूत बनेंगे और एजूकेशन में भी मजूत होंगे, हेल्थ में भी मजबूत होंगे तो दिल्ली की तरक्की नि:संदेह ज्यादा तेज गति से बढ़ेगी। ये अपने आप में उस विजन को दर्शाता है। जो हमारे फाईनेन्स मिनिस्टर का विजन है। जो हमारी सरकार का विजन है। वो उस विजन को स्पष्ट करता है कि हम केवल विजन नहीं बनाते। हम केवल बजट नहीं बनाते बल्कि हम अपने दिल्ली के हर नागरिक, हर बच्चे, हर गरीब, हर महिला सबके ारे में धयान रखते हैं और बजट में सबको कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया है। मैं एक निवेदन माननीय उपमुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा। जिस प्रकार देहली कमीशन फार विमन है और जिस प्रकार एक नई सोच के साथ सीनियर सिटीजन कमीशन भी बनाने की जो परिकल्पना की है, ये वास्तव में काबिलेतारीफ है। बहुत अच्छा है लेकिन इसके साथ-साथ चूंकि सफाई कर्मचारी का मिशन भी यहां है, पिछड़ा आयोग भी यहां पर है। एक शिड्यूल कास्ट कमीशन भी यहां बने। क्योंकि जो शिड्यूल कास्ट बोर्ड है, वो बोर्ड अपने आप में नाकाफी है। उससे कुछ रिजल्ट नहीं

आता है। उस बोर्ड की, ज से वो बना है,अ ब तक शायद एक मीटिंग केवल हुई है। उस बोर्ड की, जब से वो बनाहै,अब तक शायद एक मीटिंग केवल हुई है। उस बोर्ड को कोई पासर नहीं हैं। मैं समझता हूं अगर सफाई कर्मचारी आयेाग बन सकता है। अगर दिल्ली कमीशन फारव वूमन बन सकता है। अगर सीनियर सिटीजन कमीशन फार वूमन बन सकता है। अगर सीनियर सिटीजन कमीशन बन सकता है तो दो कमीशन और कम से कम बनाये जायें। जैसा बाजपेयी जी ने कहा कि एक डिसएबल्ड कमीशन बन जाये और एक शिड्यूल कॉस्ट कमीशन बन जाये तो सरकार और ज्यादा मजबूत होगी। ज्यादा लोगों के पास हम लोग न्याय पहुंचा पायेंगे। पानी के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व देखने को मिला और जो भी तय किया, सरकार ने एक विजन के तहत कि हम हर घर तक, हर टोंटी तक साफ पानी पहुंचायें, ये परिकल्पना अपने आप में हमें बहुत खुश करने वाली है क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं और मुझे लगता है। पानी और सीवर की जब ात आती है तो सबसे ज्यादा शिकायतें विधाायकों के पास गंदे पानी की आती हैं और ये अगर एक साल के अंदर. ...एक साल तो छोड़िये, मैं तो कहता हूं अगर दो-तीन साल तक भी हम गंदे पानी की समस्या को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। ये परिकल्पना जो हमने की है, वाकई काबिलेतारीफ है और जितना बजट सरकारने अपने जल के लिए और सीवेर के लिए जो दिया है, वो बहुत ही अच्छा काबिलेतारीफ है।

इसके साथ-साथ बिजली-पानी की तो मैं पहले ही कह चुका हूं। मनीष जी ाहर थे कि मेरे जैसे आदमी को भी 1200 रूपये कम से कम पर मंथ का फायदा हो रहा है तो इससे पूरी दिल्ली के मुझे लगता है, बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जो इस फायदे से वंचित होंगे। मुझे लगता है 80-90 प्रतिशत

लोग इस फायदे का लाभ उठा पा रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार का धान्यवाद करना चाहूंगा और पेंशन योजना जो अभी शुरू की है बुजुर्गों के लिए, जो हमने बढ़ाया है, डबल कर दिया है लगभग....जो हजार रूपये का था, दो हजार कर दिया, पंद्रह सौ को ढाई हजार कर दिया। ये बहुत ही बढ़िया है। सर, एक निवेदन छोटा सा आपसे करना चाहता हूं। आज सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, वहां सीनियर सिटीजन के लिए बहुत भयंकर लंबी लईनें लग रही हैं। कुछ बुजुर्ग रात को ओके वहां सो जाते हैं। कुछ सुबह पांच बजे वहां पहुंच जाते हैं औरवहां केवल एक काउंटर है। टेम्परेरी, कुछ समय के लिए एक की बजाय दो काउंटर करवा दें और वहां सर, आनलाईन के बाद वहां जमा करना पड़ता है, उसके लिए सात दिन का टाईम है और एक से दो बजे दोपहर को। वहां इतनी भयंकर भीड़ है। कुछ बुजुर्ग बेचारे दब जाते हैं। एक तो कम से कम सिविल डिफेंस के वालंटियर्स को कुछ दिन के लिए वहां पर लगा दें ताकि लाईनों में बुजुर्गों के ऊपर न चढ़ें लोग। वो थोड़ा सा सिस्टर्मा में आ जाये। उनको लाभ मिलेगा। इस पर भी थोड़ा सा धयान देंगे। मैं अपनी सरकार को इस अद्भुत बजट के लिए, इस आउटकम बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने एक अभूतपूर्व बजट बनाया है। सरकार ने सभी लोगों तक उसका लाभ पहुंचाया है और आने वाले समय में ये बजट भारत के दूसरे राज्यों के फाईनेंस मिनिस्टर्स के लिए एक आईना साबित होगा। उनके लिए ये एक ऐसी किताब बनने वाली है, जिसको भारत के सभी राज्यों के फाईनेंस मिनिस्टर बड़े गर्व के साथ पढ़ेंगे और मैं समझता हूं मजबूर हो जायेंगे कि वो लोग हमारे दिल्ली सरकार के फाईनेंस मिनिस्टर के बनाये हुए बजट को फॉलो करें। इसी आशा के साथ मैं पुनः अपनी सरकार का, माननीय मनीष जी का, सीएम साहब का धान्यवाद करता हूं इस अद्भुत बजट

के लिए और आपने मुझे इस परचर्चा का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धान्यवाद। बहुत-बहुत आभार। शुक्रिया, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैंने पहले सदन की कार्रवाई आरंभ होने सेप हले जरनैल सिंह जी के जन्मदिन की बधाई दी थी। अभी उन्होंने सूचना दी है कि जलपान की व्यवस्था की गयी है। साढ़े चार बजे जलपान के बाद यहां मिलेंगे। एक बार पुनः उनके जन्मदिन की बधाई।

(अब सदन की कार्यवाही अपराह्न 4.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।)

सदन अपराह्न 4.35 बजे पुनः समवेत हआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती वंदना जी।

श्रीमती वंदना कुमारी : अध्यक्ष जी, धान्यवाद कि इस जट पर हमें बोलने का आपने मौका दिया।

इस बार की बजट जो आई है, हम सब के लिए, पूरे दिल्लीवासियों के लिए बहुत ही सुनहरा बजट है और जहां भी, जिस गली में हम सब जा रहे हैं, कल एक सीनियर सिटिजन मुझे मिले थे और वो कह रहे थे चूंक मैं अभी चर्चा ही कर रहा था, सीनियर सिटिजन के मुद्दे पर आपी सरकार क्या कर रही है, उनके रिक्रिएशन सेंटर के लिए क्या कर रही है तो मैंने कहा आपने आज का बजट नहीं सुना क्या? जो बुजुर्गों के लिए आयोग बनाने की बात हमारी सरकार ने कही है और उनकी छोटी-छोटी समस्याओं को धयान में रखते हुए यह आयोग बनाया गया।

सर, अभी हाल ही में जो शिक्षा के बजट पर बात चली तो एक-एक पेरेंट्स से जहां मिलते हैं, पिछली पेरेंट-टीचर मीटिंग हुई थी और जगह-जगह लोगों को संदेश गया था कि रीडिंग मेला के माधयम से शिक्षा का संदेश घर-घर तक पहुंचा था। उस शिक्षा को देखते हुए लग रहा था, जैसे शिक्षा के बजट को देखते हुए, हम परिवार में बैठे अपने बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनके डे बाय डे की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनकी पढ़ने की शैली से लेकर, उनके अक्षर ज्ञान से लेकर, उनके स्किल डेवलपमेंट से लेकर और एक-एक चीज पर धयान रखा है हमारी सरकार ने। मैं तहेदिल से अपनी सरकार और मनीष सिसोदिया जी का, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनको तहेदिल से बधाई देना चाहती हूं जो शिक्षा के स्तर को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है।

इसमें मैं अपनी छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं जब मैं एक एनजीओ के माधयम से गली-गली में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए घूमती थी। एक पेड़ के नीचे से मेरे कैरियर की शुरूआत हुई थी और छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उस समय क्या हुआ, कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे कहा कि शिक्षा के प्रति बच्चों को इतना जागरूक करने की क्या जरूरत है और उनके स्कूल में उस समय, जब पेड़ के नीचे हमारे 188 बच्चे रेग्युलर तीन महीने तक आते थे, बारिश भी होती थी तो वहां पर वो बच्चे आते थे, वेट करते थे, कोई आता था तो बच्चे को लंच खिला जाता था, किसी की बर्थ डे पार्टी होती थी तो वो बच्चों को बैग बांट कर जाते थे। एक समय कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर गाय खोल दी। बच्चे भागने लगे, इधार-उध ार भटकने लगे। उस समय हमारे शिक्षा मंत्री थे कपिल सिब्बल जी। उनके पास मैं गई थी, तो उनका एक ही वर्ड था जो आप इन सब बच्चों को

पढ़ा दोगे तो हमारी कौन सुनेगा। उस समय की यह बात मेरे दिलों-दिमाग में हमेशा रही कि हमारी कौन सुनेगा? मतलब हर नेताओं की यह इच्छा होती थी अगर ज्यादा पढ़-लिख लेंगे तो हमसे सवाल करेंगे, हमसे पूछेंगे हर बात के लिए, हर बात का हिसाब मांगेंगे और आज वो चीज जो हम सब का सपना था, हर एक बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चा अपनी बात पूछे, हर नागरिक को अपनी बात को समझने का अधिाकार हो, वो हमारी सरकार ने सिद्ध कर दिया। शिक्षा के लिए ऐसी बजट बनाने के लिए मैं अपने वित्त मंत्री जी का तहेदिल से स्वागत करती हूं और बधााई देती हूं।

दूसरी, जो हम महिलाओं के लिए, सबसे बड़ी बात जो महिला पंचायत की बात आई, दिन भर में छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर हमें हर बात के लिए महिला आयोग भेजना पड़ता है क्योंकि पुलिस तो हमारी सुनती नहीं। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, वो प्रताड़ित होती रहती है, वो परेशान होती है। उसकी घर से लेकर बाहर तक, ऑफिस से लेकर रोड तक, वो किसी न किसी समस्यासे उलझती रहती है लेकिन कभी भी उसकी कहीं नहीं सुनी जाती। जो हमारी सरकार ने, उन छोटी बातों पर भी धयान दियाअ ौर महिला आयोग को एक बहुत बड़ी ताकत दी, जो उनका बजट तिगुना करके, जिससे महिला पंचायत हर मोहल्ले के अंदर अपना काम कर सकता है और महिलाओं की छोटी-छोटी समस्या उनके मोहल्ले में सुलझाई जा सकती है। इसके लिए भी मैं अपनी सरकारको तहेदिल से बधााई देती हूं।

तीसरी चीज जो हम सब की भावनाओं को छूती है, हम सब की आस्थाओं से जुड़ी है, आज तक पूर्वांचल वासियों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझा गया। वोट के समय उनको याद किया जाता था। वोट के समय उनके पास जाया

जाता था। हमारी सरकार ने उन चीजों पर भी धयान दिया। सिर्फ छठ पूजा में जाते थे और उनके मंच पर अपने लंबे-लंबे भाषण देकर अभी तक ककी जो सरकार रही, वो चली आती थी। लेकर कभी भी उनकी भावनाओं का धयान नहीं रखा गया, कभी भी उनकी आस्थाओं को समझा नहीं गया। (440) जब पहली बार हमारी सरकार बनी और छठ पूजा में स्टैज पर गये तो पहली बार से ही एक एक चीज की व्यवस्था, घर से लेकर घाट तक हमारी सरकार ने धयान रखा और पूर्वांचलवासियों की आस्था और भावनाओं की कद्र करके 20 करोड़ का बजट छठ घाट के लिए दिया गया। इसक लिए मैं अपने पूरे पूर्वांचलवासियों की ओर से पूरी दिल्ली वासियों की ओर से मैं अपनी सरकार को तहेदिल से बधााई देती हूं और धान्यवाद देती हूं जो कि हम सबकी भावनाओं की कद्र की हमारी सरकार ने।

अभी जो मैं पहले बता भी चुकी हूं कि जो पिछले साल हमने 15 रिक्रिएशन सेंटर्स सीनियर सिटीजन के लिए, उनकी सोसायटी के माधयम से सरकार तक पहुंचाया था, सोशल वेल्फेयर सोसायटी के माधयम से आज 6 रिक्रिएशन सेंटर्स को मान्यता मिल चुकी थी जो 20 हजार प्रतिमाह और 75 हजार रूपया वनटाइम देने का था। आज सीनियर सिटीजन का जो आयोग बना, उससे हर बुजुर्ग....जिस पार्क में जा रही हूं, जहां भी जा रही हूं लोगों की यही राय है की इतना धयान रखा गया। बच्चों के जन्म से लेकर बुजुर्गों तक का, एक परिवा रकी तरह हमारी सरकार ने धयान रखा। मैं इसके लिए भी अपने वित्तमंत्री जी का तहेदिल से स्वागत करती हूं और बधााई देती हूं। आज एक छोटी से छोटी समस्या जो हम सबके सामने आ रही हैं, कल एक साथी आये थे हमारे पास और वो बोले कि इस बार न बजट की धामाकेदार चर्चा मीडिया में नहीं चल रही है, हमने कहा कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल

पा रहा है। अगर हमारे विरोधाी दल अच्छा बतायेंगे तो उनकी चलेगा नहीं और विरोधाी दल को कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं जो इसबजट से वो क्या लें, किस बात पर चर्चा करें और क्या इसमें खामियां निकालें। तो ये सबसे अच्छी बात हमारी सरकार की बजट की रही जो एक-एक चीज को बारीकी से देखते हुए और उन्होंने इतना सिम्पल बजट की रही जो एक एक चीज को बारीकी से देखते हुए और उन्होंने इतना सिम्पल बजट जो एक आम आदमी को समझ में आता है और उसी तरह से मिनिमम वेज का जो हैं जो आज एक मजदूर भी इस बजट को देखने के लिए, सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है। रिक्शावाला भी इस बजट को देखना चाहता है कि इस बजट में मेरे लिए क्या है। ये पहली सरकार ऐसी है,आम आदमी की सरकार है कि इस बजट में मेरे लिए क्या है। ये पहली सरकार ऐसी है, आम आदमी की सरकार जिसके बजट को एक आम आदमी भी सुनना चाहता है, देखना चाहता है, जानना चाहता है जो कि हमारे लिए इस बजट में क्या है और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मैं अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, अपनी पूरी दिल्ली की ओर से और अपने पूरे क्षेत्र की ओर से बहुत-बहुत बधााई देती हूं अपने वित्तमंत्री जी को जो इस तरह का सिम्पल बजट हम सबके सामने रखा ताकि यह जन जन तक पहुंचाने में हम सबको गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बहुत-बहुत धान्यवाद, जयहिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : धान्यवाद। कर्नल सहरावत जी, मेरी प्रार्थना है आप दो दिन से अपनी सीट छोड़कर इधार बैठ रहे हैं। मैंने दो दिन ये संज्ञान में लिया, आज मुझे कहना पड़ रहा है कृपया अपनी सीट पर बैठें और सभी माननीय सदस्य इस चीज का धयान रखें। श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धान्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं अपने उप-मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी श्री मनीष सिसौदिया जी का बहुत-बहुत धान्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपनी अच्छी सूझ-बूझ के साथ जनता को धयान रखते हुए बजट पेश किया और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दो साल की भांति इस बार भी कर मुक्त बजट पेश किया गया है और एक और खास बात इस बार इन्होंने एक नई सोच दिखाई है, इस बार बजट को प्लान और नॉन प्लान से निकालकर तैयार किया है। इस वर्ष आउटकम बजट पेश किया गया है। इससे काम की निगरानी की बात बहुत अच्छी है। माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी द्वारा हर दिशा में जोर दिया गया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, पर्यावरण हो, पर्यटन हो, सुरक्षा आदि हो।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछले साल बजट दिया गया और काम हुए वे किसी से छुपे हुए नहीं हैं और इस बार भी बजट में 11300 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा, जो कुल बजट का 24 प्रतिशत है। विद्यालयों में नर्सरी कक्षा से दाखिला होना एक बहुत अच्छी सोच है। अब अभिभावक 14 वर्षों के लिए निश्चित हो जाते हैं कि हम एक बार एडमीशन करा कर 14 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं टेंशन फ्री हो जाएंगे। बच्चों के दाखिलों के लिए इसी तरह बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं को मधयाह्न भोजन की व्यवस्था करना, कंप्यूटर लैब बढ़ाना, शिक्षकों को कंप्यूटर टेबलेट्स देना, खेलकूद में बढ़ावा देना, स्वास्थ्य की तरफ भी पूरा धयान दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक बनाना, पालीक्लिनिक बनाना, टेस्ट फ्री करना, दवाइयां फ्री करना, ऑपरेशन की टाइम सीमा के बाद प्राइवेट अस्पताल करना बहुत अच्छा कदम है। सभी नागरिकों

को हेल्थ कार्ड बनवाने और हेल्थ बीमा देने की योजना बनाना और इस योजना के लिए 20 करोड़ रूपया प्रस्तावित करना ये सारी अच्छी सोच है। जो बच्चे गलत दिशा में भटक जाते हैं, उनके लिए नशामुक्ति केंद्र बनाना। स्वास्थ्य के लिए 5736 करोड़ का प्रस्ताव है उसका धान्यवाद करता हूं। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने जो गांवों के बारे में सोचा है, वह बहुत सराहनीय है। अब तक गांवों को इगनोर किया जाता था, मैं माननीय वित्तमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यमुनापार नार्थ-ईस्ट दिल्ली की तरफ थोड़ा विशेष धयान की जरूरत है। माननीय वित्तमंत्री जी ने बुजुर्गों, विकलांगों, विधावाओं के बारे में जो सोचा है, वह सराहनीय कदम है। अब तक जो पेंशन मिलती थी, वो लगभग डबल कर दी गई है। एमसीडी को पिछले साल लगभग 8000 करोड़ रूपये जिसमें से 50 हजार करोड़ नालियों के लिए दिये, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उसका हिसाब-किताब जरूर मांगा जाए। पूर्वांचलियों के लिए छठ घाट बनवाना, महिला आयोग को 20 करोड़ देना, महिला सुरक्षा देना बहुत अच्छा कदम है, मैं इस बजट के लिए बहुत-बहुत धान्यवाद करता हूं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : धान्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर बोलने का समय दिया।

कल हमारे माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली विधानसभा में 2017-18 का बजट पेश किया। इसमें अहम मुद्दा शिक्षा का रहा। इसमुं करीब 24 परसेंट बजट का हिस्सा शिक्षा के लिए रखा गया, उसके लिए मैं धान्यवाद करता हूं और मैंने पहले वर्ष में भी, जब शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, उस समय

भी धान्यवाद किया और मेरे यहां कमरे भी बनाये गये, उसका भी मैंने कई बार धान्यवाद किया मगर आज बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो दिल्ली में 500 स्कूल नये खोलने की बात कही किंतु दो साल बीत जाने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि कितने नये स्कूल बने क्योंकि मैं समझता हूं कि डिप्टी सीएम साहब इसको बनाना चाहते हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जो मैं समझ रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं कि जब 2013 के अंदर केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी की थी और वो एक लैंड बिल लेकर आये कि जमीन को जो एक्वायर किया जाता था, किसी भी सरकारी काम के लिए; चाहे एजुकेशन के लिए किया जाए, हॉस्पिटल के लिए या बारात घर के लिए या रोड के लिए, उस सब को एक्वायर करना बहुत टेढ़ा काम है और उसके बाद मैं समझता हूं शायद दिल्ली में किसी भी काम के लिए कोई जमीन एक्वायर नहीं की गई है। जब आपके पास जमीन नहीं होगी तो आप न स्कूल बना पाएंगे और न आप हॉस्पिटल बना पाएंगे और बड़े दु:ख के साथ कह रहाह ूं अध्यक्ष जी, आपके माधयम से कि ज मोदी सरकार ने लैंड बिल में संशोध ान करने की बात कही कि सरकारी काम हम नहीं कर पाएंगे, हम भारत का विकास नहीं कर पाएंगे और लैंड बिल में संशोधान होना चाहिए तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका विरोधा किया। आज मैं बड़े दुख के साथ यहां कह रहा हूं कि विकास के नाम पर कभी भी विरोधा नहीं करना चाहिए। आप बार-बार कहते हैं हम 67 हैं, विपक्ष के 3 हैं (450) मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि यहां बैठकर केवल मोदी जी को गोलियां देना या दिल्ली नगर निगम कारे गाली देना उससे आप 67 की संख्या आपकी रकरार रह जायेगी, मैं समझता हूं नहीं रह पायेगी। ये अभी आपने चार पांच महीने पहले दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में देख भी लिया है कि

तेरह में से आपको पांच सीट मिली। आज फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें 272 सीट दो, हम दिल्ली को लंदन बनायेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माधयम से कि बहुत लंबा टाईम नहीं है, दिल्ली में डेढ़ महीने के अंदर दिल्ली नगर निगम दोबारा रिजल्ट आने वाला है। मैं समझता हूं जो सपने देख रहे हैं वो पूरे होने वाले नहीं हैं।

मैं अपने कुछ विद्यालयों की तरफ डिप्टी सीएम साहब ऐजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उनको धयान दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधाानसभा के अंदर मैंने पहले भी कई बार कहा है, दिन में दो शिफ्ट लगती हैं। एक सुबह की पारी में दो शिफ्ट, शाम की में दो शिफ्ट। स्कूल में बच्चों को पानी पीने के नाम पर एक बूंद पानी नहीं है। पूरी विधाानसभा में और मैं कहूं कि करावल नगर जहां से हमारे जल मंत्री हैं, मैं उनके विद्यायल की बात कर रहा हूं, एक बूंद पानी का नहीं है। जब गर्मी होती है तो बच्चे स्कूल छोड़कर घर चले जाते हैं। पांच सौ स्कूल जो खोलने की बात कही गई, यदि उसका रेशियो देखा जाये तो 70 विधाानसभाओं में करी सात स्कूल एक विधाानसभा के अंदर आते हैं। दिल्ली में करीब 60 लाख की आबादी अनओथराइज बस्तियों के अंदर रहती है, जहां ना डीडीए की लैंड है, ना ग्राम सभा की लैंड है, ना एमसीडी की लैंड है। केवल या तो है तो केवल प्राइवेट लैंड है या जो स्कूल एक दो उस विधाानसभा के अंदर पहले बने हुए थे, वो हैं। हम जब तक जमीन का इंतजाम नहीं करेंगे जब तक कोई नीति नहीं बनायेंगे, हम शिक्षा का उद्देश्य दिल्ली में पूरा नहीं कर पायेंगे। मेरी आपके माधयम से से आग्रह है कि इस पर कोई ठोस नीति बनाई जाये कि जमीन का इंतजाम कैसे करेंगे। हम उसमें आपका बिल्कुल चौबीस घंटे धान्यवाद करेंगे, आपका साथ देंगे।

जहां तक हमारे करावल नगर का एक स्कूल है जिसमें पिछले वर्ष जब नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के रिजल्ट आये तो वहां लड़कियों ने आकर तोड़-फोड़ की, विरोधा किया क्योंकि केवल 30 प्रतिशत बच्चे वहां नौंवी क्लास और ग्याहरवीं क्लास में पास किये गये। आज हम रिजल्ट की बात करते हैं 85 प्रतिशत 95 प्रतिशत की। जब हम नौंवी क्लास में 70 प्रतिशत बच्चे फेल करके वहीं रोककर बैठा देंगे, तो रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छा हो जायेगा। आपकी तारीफ करूंगा, यदि नौंवी क्लास का भी रिजल्ट 80 परसेंट आये, 90 परसेंट आये तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी मेरे कई साथी कह रहे थे, सरिता जी चली गई हैं कि सरकारी स्कूल में जाता कौन है, सरकारी अस्पताल में जाता कौन है। मैं भी समझता हूं कि वहां गरीब आदमी जाता है। सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी जाता है। स्कूल में गरीब आदमी जाता है जसके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यहां आम आदमी के 67 विधाायक हैं, क्या किसी एक विधाायक के बच्चे सरकारी स्कूल मेमं पढ़ते हैं? जरा बता दें हाथ खड़ा कर के।

....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : चलो एक का धान्यवाद इनका और कितनों के बच्चे पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते? कि वहां शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बातचीत नहीं प्लीज।

....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बातचीत नहीं।

....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : मैं जब नगर निगम का सदस्य 10 साल रहा तो उस समय भी मेरे यहां स्कूलों की कमी थी।

....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : आपी जब बारी आये तो आप खूब बोलना, मैं मना नहीं करूंगा आपसे और ना मैं बीच में टोकता किसी को। जब मैं नगर निगम का सदस्य था तो मेरे स्कूल वालों ने....एक कालोनी थी वहां पर श्रीराम कालोनी....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बातचीत नहीं आपस में प्लीज।

....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : वहां करीब 80 परसेंट मोहम्मडन आबादी थी, उस वक्त उस कालोनी में। वहां एक भी स्कूल नहीं था और वहां कोई जमीन भी नहीं थी। शांति देसाई जी उस समय हमारे मेयर थे तो मैंने उनके पास कई बार स्कूलों का मुद्दा उठाया। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको धान्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस समय बगैर किसी परमीशन के श्रीराम कालोनी के अंदर 28 कमरों का निर्माण कराया। डीडीए की लैंड पड़ी हुई थी, परमीशन मिली और उठाकर उस पर स्कूल चालू करवा दिया, जो आज मिश्रा जी के एरिया में चल रहा है, बिना परमीशन के। हां, मैं आज भी कह रहा हूं

बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि आदमी में काम करने की क्षमता होनी चाहिये।

....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : जरा भईया, सुन लो। दिल्ली की जनता ने हमें भेजा है तो मुझे उनकी बात कहने दो आप।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, इधार बात करिये।

श्री जगदीश प्रधान : आप सहमत हैं क आज दिल्ली में पूरे स्कूल हैं....

....(व्यवधान)

श्री जगदीधा प्रधान : आप कह रहे हो इसलिये मैं देख रहा हूं आपकी तरफ कोई देखने का शौक नहीं है मुझे।

....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : तो अध्यक्ष जी, करावल नगर स्कूल की बात करूंगा मैं आपके सामने। जहां पहली शिफ्ट के अंदर करीब साढ़े छह हजार लड़कियां हैं सढ़े छह हजार लड़कियों में....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई, बीच में नहीं प्लीज।

....(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : साढ़े छह हजार लड़कियों में से तीन शिफ्ट लगती हैं यानि डेढ़-डेढ़ घंटा शिफ्ट चलती है और उस विद्यालय के अंदर नवासी सैक्शन हैं और हर सैक्शन में 80 बच्चे से ऊपर बच्चे पढ़े हैं और वहां कमरों की संख्या क्या है? आठ पक्के कमरे हैं और 9 कमरे टीन शेड में चल रहे हैं यानि साढ़े छह हजार बच्चों पर जहां केवल 17 कमरे हों, वहां आप सोच सकते हो कि 95 परसेंट रिजल्ट आ जायेगा? डेढ़-डेढ़ घंटा बच्चों को पढ़ने को मिलता हो, मैं उसी स्कूल की बात कर रहा हूं कि जिसमें बच्चों ने तोड़-फोड़ की थी पिछले वर्ष। ये माननीय मंत्री जी के एरिये का स्कूल है और मेरा वहां रेजीडेंस है तो सर, मैं आपके माधयम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को आप निर्देश दें कि कोई ऐसी नीति बनायें कि जहां स्कूलों की संख्या कम है, वहां कोई अलग से, कोई स्पेशल बजट रखकर, वहां जमीन खरीदकर वहां स्कूल बनाये जायें। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। मैं कोई राजनीति करने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं जो पीड़ा है, वो आपके सामने बयान कर रहा हूं।

परिवहन व्यवस्था, आपने नई बसें, कलस्टर बसें खरीदने की बात कही। पिछली बार भी मैंने ट्रांसपोर्ट का मुद्दा उठाया। मेरे यहां 20 साल से एक डिपो बना हुआ है करावल नगर में। जो आज मिश्रा जी के एरिया में है। पहले हमारी एक ही विधाानसभा होती थी तो उसमें जब ये ऑड इवन चला पीछे तो मैंने वहीं चौक पर बैठकर देखा बसों की हालत क्या है। बसें बहुत लगाई गई। गोपालराय जी ने बहुत बसें लगाई बाकी बस में एक भी सवारी न वहां पर उतरती थी, न वहां से चढ़ कर जाती थी। आप कहेंगे बस हमने तो भेजी थी। सवारी क्यों नहीं गई? क्योंकि वहां से भजनपुरा तक तीन किलोमीटर है। वहां से भजनपुर एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है। पांच रूपये बस

में देने हैं। पांच रूपये में ही आटो में बैठकर 15 मिनट में पहुंच जाते हैं तो गोपाल राय जी ने धान्यवाद दिया था कि जब भी हम मिनी बसें लेकर आ रहे हैं सबसे पहली बस चलेगी तो आपके करावल नगर क्षेत्र में चलेगी वो सपना रह गया।

मौहल्ला सभा की पीछे बात हुई कि मौहल्ला सभाओं द्वारा बीस-बीस करोड़ रूपया 11 विधाासभाओं में दिया गया। क्या उनसठ विधाानसभाओं के लिए कोई पैसा दिया गया? स्वराज बजट की बात कही गई। क्या वो आज बजट में दोनों चीज गायब हो गई? वाई फाई गायब हो गया? पानी जिंदगिी के लिए बहुत अहम चीज है। आप बात कर रहे हैं कि 24 घंटे टूटी खोलो और हम पानी देंगे। मैं आपके माधयम से याद दिलाना चाहता हूं कि करावल नगर विध ाानसभा, मुस्तफाबाद विधाानसभा और मेरे दूसरी तरफ गोकुलपुरी विधाानसभा जो बिल्कुल बहुत ही कम फासले पर है, (500) अभी भारती जी बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि मेरे यहां दो टाइम पानी दे दिया जाए। मुझे अभी याद आया कि भारती जी दो टाइम मांग रहे हैं, मेरे यहां तो चौथे और पांचवें दिन पानी आता है। आप कहीं भी जाकर पता कर लो, चौथे पांचवें दिन पानी आता है, वो भी एक टाइम। पानी, टूटी खोलकर तो बहुत सपने की बात है। आप कहीं भी जाकर पता करा लें, स्कूलों में पानी की ये हालत है।

दूसरा, ट्यूबवैल लगवाए हैं। ट्यूबवैल के लिए भी मैंने प्रार्थना की थी कि प्रदूषण फैल रहा है इलाके में। लोगों ने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। कैमिकलस का जो गंदा पानी निकलता है, वो सारा जमीन में जाता है और जमीन में से जब पानी हम निकाल कर पीएंगे तो बीमारी बढ़ती है। उस पर भी कोई धयान नहीं दिया गया।

अगला सर, यमुना की सफाई की बात हुई। आप शायद यहां बस अड्डे से निकलकर घर जाते हो और यमुना के किनारे पर लोग सब्जी बेचते हैं, यदि कोई आदमी 6 महीने उस सब्जी को लगातार खा लेगा तो हॉस्पीटल से पहले रूकेगा नहीं। क्योंकि यमुना के अंदर जो पानी है, आज वो एक बहुत ही कैमिकल का, सड़ा हुआ, मैं कहूं इतना प्रदूषित पानी है, जिससे वो सब्जी उगाई जाती है। तो मैं आपके माधयम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम जब तक यमुना की सफाई ना हो, वहां पर सब्जी लगाना बैन कर दिया जाएं ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब न हो।

अध्यक्ष महोदय, पानी की बहुत दिक्कतें हैं। मेरे तो पूरे क्षेत्र में दिक्कत है। मैंने अभी 4 ट्यूबवैल लगवाए हैं, 4 ट्यूबवैल का पानी भी पीने योग्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी 2-3 ये बातें थी, वो आपके सामने रख दी हैं। इन पर अगर गौर किया जाए तो बहुत-बहुत धान्यवाद, जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : श्री वेद प्रकाश जी। एक मिनट पहले माननीय मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन के अगले क्रम में जब बजट पर जवाब देने का आएगा तो दूंगा लेकिन एक थोड़ा सा फैक्ट इन्होंने सदन के समक्ष रखा जो मुझे लगता है, उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंि जब रिकार्ड में इन्होंने एक ओवजर्वेशन दिया, बाकी सब बजट से संबंधाी सारी बातों का और दिल्ली से संबंधित सारी बातों का जवाब, मैं अपनी चर्चा में, जब जवाब देने का क्रम आएगा तो दूंगा लेकिन आपने एक बिल का नाम लिया कि केंद्र सरकार के एक बिल का विरोधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया,

बिल्कुल किया और आज सदन में ऑन रिकार्ड फिर से उसका विरोधा करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि आज जिस लैंड बिल की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, जगदीश भाई वो लैंड बिल आज भी पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के सामने पैंडिंग है और सको अरविंद केजरीवाल रोककर नहीं बैठे हुए, जो ज्वाइंट कमेटी है उसको हेड किया था एस. एस. आहलुवालिया साहब ने जो कि अब मोदी सरकार में मंत्री हैं और आहलुवालिया साहब के जो ओब्जर्वेशन हैं, मोदी सरकार में मंत्री जी के जो ओब्जर्वेशन हैं, उस बिल पर जिस बिल का हमसे समर्थन चाह रहे हैं या उन्हें आपत्ति है कि हमने उसका विरोधा किया, नहीं तो दिल्ली में पता नहीं कितनी जमीन आ जाती! उसमें उस पालियामेंटरी कमेटी ने कई खामियां पाई। एस. एस. आहलुवालिया साहब की कमेटी थी। वो कमेटी, अभी उस कमेटी के उस वक्त के चेयरमैन भी इस केंद्र सरकार में मंत्री है, उन्होंने उस बिल में कई सारी खामियां पाई और उन खामियों के बेस पर वो बिल अभी वहां रूका हुआ है, ज्वाइंट कमेटी के पास रूका हआ है। वो हमारी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के कहने से लैंड बिल रूक जाएगा, ये नहीं है और समर्थन करन `से पास भी नहीं हो जाएगा। लेकिन वहीं मोदी सरकार के फैल्योर की वजह से वो रूका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने बिल एक खामी भरा बनाकर के दिया। इंट्रस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि जो इसकी कमियां थीं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत उसका रिकार्ड है और मेरा इंट्रेस्ट भी रहा है उसमें। इंट्रेस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि मोदी सरकार इस पर दो बार ऑडिनेंस लेकर आई If I am not wrong, may be शायद दो बार या तीन बार....तीन बार, ऑर्डिनेंस लेकर आई लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने ऑडिनेंस लाना भी बंद कर दिया। क्योंकि ऑडिनेंस लाने के बावजूद देश में इस सो कॉल्ड अच्छे बिल के तहत लैंड एक्वीजिशन

हो ही नहीं सका। तो मोंद सरकार जो बिल लेकर आ रही है, उसके तहत देश में किसी एजेंसी, किसानों का तो छोड़ दीजिए, किसानों का तो क्या भला करेंगे ये लोग! लेकिन देश में जिन एजेंसीज को जमीन चाहिए, उन एजेंसीज का इंट्रेस्ट भी नहीं है कि वो जमीन एक्वायर कर लें, उस एक्ट के तहत। तो इसलिए वो एक्ट बहुत खराब एक्ट है। मैं बिल्कुल अपनी सरकार की ओर से, भारत के नागरिक होने के नाते, अपनी पार्टी की ओर से भी इस बिल का विरोधा करता हूं और आगे भी करूंगा और हमारा विरोधा तो छोड़िए, हमारा विरोधा तो सिम्बॉलिक है, आपकी पार्टी की ज्वाइंट कमेटी कर ले, बहुत-बहुत बड़ी बात है।

अध्यक्ष महोदय : वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : माननीय अध्यक्ष जी धान्यवाद, आपने मुझे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आज्ञा दी।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये दिल्ली का बजट पेश किया माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसौदिया के द्वारा, यह बजट सभी मानवीय पहलुओं को देखते हुए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से एक अनोखा बजट है, जिसके लिए मैं दिल्ली सरकार को हृदय की गहराइयों से धान्यवाद करता हूं और बजट के बारे में मेरे सभी साथी अपने-अपने तरीके से चर्चा कर चुके हैं, सभी पहलुओं पर रोशनी डाल चुके हैं। कल जब मनीष जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो बैठे-बैठे मुझे एक बात याद आई जब गांव में 2 साल पहले वर्षा के कारण फसल खराब हुई थी तो गांव के लोग मेरे पास आए कि हमें कम से कम अरविंद केजरीवाल जी से 5-6 हजार रूपये बीज और खाद के तो दिलवा दो कम से कम। तो

मैं मुख्यमंत्री जी के पास आया। मैंने कहा गांव के लोग तो 6 हजार रूपये कह रहे हैं आप 11-10 हजार रूपये कर दो। तो अरविंद जी ने मुझे कहा कि बेवकूफ बच्चे 10 हजार में कैसे काम चलेगा उनका! नीयत की बात बता रहा हूं भाईसाहब, हंसना बड़ा आसान है जो जाब हो वो बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वो किसान और उसका परिवार अगली फसल तैयार होने तक 3 महीने तक रोटी कहां से खाएगा। मैं उनको प्रति एकड़ 20 हजार रूपये के मुआवजे का एलान करूंगा। तो उकसे बाद बजट को कल सुना, देखा और पढ़ा। मैं जयादा न कहकर एक ही बात कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था, पिछली सरकारों ने चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो उसके लिए कुछ करना तो दूर की बात है, कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं। अभी त्यागी जी ने कहा कि आगे बैठने वालों को तो आराम से सुनाई देता है लेकिन आवाज और नीयत उसी को कहते हैं जो बिल्कुल आखिरी छोर वाले को सुनाई दे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा विधायक हूं जो बिल्कुल दिल्ली के बार्डर से आता हूं। बवाना विधान सभा से। दो-दो, तीन-तीन बार्डर लगते हैं। पिछले 20 सालों से हमारे देहात की तरफ दो-दो, तीन-तीन फुट के गड्ढे थे और आरडीी का बजट देना तो दूर की बात, एक बारी मैं गांव के लोगों के साथ शीला दीक्षित के पास कुछ समस्याएं लेकर आया था। किसानों की समस्याएं थी, गांव के लोगों की। शीला दीक्षित ने क्या कहा कि बवाना कौन सी कॉलोनी है! दिल्ली की मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता था कि गांव बवाना कॉलोनी है कि गांव है और ये कहा कि क्या वहां खेती भी होती है। तो बड़े विडम्बना और शर्म की बात थी उस सरकार के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कि बजट में चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं, अपनी आत्मा से कह रहा हूं जो आरडीबी बजट

का 2 सालों से पुनर्गठन किया गया है। (510) वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि बहुत ही छोटी राशि 125 करोड़ से बढ़कर 6 सौ करोड़ रूपये किये हैं, न तो मेरे पास धान्यवाद के लिए शब्द है, न ही मैं कर सकता हूं। मेरे गांव के लोग हर बार कहते थे कि भई, गांव का कुछ तो हो, गांव की तरफ कोई तो देखे। उनका मनोबल भी टूट चुका था। एक किसान जिसका परिवार पूरे साल फसल के लिये अपने आप को गला देता है, लेकिन आखिर में उसकी फसल खराब हो जाती है। उसको कुछ नहीं मिला। ये हर बार होता था। मेरी-मेरी याद में 20-25 साल में ये 10-20 बार हो चुका है, लेकिन मैंने अरविंद जी के बारे में सुना था जब मैं ब ीजेपी मेमं था जो मजदूरों के बीच में रहे, झुमग्गियों के बीच रहे हैं, हर दर्द को उन्होंने सहा है, हर दर्द को उन्होंने देखा है। फिर वही बात है 'जाके पैर के ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पराई।' कहां तो मोदी जी, हर रोज जाज में घूमते रहते हैं, कहां शीला जी एयरकंडीशन में बैकर दिल्ली को चला हरी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल क कारण, माननीय मनीष सिसौदिया जी के कारण जो आज गांव के लोगों का मनोबल बढ़ा है, आज उन्हें इच्छा शक्ति मिली है।

सुबह 10 बजे के आसपास दरियापुर गांव से कुछ लोग आये। मनीष जी को और अरविंद जी को मैंने कहा कि भई बजट पेश हो गया है और गांव के लिये 925 करोड़ रूपये का प्रावधाान है तो अरविंद केजरीवाल जी को गांव के लोग लाला जी कहते हैं, जी, बोले हां भई लाला जी तो धााकड़ छोरा है, जो वास्तविकता थी, बोले लाला जी तो छोरा धााकड़ है ये बीजेपी वाले तो उएं पीछे पड़े रहै हैं। ये गांव के लोगों की अपनी जबान थी जी, वो भाग ही जायेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है बैठने की। मैं उनमें 20 साल रहा हूं उनमें दम न तो था, न होगा। तो मैं आम आदी पार्टी सरकार के दूरदर्शी

नेतृत्व की, दिल्ली से हटकर गांव के बोर्डरों तक जाने की और इस बजट को पेश करने की, गांव का मुख्य रूप से धयान देने के लिए हृदय की गहराईयों से नमन करता हूं और मनीष जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

शिक्षा के क्षेत्र में, मनीष जी तवज्जो चाहूंगा, ''जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। धान्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह : धान्यवाद अध्यक्ष जी, दिल्ली के हरेक वर्ग को ध यान में रखते हुए दिल्ली के एक-एक आम आदमी की जरूरत को, उसके हित को, उसके हक को धयान में रखते हए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरपरस्ती में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने कल केंद्र सरकार की तमाम अड़नों के बाद; कभी सीबीआई, कभी दिल्ली पुलिस, अलग-अलग तरीके के तमाम अड़चनों के बाद जो काबिले तारीफ बजट पेश किया है, क्योंकि वेद प्रकाश भाई ने एक शेर से अपनी बात खत्म की तो मेरे को भी एक शेर धयान आ गया कि 'गुरूरे वक्त तुझे ये बात कौन समझाये, वो सर झुक नहीं सकते जिन्हें कट जाना आता हो।' ये एक मिसाल पेश की है इस बजट ने कि जितनी मर्जी आप अड़चनें डाल लो, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मकसद, जो उद्देश्य ये सरकार लेकर आई है, ये सरकार उस पर चलती रहेगी।

अध्यक्ष जी, बात चाहे कल के बजट भाषण में एन्वायरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बबूल के पेड़ों को हटाकर, दूसरे कीकर के पेड़ों को हटाकर अच्छे फलों वाले पेड़ों को लगाने की हो या उस कहावत की हो कि 'बोया पेड़ कीकर का तो आम कहां से खाये। एक तो वो कीकर के पेड़ लगे हैं जो पूरी दिल्ली

के पानी को सुखाएं जा रहे हैं, विदेशी पेड़ और एक वो विदेशी नीतियां जो अंग्रेज बना के गये थे, जिन्होंने आम आदमियों का जीना मुश्किल कर दिया था। उन नीतियों के विरूद्ध, उन नीतयों के उलट आम आदमियों के हित में इस बजट को पेश करने की बात हो, मेरे को याद है अरविंद केजरीवाल जी की बात जब चुनावी भाषणों में रखते थे तो वो कहते हैं कि विकास खाली फ्लाई ओवर नहीं होते, फ्लाईओवर चार कम बना लेंगे पर अगर बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छी हैल्थ सिस्टम डेवलप कर लिया, तो 400 फ्लाई ओवर बच्चे अपने आप बना देंगे। उसी को पूरी तरह से मूर्त रूप देते हुए आज सरकार का ये बजट आया है ।ऐरअ गर हमने दिल्ली के एक-एक निवासी को ये बेफिक्री दे दी कि किसी को भगवान न करे महंगा इलाज कराने की नोबत आगई तो किसी बहन को, किसी माता को अपने गहने बेचकर इलाज कराने की जरूरत नहीं आएगी। आज दिल्ली के हैल्थ सिस्टम में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर सरकारी अस्पताल में नंबर हनीं भी आ रहा तो प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज किया जाएगा, इसका खर्चा सरकार उठाएगी।

अध्यक्ष जी, वो विदेशी सिस्टम कुछ ऐसा था कि सारा का सारा कमर्शियलाइजेशन हो गया था, डॉक्टर साहब चाहते थे कि सारे मरीज बन जायें, वकील चाहते थे सारे झगड़ालू हो जायें, तांत्रिक बाबा चाहे थे कि सारे भूत-प्रेतों में विश्वास करने लगें तो सरकार की जिम्मेवारी थी, इससे निकाला जाये। नेता जो आज तक आम आदमी पार्टी के पहले वाले नेता थे, वो ये चाहते थे कि सारे अनपढ़ के अनपढ़ रहें। जैसे नितिन भाई ने अपनी बात में बताया कि पढ़ गये तो सब समझ में आ जायेगी फिर हमारे को कौन पूछेगा। तो खास तौरसे बधाई देना चाहता हूं कि अब तो आंकड़े भी सामने हैं कि देश की

17 स्टेटस जो टॉप की स्टेटस है, उनके आंकड़े हैं कि एजूकेशन पर पिछले सानल 16-17 फाईनेंसिएल ईयर में किसने कितना पैसा खर्चा है, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है यह बताते हुए कि दिल्ली 17 राज्यों में नम्बर वन राज्य है जिसमें एजूकेशन के ऊपर 22.9 प्रतिशत पैसा खर्चा गया है। बार-बार अरविंद भाई बताते हैं कि कम्पेयर कर लो जी, दावे के साथ कहते हैं। आज वो एमपी जहां पर आपकी 10 साल से सरकार है, उनका चैक कर लो। उनका सिर्फ 16.6 प्रतिशत है नीचे से तीसरे नम्बर पर है। उसके बाद आप बात कर लो हैल्थ सिस्टम की, हैल्थ सिस्टम में 17 राज्यों के आंकड़े आपके सामने है इन 17 राज्यों में दिल्ली 11.2 के साथ पहले नंबर पर है। आप बात कर लो अपने छत्तीसगढ़ की, वो इसके हुत पीछे है। नीचे से दूसरे-तीसरे को लेते हुए सिर्पु 5.6 जिन्होंने हैल्थ के ऊपर खर्चा है। तो आंकड़े सामने हैं। अभी बहुत सारे लोग आते हैं अध्यक्ष जी, बताओ जी, किया क्या है। तो जब पूछते हैं एजूकेशन में क्या हुआ तो दूर नहीं जाना पड़ता। अपनी विधाान सभा के अंदर डिस्ट्रिक्ट सैंटर के अंदर मॉडल स्कूल हैं, वहां ले जाते हैं, देख लो जी, दिल्ली के किसी प्राईवेट स्कूल के साथ कम्पेयर कर लो, उससे बढ़िया ही मिलेगा। कोई पूछता है कि हैल्थ में क्या किया तो पिछले दिनों दिल्ली स्टेट ऑफ कैंसर इन्स्टीट्यूट गया अध्यक्ष जी, हां मेरे सथ कुछ लोग थे, गया तो किसी पेशेंट को देखने था पर देख के अपनी आंखों से यकीन नहीं हुआ जब वहां से जो फोटो खींच के डाली तो उसके बाद बड़े-बड़े मीडिया वाले पहले दिखाते नहीं थे, वो सब हैरान हो गये। मेरे को अपने किसी साथी का फोन आया, ''सही में, ये असली फोटो है ना! मतलब इतना काबिले तारीफ काम दिल्ली के हैल्थ सिस्टम में हुआ पड़ा है। चाहै हैल्थ की बात कर लें, चाहे एजूकेशन की बात कर लें। कोई पूछता है कि जी, बुजुर्गों के लिये क्या किया

है तो तिलक नगर की खुशनसीबी है कि मोहल्ला सभा के पायलेट प्रोजेक्ट में रखा गया है। वहां बुजुर्गों ने आकर बोल दिया कि बुजुर्गों के लिये कोई बैठने की जगह नहीं है तो सीनियर सिटिजन सैंटर का अभी पायलेट प्रोजेक्ट तिलक नगर में बनाया है जिसमें बड़ा एयरकंडीशंड हॉल बुजुर्गों के लिये बनाया है, फिजयोथैरेपी है, लाइब्रेरी है, कैरमबोर्ड के एयरकंडीशंड हॉल बुजुर्गों के लये बनाया है, फिजियोथैरेपी है, लाइब्रेरी है, कैरमोर्ड के एयरकंडीशंड रूम है। दुनिया भर की फाइल स्टार फैसिलिटी जो कभी विदेशों में होती होंगी, वो सारी आज तिलक नगर के सीनियर सिटिजन रिक्रेशन सैंटर में मौजूद है। वो सब इसी स्वराज बजट के माधयम से उपलब्धा हुई है और कोई बोलता है और सुरक्षा के लिये क्या किया तो आज बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि 50 प्रतिशत तिलक नगर को हमने गेटों के साथ कवर कर दिया है। ये तभी मुमकिन हो पाया कि मोहल्ला सभा प्रोजेक्ट के तहत हमें बजट दिया गया है। ये तभी मुमकिन हो पाया कि मोहल्ला सभा प्रोजेक्ट के तहत हमें बजट दिया गया जिसमें अप्रूवल पहले से था कि जो उस सभा के अंदर पब्लिक ने बोल दिया, वो फाईनल है। इस तरीके के काम इस बजट में रखे गये हैं। जो लोगों ने बोलना है, वो तो अध्यक्ष जी बोलते रहेंगें। बचपन में स्कूल में दो लाईनें सुनते थे 'इंसाफ की डगर पे बच्चो दिखाओ चलके, ये देश तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के' तो इसको सुन-सुन के एक दो गलत नेता भी बन गये। उन्होंने इसके मतलब ही दल दिये। वो आजकल कहते हैं 'श्मशान की डगर पे वोटर दिखाओ चलके, श्मशान है तुम्हारा मुर्दे तुम्हीं हो कल के' जो बात करते हें खाली मरने मारने की, उनको सिर्फ यही आता है और एक तरफ बात विकास की होती है तो सारे तथ्य सारे फैक्ट आपके सामने हैं। मैं तिलक नगर के सभी क्षेत्र वासियों की तरफ से, पूरी दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी

को इस काबिले तारीफ बजट की बहुत-बहुत बधाई देता हूं और धान्यवाद करता हूं कि इसी तरीके से आप लगे रहें :

''ये राहे ले ही जायेंगी सुनहरी मंजिलों तक

कभी सुना है कि अंधोरों ने सेवरा होने न दिया हो।'

बहुत-बहुत धन्यवाद, इन्कलाब जिन्दाबाद। (520)

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा कल होगी। लेकिन कुछ माननीय सदस्य किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। मैं चीफ व्हिप जगदीप जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि चार-पांच सदस्य....मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कल उनके नाम चर्चा में जरूर आएंगे। तो एडवांस में अपनी तैयारी करके आएं। बहुत कम वो भाग लेते हैं कभी कभार....नहीं हो गया महेंद्र जी, बस प्लीज। अब एमसीडी पर चर्चा हम आरंभ कर रहे हैं। आदर्श शास्त्री जी।

विधायक निधि के बारे में नगर निगम पर चर्चा

श्री आदर्श शास्त्री : बहुत-बहुत धान्यवाद अध्यक्ष जी, आपने ये मौका दिया। जो दिल्ली में आज एमसीडी की वजह से पूरी दिल्ली की जनता, बुरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। यहां पर हम लोग, सभी विधायक उसी बात को लेकर परेशान हैं क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। ये जो एक विशाल बहुमत आम आदमी पार्टी को जो विश्वास दिल्ली की जनता ने दिया था, वो विश्वास इस बात का था कि दिल्ली को हम लोग बदल पाएंगे। रहन-सहन लोगों का, जा रोजमर्रा की जिंदगी, जीवन व्यापन में समस्याएं उठती हैं, उससे उनको कुछ आराम मिलेगा। उस रास्ते की एक सबसे बड़ी सीढ़ी की बजाय, आज कांटा बनकर एमसीडी और एमसीडी का भ्रष्ट काम करने का तरीका आज आ गया है।

मैं अध्यक्ष जी, बताना चाहता हूं इससे पहले कि मैं दो मिनट आपका समय लूं और बताऊं ''ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल जो करप्शन इंडेक्स को मेजर करती है ग्लोबली पुरी दुनिया में मेजर करती है। ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल ने वर्ष 2012, 2013 व 2014 तीन सल जो सिविक बॉडीज होती हैं, उनका भी असेसमैंट किया था और मैं आपके माधयम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि इन तीनों वर्षों में दुनिया में 88 नगर निगमों का उन्होंने आंकलन किया। उसमें से तीनों वष्र दिल्ली की एमसीडी सबसे भ्रष्ट नगर निगम पूरे दुनिया में पाई गई। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का एक झूठ है, इन लोगों के माधयम से आया।

अध्यक्ष जी, हम लोग सब जानते हैं कि कई बार एमसीडी में, एमसीडी कमीश्नर से मुलाकात की, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की, कई और अधि ाकारियों से मिलें। बात अधिाकारी सुन लेते हैं। कहते हैं, इस पर काम होगा। मगर उसक बाद आज दो साल के बाद भी काम नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अलग-अलग जगह विधाायक निधि से एमएलए फंड से डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा लगाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मेरी अपनी विधाान सभा में लगभग 8 करोड़ में से 3 करोड़ रूपये एमएलए फंड का वो एमसीडी के द्वारा कराये जाने वाले कामों के लिए दिया गया है जिसमें ओपन जिम, सड़क, ड्रेन कई चीजों के निर्माण हैं और दो वर्षों में उन ढाई करोड़ के काम में ऐसा कोई कारण एमसीडी के कमिश्नर बता पा रहे हैं, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर नही बता पा रहे हैं कि ढाई करोड़ के काम में पिछले दो साल में एक काम भी जमीनी स्तर पर अभी खत्म नहीं हुआ है। दो साल के अंदर ढाई करोड़ रूपये में से एक भी काम, कई कामों के टेंडर

हो चुके हैं, कई अवार्ड हो चुके हैं, कभी ठेकेदार नही आता है, कभी जेई नहीं आता है तो कभी इंजीनियर नहीं आता है। तो ये साफ है कि जब इन लोगों से बात है कि हम लोगों को काम नहीं करने दिया जाता, हम लोगों को रोका जाता है। मैं एक और उदाहरणअपनी विधाान सभा का जरूर आपको दूंगा मेरे यहां से कुछ कार्यकर्ता जो वहां के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, उसके दफ्तर गए, एमसीडी के। तो हालत ये है कि वो सुपरिटैंडिंग इंजीनियर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था, सामने बैंच पर बैठा था अपने चैम्बर में और उसकी उसकी टेबल पर पैर रखकर बीजेपी का पार्षदबैठा हुआ था। ये सच्चाई है एमसीडी में जो ाष्टाचार है और इसकी समस्या से हम लोगों को दिल्ली को निजात दिलाना है। आज सच्चाई ये है कि चाहे मैं एमसीडी कमिश्नर के पास गया हूं, चाहे मेयर के पास गया हूं, कहीं पर भी सिकी काम को दिल्लीवासियों के लिए कोई रास्ता आगे निकले, उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता। हर बार कोई न कोई बात पर रोकाजाता है। जहां पर सीवर का काम चल रहा है, जहां सीवर डालने की बाद सड़क बनाई जानी चाहिए, वहां भी सड़क पर काम पहले ही शरू कर दिया जाता है। वहां के निवासी आते हैं, विध ाायक के पास आते हैं कि भाई साहब, यहां पर यह काम अभी सीवर डाल जाए तब होना चाहिए। उसके बाद भी नगर निगम या निगम पार्षद काम करवा रहा है। ये गलत है। ये टैक्स के पैसे का दुरूपयोग है, वेस्टेज है। उसके बाद भी यह काम कराया जा रहा है। केवल छोटी राजनीति के लिए! भ्रष्टाचार की सीमा इतनी है कि एमसीडी का स्कूल हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे उनकी प्राथमिक जो स्वास्थ्य संबंधित जिम्मेदारियां हैं, उसकी बात करें, शिक्षा की बात करें। यहां तक कि कोई अपना मकान बनाना चाहता है। हर एक काम में हर एक बात में घोर भ्रष्टाचार है और ये हम लोग आज सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माधयम से यह अनुरोधा है कि इस सदन को ये हम लोग ये बताने की कोशिश करें दिल्ली की जनता को कि इस तरह से सदन में हम लोग जो बात उठा रहे हैं, एमसीडी उस काम को, दिल्ली की जनता के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। निगम पार्षद रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर को मेयर को आप सदन में बुलाएं और उनसे यह पूछा जाए कि ऐसा क्या कारण है कि एमएलए फंड से जो विकास कार्य अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग विधाान सभा मे होना है, उन सब कार्यों को किस वजह से रोका गया है। ऐसे क्या कारण हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो काम विधाान सभा में दो-दो साल से अभी तक नहीं हुए हैं। इसकी जानकारी सदन को, एमसीडी के जितने भी आला आफिसर्स हैं, वो या मेयर आकर यहां सदन में दें। एक बार फिर बहुत-बहुत धान्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : सरिता सिंह जी। अखिलेश जी, आप बोलना चाहते हैं तो आप लिखकर भेज दीजए ना। स्लिप लिखकर भेजें मेरे पास। मैं नाम लूंगा तब। सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंह : धान्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने जो एमसीडी पर आज ये स्पेशल जो एमएलए फंड को लेकर आज बहुत सारे विधाायकों ने अपनी बात रखी थी कि एक सैशन होना चाहिए कि किस तरह से बजट होने के बावजूद भी....मतल हम एक तरफ ाज पूरी चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने बजट दिया और हम सब के पास कम से कम चार-चार करोड़ तो हैं ही जिसमें हम काम कर सकते हैं जिससे हम अपने क्षेत्र की जो

छोटी-छोटी रिक्वायरमेंट हैं, एमएलए लैड का मतलब ही यह होता है कि हम छोटे-छोटे रिक्वायरमेंट जो अपने एरिया में है, उसको हम सॉल्व कर पाएं। पर इसमें पिछले दो सालों में एमसीडी ने परेशानी क्रिएट की है। दो-तीन बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो मैं अभी सदन के सामने रखना चहूंगी कि क्या हम से पहले कोई विधाायक नहीं थे या हमसे पहले कोई सरकार नही थी? ईडीएमसी ने एक तरीके की कमिशनखोरी शुरू की है। यह आपके विधाान सभा में है शायद ईडीएमसी की सारी विधाान सभाओं में ये दिक्कत आ रही है कि पांच प्रतिशत वो सर्विज चार्जेज के नाम पर मांग रहा है। यानि अगर कोई गली का एस्टीमेट बना है, अगर वो पांच लाख का है तो उसमें पहले पांच प्रतिशत उनको दो। मतलब खुले आम करप्शन और कागज में करप्शन कि पहले वो पांच प्रतिशत दो तब उसका वर्क ऑर्डर होगा। ये तो जबरदस्ती है और आज तक ये कानून नहीं था। अचानक जब हम सरकार में आएं तो ये कानून बन गया और पांच प्रतिशत की वजह से हमारे कामों को रोक दिया गया कि पांच प्रतिशत जब तक जमा नहीं हो, जब तक पांच प्रतिशत नहीं कटैगा तब तक आपका वर्क ऑर्डर नही किया जाएगा। उसमें यूडी को हारकर वो पांच प्रतिशत वाला प्रोविजन एक्सेप्ट करना पड़ा जब कि ये कम्पलीटली इल्लीगल है। इस पर कोर्ट में कारवाई होनी चाहिए। ये कौन सी पॉलिसी के तहत वो पांच प्रतिशत ईडीएमसी ने लागू करवाया है? और यहां पर यह खत्म नहीं होती है बात। मैं यहां पर पांच-छः गलियों को....वैसे अगर मैं इस साल की बात करूं तो मेरी साइ गलियां बननी हैं, जिसका पैसा मतलब यहां पर कुछ भई साहब ये बोल रहे हैं कि आठ करोड़ में से तीन करोड़। मैं ये कह रही हूं कि मेरे दो साल के आठ करोड़ में से 7 करोड़ रूपया ईडीएमसी के पास है क्योंकि पूरी की पूरी विधाान सभा में डेवलपमेंट वर्क होना है, वह ईडीएमसी से होना

है। चाहे लाईट लगवाना हो, चाहे सड़क बनवाना हो, चाहे कोई सा भी काम हो, जल बोर्ड के काम को छोड़ कर। सारा का सारा काम ईडीएमसी को करना है। मैं केवल पांच गलियों को मैंशन करूंगी। जगतपुरी गली नं. 2, नन्द नगरी सी-3 में पॉयल मैडिकोज वाली गली, चंद्र लोक में गली नं> 2, ललिता मंदिर, अशोक नगर, वैलकम में जीबी-6 वाली गली। ये सारे वर्क जो हैं, ये जून 2016 से पेंडिंग है। मतलब इनका सब कुछ हो गया है, पैसा जा चुका है सब कुछ। वैसे मेरे यहां लगभग साठ गलियां हैं। जिनका पैसा तक एमसीडी से कट चुका है और इन गलियों में तो ये आतंक कट गया है कि तीन-तीन, चार-चार महीने से वो गलियां खुदी पड़ी हैं और जब आप उनसे बात करो कि तीन महीने से चार महीने से गली खुद गई है, अब गली बन क्यूं नहीं रही है तो उनको याद आता है कि ठेकेदार के बेटे की शादी है। ठेकेदार की बेटी की शादी है तो क्या उनको ये नहीं पता था तीन महीने पहले कि बेटै या बेटी की शादी होनी वाली है और जेई ऑन रिकार्ड यह कहता है ठेकेदार से कि काम नहीं करना है और जेई पार्षद के कहने पर काम कर रहा है। तो ये एक सच्चाई है जो जनता के सामने आनी चाहिए कि ईडीएमसी को जो एमसीडी....या तो एजेंसी बदली जाए....(530) हमें जिस तरह फल्ड इरिगेशन जैसे अनाथराइज कालोनीज में इरिगेशल डीएसआईडीसी काम करती है वैसे यहां पे भी ओपन किया जाए ताकि हम अपना काम ईडीएमसी से कराने के बजाय उनसे काम करवाएं। हां, दो महीने बाद तो वो हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, लाइटों का ये हिसाब किताब है मेरे यहां कि मैंने 2015-16 में लाइटों की रिक्वारमेंट दी थी एमसीडी को, गलती हो गई मेरे से कि एमसीडी को काम दे दिया और वो लाइटें आज तक नहीं लग पाई। एक बार 600 का दिया एक बार 750 का दिया और अभी तक 600-750 जोड़ के अगर

13,500 होता है तो अभी तक दो सालों में मात्र 164 लाइटें लग हैं और उस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो पैसा कहां है, किसके पास है और काम क्यूं नहीं हो रहा। कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आज सबसे बड़ा ये सवाल है कि आज क्षेत्र की जनता तो हमसे सवाल कर रही है। गली का उद्घाटन तो हमने किया था जाके। तो ये इसमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ये बहुत ही सीरियस मेटर है। अगर तीन महीने, चार महीने और एमसीडी बिना हमसे पूछे हमारे पैसे से एमएलए फंड का पैसा तीन महीने का अगर टाइम है तो 6 महीने अपने आप एक्सटेंड हो जाता है,हमें पता भी नहीं चलता कि तीन महीने तक कॉन्ट्रेक्टर ने काम नहीं किया। तो तीसरे महीने के एंड में ऑटोमेटिक्ली जो ईडीएमसी का अधिकारी है, वो कॉन्ट्रेक्टर को एक्सटेंशन दे देता है। ब्लैक लिस्ट करने की कोई पॉलिसी नहीं है। वो केवल नोटिस दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है और ये साजिश है जो विधाायकों के खिलाफ की जा रही है। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में कोई कम्पलेंट हनीं है। लोग पानी से बहुत खुश हैं, लोग शिक्षा से बहुत खुश हैं, लोग स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत खुश हैं पर ये एक साजिश के तहत एमसीडी द्वारा किया जा रहा है कि किस तरह विधाायकों को दबनाम किया जाए और उन्हीं की गलियों में जब वो खुद उद्घाटन करके आए तो उनकी गलियों को तीन महीने, चार महीने तक छोड़ दिया जाए और तीन-चार महीने तक उसका निर्माण न किया जाए। आप सोचिए, हम खुद जिस गली में रहते हों, तीन महीने तक अगर वो गली नहीं बनेगी तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे। तो आज ये मेरे यहां पर पूरी स्थिति है ईडीएमसी की और यही शायद सबके यहां पर भी होगी। तो इसके लिए आपको कमिश्नर को सम्मन करना पड़ेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उनसे वाद-विवाद हो। मैं ये सब चाहती हूं कि ये काम क्यूं नहीं

हुआ और अगर नहीं हुआ तो पैसा दिल्ली सरकार को वापस किया जाए, ब्याज के साथ वापस किया जाए। धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश त्रिपाठील जी।

श्री अखिलेश त्रिपाठी : धान्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : शॉर्ट में बोले थोड़ा।

श्री अखिलेश त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगा, बहुत छोटे में। आज जब चर्चा अभी शुरू किया था शास्त्री भाई ने जैसे लग रहा था कि किसी घाव को कुरेद दिया गया हो। हालात क्याहै एमसीडी का? वर्ष 2013-14 चूंकि दिसम्बर में चुनाव हुए और एमएलए बन के 2013 में बहुत सारे साथी 28 लोग यहां पर बहुत सारे बैठे हुए हैं, बने। जो पीछे एमएलए थे, उनका 2013-14 का बजट भी हम लोगों का सुपुर्द किया गया। कई मीटिंगें हुइह मारी मॉडल टाउन विधाान सभामें मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि संगम पार्क वार्ड में लाल बाग में काम करने के लिए 26 लाख रूपये एमएलए फंड में दिया गया 2013 में। आज तक वो काम नहीं हुआ। जब मीटिंगें हुई, कहा गया कि भई, आप नहीं काम करना चाहते हो तो पैसे वापस कर दीजिए। हालत ये है कि मुझे लगता है कि इसमें घोटाला हो गया और सारा का सारा पेमेंट कर दिया, काम एक पैसे का नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड काम बता के बता रहा हूं कि इसी प्रकार संगम पार्क में 6 ब्लॉकों में घरों की पाइप लाइन बदलने के लिए 9-9 लाख रूपये के हिसाब से दिए गए। एक रूपये का काम नहीं हुआ। कहां गया पैसा? कई मीटिंगें हुई, कुछ नहीं बताने को तैयार हैं। धार्मपुर लाज में साढ़े चार लाख रूपये के शौचालय बनाने का काम उनको दिया गया था रेनोवेशन का 2013 में। कहते हैं, काम हो गया जी। वहां की

सारी जनता ने लिख के दिया कि एक ईंट, एक टाइल नहीं लगाया गया एमसीडी द्वारा। वो कहते हैं कि काम हो गया। तो मैं सबसे पहले ये मांग करना चाहता हूं कि 2013-14 का एमएलए निधि कहां कहां यूज हुआ, उसका कम्पलीशन सर्टिफिकेट किसने दिया, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है 2013-14 के एमएलए फंड के लेड में। 2014-15, 2.15-16, और 2016-17 में। सरिता कह रही थी कि तीन महीने, चार महीने छोड़ देते हैं, 6-6 महीने छोड़ देते हैं, रोड नहीं बनती औरहपले अर्बन विलेज फंड हुआ करता था, अर्बन विलेज डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट फंड उससे मैंने राजपुरे गांव में 11 सड़के बनाने के लिए दी, हालत ये है कि उनमें से आधाी सड़कें भी आज तक नहीं बनी। 2014 में दी गई थी। एक एक सड़क का रिकॉर्ड याद है, 2014 में एमएलए फंड से ईश्वर कालोनी में 18,500 लाख बजट दिया गया सड़क बनाने के लिए मॉडल टाउन विधाान सभा में। वो कहते हैं कि फाइल ही गायब हो गई। अब पता चला, पीछे अभी 10 दिन पहले धारना करना पड़ा एमसीडी के इंजीनियर के कमरे के बाहर और तब चला पता कि अब फाइल मिल गई है। आज तक काम शुरू नहीं हुआ एक मीटिंग में 2013-14 में, 2014-15 में राणा प्रताप बाग में सड़क बनाने के लिए पैसे दिए गए। जब धारना किया तो दो दिन पहले अब जा कर सड़क बनी। क्या कर रहे हैं! ये जनधान का राजनीति के चक्कर में नाश क्यों कर रहे हैं? इस तरीके की बोखलाहट, इस तरीके का पागलपन, इस तरीके का बदला लेने का दु:स्साहस आज भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठकें कर रही हैं। चूंकि मैं शहरी क्षेत्र का विधाायक हूं। अध्यक्ष जी, हमारे यहां 95 परसेंट जो काम होता है, वो एमसीडी के माधयम से करना पड़ता है। हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है काम कराने के लिए। डेढ़-डेढ़ साल हो जाते हैं लिखकर के दिए

कि फलाने काम के लिए आप एस्टीमेट बना के दीजिए, एस्टीमेट बना के नहीं देते। जिन सड़को के लिए पैसे, नया रोड बनाने के लिए पैसे दे दिए गए हैं उनमें अगर पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए जाते हैं, सीवर की लाइन बिछाने के लिए जाते हैं तो एमसीडी वाले आके कहते हैं कि इसकी रोड कटिंग का पैसा दो। हम कहे, ''भाई किस बात का पैसा? जब नया रोड बनाने के लिए पैसादे दिया तो किस बात के पैसे चाहिए?'' वो कहते हैं, ''नहीं जी, हमें पैसे तो चाहिए।'' और इसका उदाहरण है राणा प्रताप बाग में रोड बनाई। इसके पहले हम पानी की लाइन और सीवर की लाइन बिछा रहे थे। आज के डेढ़ साल पहले उन्होंने कहा कि नहीं जी, पैसे चाहिए हमें और अन्ततः मजबूरन काम करवाना था और उनको हमतें साढ़े पांच लाख रूपया रोड कटिंग का देना पड़ा। कमाल हो गया! कमाल हो गया! क्या चल रहा है? क्या तंत्र है? क्या एमसीडी कर रही है? ये जनधान का किस तरीके का दुरूपयोग है? एमएलए फंड एक बहुत महत्वपूर्ण फंड होता है। कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं पूछते। पूछते, हां जी, करेंगे? आज तक किसी भी ठेकेदार को एक भी नोटिस एमसीडी नहीं दिया, एक भी ठेकेदार को नोटिस नहीं दिया कि आपने काम समय पर नहीं किया। आप मंगा लीजिए रिकॉर्ड। अगर दिए होंगे तो इनको सौ परसेंट नंबर दे दिए जाएगा। क्या कर रहे हैं? ये बैठकर के दुश्मनी इस तरीके से काम करेंगे आप, नहीं इसी तरीके से एक चर्चा से हटकर एक बात बताना चाहताह ूं।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री अखिलेश त्रिपाठी : एक मिनट, एक मिनट लगेगा। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने डीडीए के कुछ अधिकारियों को बुला खा था डारेक्टर हॉर्ल्टिकल्चर

को और वहां पर चर्चा क्या हुई कि 108 जगह कुछ....डूसिब का मैं मेमबर हूं, वहां पर बात हो रही थी 108 जगह शौचालय बनने की अलग-अलग ग्रीन लैंड में और डीडीए के लेंड में। परमिशन छठे महीने 12.06.2016 का है। आज तक बनके तैयार हो जाते सारे शौचालय। मैंने जब उनसे पूछा, ''भाई साहब, ये आपके एसओ आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं बार-बार काम रोकने? 6 महीने हो गए, काम नहीं होने दे रहे। वो बोले, ''जी, पिछले हफ्ते हर्षवर्धान जी ने मीटिंग ली थी। उन्होंने बोला था कि होल्ड पे रखो।'' शेम! धिाक्कार है ऐसी राजनीति पर! धिाक्कार है ऐसी राजनीति पर! सुनकर के जनता, 300-300 जनता खड़ी थी। उन्हें थू-थू करी, धिाक्कार किया ये राजनीति है! ये कर रहे हैं आप लोग! एक तो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि 108 जगहों पर आज भी जबकि लैंड कमिश्नर, डीडीए का परमिशन मिला हुआ है। 12.06.2016 को। लैंड का मालिक ये कहता है कि आप करो। लेकिन फिर भी कहते हैं कि फिर भी हम नहीं होने देंगे, ये हालत है!

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, अब कन्क्लूड करें। नहीं, अखिलेश जी, अब कन्क्लूड करें। देखिये, मुझे सभी सदस्यों को समय देना है।

श्री अखिलेश त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि एमएलए फंड की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम बने। जो अधिाकारी जिसको समय से नहीं यूज करते, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उनको क्या दंडित किया जा सकता है, किस तरीके से उनको काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, कोई न कोई सिस्टम बनना चाहिए। अध्यक्ष जी, क्योंकि जनधान का, इस दुश्मनी के चक्कर में एमसीडी जो कर रही है, आज भी 1 करोड़ 84 लाख रूपये मेरे पास बचा हुआ है। 1 करोड़ 84 लाख रूप्ये रोड बनने को

खड़े पड़े हैं। जिम्मेदार कौन है आज? कौन जवाब देगा? और पूछते हैं कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टियों को जो बैठकर के जनता का भला नहीं, जनता के कामों में रोड़ा डाल रहे हैं! बहुत बहुत धान्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे बहुत चीजें कहनी हैं कि सफाई नहीं होती, नाली नहीं निकलती, सफाई कर्मचारियों को कुछ पैसे लेकर के छुट्टी दे दिया जाता है कि आप काम नहीं करना। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको जनता बताएगी। लेकिन इसमें मॉनिटरिंग सिस्म बनना चाहिए, पूरा सदन इस पर प्रस्ताव ली लाए, मैं चाहता हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वूर्ण है कि एक प्रस्ताव पूरा सदन लाए कि इस पर क्या होगा। (540)

अध्यक्ष महोदय : गिरीश सोनी जी। बहुत संक्षेप में रखिए प्लीज। कई नाम हैं। थोड़ा सा मेरी प्रार्थना है व्यक्तिगत।

श्री गिरीश सोनी : धान्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा कि एमसीडी का विषय आया तो काफी हमारे विधाायक साथियों का दर्द निकल के आया तो एसो ही कुछ मेरे इलाके में भी काफी समय से मैं एमसीडी को झेल रहा हूं। लाइटों के मामले भी हैं। लाइटें नहीं लगी है और दूसरा ये कैसा मामला जो उन्होंने अटका के रखा हुआ है, वो मेरी समझ से बहुत अजीब, परे है इसलिए मैंने सदन में रखना उचित समझा उसे। क्योंकि एक सवा करोड़ यपये की लागत की एक सीवर लाइन रघुबीर नगर इलाके में हमने पास कराई थी। तो वहां के एक पार्षद हैं प्रदीप शर्मा, उन्होंने जल बोर्ड को एक लेटर दिया था हालांकि जल बोर्ड ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। सीईओ को एक लिखित पत्र दिया जो ये आरआर कट का चार्जिज है, वो आपको देने के आवश्यकता नहीं है। मैं

गलियां बनवा दूंगां तो खैर! मुझे उसके विषय में न ही जल बोर्ड ने कभी सूचित किया और वो लाइन पास हो गई जब बिल्कुल फ्लोर पर काम आने वाला था कि इस काम की एनओसी चाहिए एमसीडी से तो पार्षद साहब मुकर गए। कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। फंड नहीं है। अब फंड नहीं है, सवाल ये आया कि फंड नहीं है तो आखिरकार ये गली बनेगी कैसे? तो कहते हैं, नहीं जल, जल बोर्ड, हम एनओसी....एमसीडी कहती है कि हम एनओसी तभी देंगे कि जल बोर्ड इसका आरआर कट का चार्ज जब जमा कराए और तब हम इसको एनओसी देंगे और तभी लाइन डलने देंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां जनता इतनी परेशान है दो साल से, मैं जैसे-तैसे....सवा करोड़ का मतलब होता है एक करोड़ से ऊपर का जो लाइन पास कराया जाता है, उस पर सीईओ लेवर तक का अप्रूवल चाहिए। जैसे-तैसे वो पास कराया। एमसीडी ने उसको ये कहा कि अब हम एनओसी नहीं देंगे और मैंने जल बोर्ड से बात की तो जल बोर्ड ने कहा कि हमारे पास अभी इसके लिए फंड नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा होता आया है कि अगर पार्षद लिखकर दे देता था तो हम उस गली को बना देते थे। अ उस काम को अटका दिया गया। मैंने कहा ऐसा है कि मैंने एमसीडी को एक लिखित पत्र दिया। उस पत्र में सारा हवाला दिया कि इतनी गलियां हैं, ये सब गलियों का एस्टीमेट हमारे को बना के दीजिए। हम एमएलए फंड से उस गली को बनवायेंगे, न तो वो उसका एस्टीमेट बना के दे रहे हैं, कहते हैं, ''ये नहीं, उसके हमारे नियम में नहीं है। हम तो जल बोर्ड से ही लेंगे। जब एमएलए अपने फंड से कुछ भी करा सकता है। जब ग लियां बनवा सकता है तो उसको उसका एस्टीमेट एमसीडी क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां सीवर लाइन ये न डल जाए। किसी तरह से उस काम को रोकने के लिए और सब जो माननीय पार्षद जी थे, उनकी एक मंशा

ये थी क्योंकि जो पहले भी मेंटलिटी कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति की रही है, वो यही रही है कि मेरे बोर्ड कैसे लगें। क्योंकि उनको बोर्डग लगाने के शौक हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं वहां पर जितने ज्यादातर काम सिर्फ यही हो रहे हैं कि पार्कों में तख्तियां लग जाएं ''इस पार्क काविकास कार्य. ...दाना लगा दिया थोड़ा सा और तख्ती लग जाए, कहीं बोर्ड लग जाए और कही स्टेडियम का उद्घाटन हो जाए, हां, गलियों के नाम इस तरह से वो नामकरण में लगे हुए हैं इस समय। तो ये समय उनका एक जो विचार था कि यहां पर सीवर लाइन डलेगी और जो गली बनेगी, उस पर मेरा बोर्ड लग जाएगा कि ये विकास कार्य फलां निगम पार्षद के प्रयासों द्वारा किया जा रहा है। तो उस मंशा पर पानी फिरते नजर आया और उन्होंने एमसीडी को न तो एनओसी देने दिए और न ही एमसीडी, मैंने डीएम के माधयम से पूछने की भी कोशिश की कि आप उनसे पूछिए कि आखिरकार ऐसा क्या है कि एमएलए इसको बनाना चाहता है, एस्टीमेट बनाएं, एस्टीमेट पहले ले लें। एस्टीमेट बनाके दे दो और उसका फंड डूउा से मैं पास करा सकता हूं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वो कहते हैं कि नहीं जी, एनओसी नहीं मिलेगी। तो मैं बड़ा परेशान हूं। मैं सदन के माधयम से चाहता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पूछा जाए कि आखिरकार उसको क्यों नहीं बनवाया जा रहा है। जबकि मेरा फंडभी बचा हुआ है। मैं फंड देने के लिए तैयार हूं, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और जल बोर्ड के पास अभी फंड नहीं है। अगले साल में फंड आएगा तो जब तक जाएगा, तब तक लोग काफी परेशान हैं। तो इसका कुछ न कुछ और कम से कम मैं उसका जितना फंड गलियों को लगभग पौने दो करोड़ रूपये गलियों को बनाने का बनता है क्योंकि सवा करोड़ जब उसका सीवर लाइन का है, वो भी मैंने फंड बचासकर रखा हुआ था

जो कि अब मेरा लेप्स होगा। मतलब कहने का, अगले साल में लॉक हो जाएगा। इसलिए इस पर जरा धयान दिया जाए, धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : महेंद्र गोयल जी।

श्री महेंद्र गोयल : धान्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 10 नाम हैं। एक को मैंने अलाउ किया। मैं 10 को अलाउ करवा दूंगा। भई दो मिनट रूक जाओ। हां महेंद्र जी, शुरू करें, संक्षेप में रखिएगा।

श्री महेंद्र गोयल : धान्यवाद अध्यक्ष जी। वैसे तो एमसीडी पर मेरे काफी साथियों ने बोल दिया है। अखिलेश भाई का तो दर्द ही आज घड़े से बाहर आ गया। आप क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी कनक्लूड करने के लिए बोले तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह देता हूं कि अप्रैल के महीने में कनक्लूड कर देंगे एमसीडी को। जहां पर हम लाइटों के लिए पैसा देते हैं एमसीडी को, आज तक नही लगी। गलियों के लिए या बैक लेन के लिए पैसा देते हैं या नालियों के लिए पैसा देते है वो पैसा फरवरी, 2016 से मैंने अपने फंड से दिया हुआ है लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ बहुत दु:ख होता है। पार्कों के लिए जो एमसीडी के पार्क है उसके लिए एमएलए ने अपने खाते से फंड दिया हुआ है। उसके लिए भी काम नहीं हुआ ये बड़ा ही दु:खदायी है। कहीं पर डिटेल में जाऊं और आप वहीं कनक्लूड की भाषा मेरे लिए इस्तेमाल करें, कनक्लूड का मैंने आपको शब्द बता दिया। अप्रैल में तो हो ही जायेंगे, ध न्यवाद जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धान्यवाद। जितेंद्र तोमर जी।

श्री जितेंद्र तोमर : बहुत महत्वपूर्ण चर्चा....

अध्यक्ष महोदय : तोमर जी, आप बोलिए प्लीज।

श्री जितेंद्र तोमर : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरे साथी बात कर रहे थे एमसीडी की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी कि अधिकारी यहां दोषी नहीं हैं, दोषी हमारे बैठे हैं, प्रतिपक्ष के नेता। इनकी पार्टी जो है उसको क्योंकि दस साल हो गए हैं निगम पार्षदों को और मेयर स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन, तो वो जो है अधिकारियों को काम करने नहीं देते। जैसे कि अभी आदर्श भाई कह रहे थे कि वो अधिकारी बेंच पर बैठा हुआ था अपने निगम पार्षद उसकी टेबल पर पैर रखके बैठा हुआ था तो ये स्थिति हो गई है कि काम अधिकारी करना चाहे तो भी निगम पार्षद नहीं करने दे रहा, मेयर साहब नहीं करने दे रहे, स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं करने दे रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आज से 6 म हीने पहले इनको नौ ओपन जिम बनाने के लिए कहा, एस्टीमेट बनवाए इनसे, एस्टीमेट बने, तीन महीने घुमाने के बाद इन्होंने कहा कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसको नहीं करेगा। पहले हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा कि करेंगे। तीन महीने बाद कहा कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसको नहीं करेगा, इसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। मैंने उनको बुला लिया। उन्होंने घुमाया तीन महीने। तीन महीने के बाद कहते हैं कि साहब, वो जो डिपार्टमेंट है, जो सेंक्शन देता है, वो नहीं दे रहा है। 6 महीने से पैसा रूका हुआ था, मैंने तुरंत उस पैसे को और कही डायवर्ट किया। क्योंकि मुझे पता था कि पूरा साल ये निकल जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। मैंने उसको डायवर्ट कर दिया कि अगले साल देखेंगे। तो ये सब चीजें जो करवा रहे हैं वो लोग, निगम पार्षद ने लिख कर दिया है और डांटा और

मुझे बताया उस आफिसर ने कि निगम पार्षद ने कहा और मेयर ने कहा कि किसी हालत में भी इन एमसीडी के पार्कों में ओपन जिम एमएलए फंड से नहीं लगने चाहिए। तो अधिकारी डरा हुआ है। सबसे ज्यादा जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहां आन रिकार्ड कह रहा हूं मुझे नहीं पता आपके यहां बाकी ईडीएमसी में और एसडीएमसी में कमिश्नर बैठे की नहीं बैठे....

अध्यक्ष महोदय : महेंद्र जी बैठ जाइए प्लीज। (550)

श्री जितेंद्र तोमर : लेकिन जो नार्थ दिल्ली कारपोरेशन का जो कमिश्नर है जो पहले भी था और आज भी है, इतना मिला हुआ है इन सब लोगों से, सारे भ्रष्ट हैं। बताइये, आप कितने भ्रष्ट हैं और वो भी बहुत बड़ा भ्रष्ट है। मतलब जितनी बार फोन करो, कभी फोन पर आज तक नहीं आते वो। जितनी बार फोन करो, वो महाजन नाम का कोई दलाल रखा हुआ है, वो सब डील करता है। ये तो आप निगम पार्षद अपना रहे हो विजेंद्र जी। आपको सारा पता है। हां जी, तो इतना बुरा हाल है। अब तो एमएलए फोन कर रहा है। चार बार मेसेज छोड़ रहा है। उसका फोन नहीं आता पलट करके कभी। ये हालत है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लिए ये बहुत दर्दनाक है और इस सदन के लिए दर्दनाक बात है ये। क्योंकि मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। मैं काफी चाहता हूं। मैं ये बात कह रहा हूं यहां पर। मैंने तीन बार एक क्वेश्चन यहां पर उठाया। मैंने आपसे प्रार्थना की। मैंने पहले 280 में आज से 6 महीने पहले बात की कि मेरे यहां एक रेलवे अंडर ब्रिज बन रहा है और उस ब्रिज की एलाइनमेंट 13 फुट बाहर है। अपनी एलाइनमेंट से 13 फुट अंदर चला गया है वो और उसको यहां भी उठाया। बहुत बार, एक बारमनीष सिसौदिया जी को जो हमारे माननीय उपमुख्यमंत्री जी हैं, उनको लेकर के गया

वहां पर मैं, उनको दिखाया। आपके यहां नियम 55 में मैंने दो बार लगाया। मैंने रिक्वेस्ट की कि कमिश्नर साहब को क्वेश्चन एंड रिफ्रेंस कमेटी में तलब कर दीजिए। यहां तलब कर दीजिए। हुआ कुछ नहीं और परसों जो माननीय सांसद महोदय हैं, उसका उद्घाटन कर गये उस लूले-लंगड़े ब्रिज का। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम मेरा नाम नहीं है उसमें। मैं उसमें आपसे बात करूंगा। तमाम लोगों के लिए हैं कि वो ब्रिज जो 13 फुट एलाइनमेंट जिसकी बाहर है, उस ब्रिज का उद्घाटन होक गया और मैं चीखता रहा, चिल्लता रहा। मैंने तीन बार इस सदन में कहा। मैंने पचास बार कमिश्नर को फोन किया। मैंने दस बार चिट्ठी लिखीं। मैंने बीस बार चीफ इंजीनियर को, इंजीनियर इन चीफ को बुलाके वहां पर दिखाया कि भई इसको तोड़ के सीधाा करों इसको। ये कलंक है। दिल्ली के ऊपर कलंक है। इतिहास में रहेगा हमेशा, क्योंकि एक बार उद्घाटन हो गया, हमेशा के लिए हो गया और जो भी वहां देखेगा। विधाान सभा मेरी है। जो वहां से निकलेगा, पत्थर पढ़ने नहीं जायेगा कि पत्थर कौन सा वहां लगा हुआ है। वो कहेगा विधाायक कौन है यहां पर, जिसके यहां इतना, इस पुल का उद्घाटन हो गया। ये पुल चालू हो गया इस तरीके से। तो मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि या तो हमारा अंकुश नहीं है। डायरेक्टर लोकल बॉडीज को आपने बोला, नहीं बोला। क्वेश्चन एंडरिफ्रेंस कमेटी में गया कि नहीं गया। लेकिन कमिश्नर ने कुछ नहीं किया। मनीष भाई के कहने के बाद भी उन्होंने वहां आर्डर किया था। साइट पर आर्ड किया था कमिश्नर को कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। इसको आप हटाईये, तोड़िए। इसको तोड़ के दुबारा बनाइये इसकी एलाइनमेंट। नहीं बनीं। चलिए, अगली बात करता हूं। उसमें पत्थर लगा। मुझे नहीं पता क्या प्रोटोकाल होता है। पत्थर पर हर्षवर्धान जी का नाम है, पत्थर

पर मनोज तिवारी का नाम है, किसलिए? ही इज नॉट एमपी फार दिस एरिया। मनोज तिवारी जिी का नाम है पत्थर पर फॉर्मर जो एक्स एमएलए है, उसका नाम है। जी, अब तो मैं ये कहना चाह रहा हूं और ये पत्थर नहीं है। अभी एक उद्घाटन हुआ उससे पंद्रह दिन पहले कम्यूनिटी सेंटर का। उसके ऊपर क्योंकि वहां काउंसलर कांग्रेस का है, वहां सज्जन कुमार का नाम है। अपना एक्स एमएलए कानाम। ये सब चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। मेरे यहां तो है ही है, बाकी जगह भी होगा, मैं समझता हूं। बाकी जगह भी होगा ये। तो ये क्या है? क्याचल रहा है सब? मुझे नहीं मालूम ये क्या चल रहा है। और सुन लीजिए, पिछले दो महीने से क्या है कि क्योंकि काम तो कोई था नहीं इनके पास, नामकरण बहुत सारे किये इन्होंने। बहुत सारी सड़कों का नाम बदल दिये। पार्कों के नाम बदल दिये और उस पर नाम आता है मेयर साहब का नाम आ गया, काउंसलर का नाम आ गया, पूर्व विधाायक का नाम आ गया और जो मनोज तिवारी का नाम आ गया, पूर्व विधाायक का नाम आ गया और जो मनाज तिवारी का नाम आ गया। क्यों भाई, ये कौन सा प्रोटोकाल है?

अध्यक्ष महोदय : करिए, तोमर जी समअप करिए।

श्री जितेंद्र तोमर : अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर कोई न कोई, जो भी एक्शन हो सकता हो, एक बार दिखाइए कमिश्नर को बुलाके कि भई, ये कौन सा प्रोटोकाल है। प्रोटोकाल ये कहता है कि काम कोई भी करे। जो वहां का सीटिंग एमपी होता है, जो सीटिंग एमएलए होता, जो सीटिंग काउंसलर होता है, प्रोटोकाल ये कहता है कि उसका नाम होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो मैं तो ये ही कहना चाह रहा हूं आपसे, वैसे

मैं विजेंद्र जी बता दूं। अभी आप कह रहे थे कि मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं कि और 15-20 दिन की बात है। वैसे दो-तीन दिन के बाद वो लग जायेगी। चार-पांच दिन में आचार संहिता और अभी अप्रैल के अंदर सूपड़ा साफ होने वाला है। उसके बादहम ठीक कर लेंगे सारे अधिकारियों को। अधिकारी काम करना चाहते हैं। ईमानदारी की बात है कि काम करना चाहते हैं। उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो आपने एडवाईज किया नहीं उनको लेकिन जनता अब उनको ठीक कर देगी और अभी जो आने वाला समय है जब अप्रैल में चुनाव होंगे तो हालत वो होगी जैसे आप दो बैठते हो न यहां पर। तीसरा भाग जायेंगे अगली बार। तो जैसे तीन बैठते हो, वहां पर भी चार-पांच से ज्यादा का मामला बनेगा नहीं। देख लेना आप। बहुत-बहुत धान्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धान्यवाद। सोम जी, बोल लीजिए। नहीं, अब नहीं प्लीज।

श्री सोमदत्त : अध्यक्ष जी, बस एक मिनट। एमसीडी किस प्रकार राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है, इसके मैं एक दो उदाहरण देता हूं आपको। एमसीडी के हाउस में ये पास होता है कि एमसीडी के अधिकारी एमएलए के साथ राउंड पर नहीं जायेंगे। एमसीडी बोलती है कि एमएलए फंड से स्ट्रीट लाईटें नहीं लगायेंगे। एमसीडी बोलती है कि एमएलए फंड से बेंच नहीं लगायेंगे और जो लगे हुए हैं, वो भी हटा देंगे। ये राजनीतिक द्वेष नहीं है तो क्या है?

अध्यक्ष महोदय, एक और बढ़िया उदाहरण देता हूं आपको। एमएलए फंड से विजेंद्र गुप्ता जी ने अपने एरिया में बेंच लगवायें हैं। एमसीडी ने लगायें हैं

और मैं पिछले डेढ़ साल से परेशान हो गया। वहीं एमसीडी मुझे जवाब देती है कि इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है और वही एमएलए फंड से वही एमसीडी इनके असेम्बली के अंदर इनके जिम लगा देती है। हमारे लिए पॉलसी बनेबी, कब बनेगी, क्या बनेगी, कुछ नहीं। सारे नियम सिर्फ हमारे लिए हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है। वहीं एमसीडी बिल्कुल, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं इनकी असेम्बली में एमएलए फंड से जिम लगाये हैं एमसीडी ने। हमारे लिए नहीं हैं, हमारे लिए पॉलिसी बनेगी। कमिश्नर से मिला। डायरेकटर हर्टिकल्चर से मिला लेकिन हमारे लिए नहीं है वो पालिसी। वो पालिसी सिर्फ इनके लिए है। एमसीडी सिर्फ इनके जिम लगायेगी एमएलए फंड से। यही एग्जाम्लप देना चाह रहा था। धान्यवाद।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धान्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी। अजय दत्त जी नहीं प्लीज। अखिलेश जी आप बोल चुके हैं।भई, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? नहीं, ये कोई तरीका है! सोमनाथ जी। वंदना जी बैठिए। प्लीज बैठिए। रिक्वेस्ट है। श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धान्यवाद। आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त रखियेगा, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष जी, सभी साथियों ने अपने मन की पीड़ रखी और ये चार करोड़ का जो फंड हमें मिलता है एमएलए लैड फंड, मैंने कहा न आलमोस्ट दो-दो करोड़ रूपया सबने दे रखा है एमसीडी को। तो इस

हिसाब से कुछ नहीं तो डेढ़ सौ करोड़ रूपया एमसीडी के पास हमारा है जो कि अनएकाउंटेबल है और शर्मिंदा करती है हम सबको कि एमसीडी की जो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है उसे उतना एकाउंटेबल होना एमएलए को, जितना वो एकाउंटेबल पार्षद को है, जितना एकाउंटेबल वो सांसद को है। लेकिन वो है नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इसका कारण ये है कि वहां बैठे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर एमएलए लैड फंड से कम न होने दिया जाये तो जनता के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति घृणा पैदा होगी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी सोमदत्त भाई ने कहा। सत्य है कि रेजल्यूशन नंबर 110 में पास किया गया क एमएलए लैड फंड से एमसीडी के अंदर काम नहीं हो सकता और अगर और कोई एजेंसी काम करना चाहे एमएलए लैड फंड से तो वो एनओसी नहीं देगी एमसीडी। इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम एमसीडछी का और हम 67 एमएलए बैठकें मुख देखते रहें। ये कोई न तो मानने योग्य बात है। मुझे लगता है कि आपके माधयम से कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे सबको मालूम पड़े। दिल्ली के अंदर यह बात तो कम से कम मालूम पड़े सबको कि भई एमसीडी इस तरह से काम नहीं करने दे रही है। क्योंकि टरशिरी लेबल ऑफ गवर्नेंस होने के बावजूद जिसमें एक सांसद है, एक विध ाायक है, एक पार्षद है। उसके बावजूद चूकि आम आदमी पार्टी के विधाायक हर वक्त उपलब्धा रहते हैं, वही मिल पाते हैं तो जनता को आशाएं हमसे ही हैं। पार्षद मिलता नहीं, सांसद मिलता नहीं। अब जनता जब भी कुछ लेके आती है तो उसे क्या पता है कि एमसीडी क्या है जी, ये डीडीए क्या है जी। अध्यक्ष महोदय, हम सबने अपने-अपने फंड दिये हैं लेकिन ये कॉस्टिट्यूशनली भी सबको पता है कि 99 परसेंट वो काम जो कि जनता को दिखते हैं, जो

जनता को चुभते हैं, चाहे वो गलियों का हो, बरसात के पानी का इकट्ठा होना हो, स्ट्रीट लाईट्स का हो, पाके हो हो, पार्किंग हो, सफाई हो, ये सारे काम एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। कराना उनसे ही पड़ेगा लेकिन एमएलए का न तो आदेश मानते हैं, न रिक्वेस्ट मानते हैं, न एमएलए लैड फंड से वो काम करने को राजी हैं। बतायें, क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हम सबने, मेरा ख्याल है हममें से हरेक ने ओपन जिम्स के लिए उनको पैसे दे रखे हैं, स्ट्रीट लाईट्स के लिए उनको पैसे दे रखे हैं लेकिन पैसे भी रख लिये, काम भी नहीं किया। आज पैसे उनके पास में हैं। पैसे वापस नहीं किये गये।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे यहां हौज खास एसएफएस फ्लैट हैं। वहां उसकी बाउंड्री वॉल बनवानी थी। पिछले दो साल से हम उसके पीछे पड़े थे कि एमसीडी के कि भई तुम उसको बनवाने दो। 28 लाख रूपये ले भी लिय। नहीं बनन दिया लेकिन जब हमने किसी और से करवाने का प्रयास किया, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट से तो उन्होंने एनओसी देने से मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि भई, तुम बनाओ। हम देखेंगे जाकर अगर वो इसको अड़ंगा लगायेंगे, उसको देख लेंगे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एफआईआर तक की धामकी दी। पुलिस वाले आये। काम रूकवाने का प्रयास किया लेकिन अंततः वो काम हो गया। आज पूरे विधाान सभा के अंदर वो दीवार जो हमने इरिगेशन और फ्लड से बनवाया है, आज एक मिसाल है। (600) पूरी विधाान सभा के अंदर कहते हैं कि जब आप एमसीडी में आओगे, तब हम अपना काम करवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, उसका कारण

क्या है, जो अरविंद जी अक्सर अपने भाषणों में कह रहे हैं आज कल ये आये थे इनके पार्षद स्कूटर वाले, कोई पंक्चर बनाया करता था, किसी की ठेले की दुकान थी, आज सब के पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, फॉरच्युनर है। कहां से आ रहा है? जिस तरह से इन्होंने एमसीडी को दोनों हाथों से लूटा है और विजेंद्र जी हंस रहे हैं, उनको सत्यता पता है। एक हमारे यहां पार्षद है स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन है शेलेंद्र सिंह मोंटी, 11-11 मकान कहां से आ गये? आज डीडीए की जमीन पर 'द रोज' नाम का होटल बनाया, उसको सील कर दिया गया है, डेमोलिशन के ऑर्डर हैं। अंदर से बन रहा है, हमारे पास प्रूफ है। डीडीए के अधिकारी ने लिख कर दिया है कि यहां पर कंस्ट्रक्शन दचल रहा है। इसके अंदर इल्लीगल हो रहा है लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं! कारण क्या है? कोई स्टे नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है, इन सब को लग रहा है कि इनकी लुटिया डूबने वाली है। जनता ने मन बना रखा है कि पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी का काम अगर कोई कर सकता है, अगर लंदन कोई बना सकता है दिल्ली का, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी बना सकती है और इसलिए घबराहट है। उनको पता है जितने कुकर्म इन्होंने किए हैं एमसीडी के अंदर बैठकर, सब को खोला जाएगा। एक-एक कुकर्म का बदला लिया जायेगा। उनको बताया जायेगा कि किस तरह से आपने कुकर्म किए, जनता के पैसे लूटे, आप जाइये अब सलाखों के पीछे।

अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि जिस दिन आम आदमी पार्टी एमसीडी में आयेगी, उस दिन इन सारे पार्षदों का कुकर्म और लेखा-जोखा लेकर के आम आदमी पार्टी सब को जेल भेज कर रहेगी। अध्यक्ष महोदय, यही एमसीडी जो आज हम सब जानते हैं कि यह मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, आज किसी

से पूछो कि एमसीडी का मतलब क्या है? कहता है, ''मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट।'' इसी एमसीडी को मैं सदन को साक्षी मानकर, आपको साक्षी मानकर कहता हूं, सारे साथी हमोर बैठे हैं, यही एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट से मोसट करेक्ट डिपार्टमेंट बनाकर आम आदमी पार्टी दिखायेगी। मोस्ट करप्ट से मोसट करेक्ट की यात्रा आम आदमी पार्टी करायेगी एमसीडी को। लेकिन मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं चूंकि चुनाव कुछ दिनों के बाद है, हम सब के जो पैसे अटके हुए हैं, उसका क्या होगा? जो हमारे काम अटके हुए हैं, उसका क्या होगा? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कुछ तरीका निकालें, जिससे कि हम सारे जितने विधाायक साथी हैं, जिनका पैसा अटका हुआ है, जिनका काम अटका हुआ है, उसका कुछ तो निवारण निकलें। कमिश्नर को बुलाया जाये और कहा जाये कि हमारे जो काम अटके हैं, जिसके आपने पैसे ले रखे हैं, वो तो कम से कम काम पूरा किया जाये, आपसे गुजारिश है। धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यहां पर सभी सदस्य अपनी-अपनी समस्या बता रहे हैं। मुझे लगता है क अगर समस्या को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाये, उसको एक एंगल से न देखा जाये तो इसका समाधाान हो सकता है। एमएलए पंड जिसमें सीधो तौर पर दो एजेंसीज इसमें जुड़ी हुई हैं; एक अरबन डेवपलमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और दूसरा दिल्ली नगर निगम। पिछले दिनों जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई तो उन्होंने उस व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश की और एक एजेंसी का निर्माण हुआ जिसका नाम था डीयूडीए और डीयूडीए के जो इंचार्ज होंगे, वो डीएम होगा। यानी कि डीएम के तत्वावध ाान में डीयूडीए काम करेगा। बहुत दिनों तक डीयूडीए में असमंजस रहा, डीएम

में यह असमंजस रहा, अधिकारियों में असमंजस यह रहा कि इससे काम कैसे प्रारंभ किया जाये। लेकिन धीरे-धीरे चीजों को, जैसे-तैसे समय बीतता गया, जो दिक्कतें आती रहीं, उसको समय-समय पर तरह-तरह से दूर किया गया। लेकिन कुछ जो मूल सवाल हैं, वो आज भी मुंह बाये खड़े हैं हमारे समक्ष हैं। अगर हम इस चर्चा को आधी और राजनीति से प्रेरित रखेंगे तो हम शायद क्षेत्र के लोगों का भला नहीं करेंगे। अभी नया वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, डीयूडीए तब तक बुकिंग नहीं करता है, जब तक उनके पास एक किश्त बजट की डीयूडीए के पास न आ जाये यानी कि बैंक में पैसा न आ जाये डीयूडीए के पास तब तक....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता : मुझे बात करने दीजिए, आप उसमें जो सुधाार करना हो, कर लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, बोलिये, बोलिये।

श्री विजेंद्र गुप्ता : क्योंकि डीयूडीए की भी उसमें गलती नहीं है। डीयूडीए को चैक बनाकर दिल्ली नगर निगम को देना होताह ै और जब तक पैसा नहीं आएगा डीयूडीए चैक नहीं बना सकता। दूसरा, उससे पहले डीयूडीए बुक करता है उसको। अब प्रक्रिया क्या है कि एक विधाायक ने नगर निगम के अपने लोकल अधिकारी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को कहा कि मेरे फंड से यह सड़क बना दीजिए। उसक बाद वो उस सड़क का ऐस्टिेट बनाएगा, उसका ऐस्टिमेट बनाकर वो आपके पास आयेगा

कि इसमें दस लाख रूपये खर्च होगा। उदाहरण के तौर पर, विधाायक चिट्ठी देगा कि मेरे फंड से इस सड़क को बना दिया जाये, मैं इसके लिए दस लाख रूपये अपने फंड से रिलीज करता हूं। वो चिट्ठी लेकर नगर निगम का अधिकारी डीयूडीए (डूडा) में जायेगा। डीयूडीए उसको बुक करेगा, बुक करने के बाद....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महेंद्र जी, एक सेकेंड। इनको बोल लेने दीजिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता : महेंद्र जी, पूरी बात होने दो।

अध्यक्ष महोदय : महेंद्र जी, यह बात ठीक नहीं है प्लीज।

श्री महेंद्र गोयल : मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : महेंद्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। आप बैठिये प्लीज।

श्री महेंद्र गायेल : नेता, प्रतिपक्ष का वो कर रहे हैं, ये एमसीडी की तरफ से बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महेंद्र जी, बैठिये प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : कोई किसी की तरफ से बोल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो आनी चाहिए न पूरी।

अध्यक्ष महोदय : महेंद्र जी, बैठिये प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : बात पूरी होनी चाहिए न। यहां बात पूरी हो जाये, उसमें क्या फर्क पड़ता है?

अध्यक्ष महोदय : महेंद्र जी, उनको बात पूरी तो करने दो।

श्री विजेंद्र गुप्ता : कुछ आपने बता दी, कुछ मैं बता रहा हूं, उसमें क्या है, मिलक के हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकल जाये।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तोमर जी, मैं देख रहा हूमं सब।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अब सवाल यह है....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नोट कर रहा हूं दो मिनट रूक जाइये प्लीज। वंदना जी, प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : मुझे लगता है जिन मैम्बरों का काम में इंट्रेस्ट है, वो जरूर मेरी बात को धयान से सुनेंगे और यहां पर चाहेंगे मंत्री जी इसका कोई हल निकालें।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, मैं दो मिनट रोक लूं।

श्री विजेंद्र गुप्ता : जी।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा को लम्बा नहीं करना चाहतजा

श्री विजेंद्र गुप्ता : मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : शॉर्ट में कर लीजिए प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही आपको बताऊंगा। उसके बाद वो उसको बुक करेंगे, बुक करने के बाद चैक बनायेंगे। अब चैक कितने का

बनेगा, जितने एमाउंट का ऐस्टिमेट है, उसके 50 परसेंट का चैक बनेगा। लेकिन होता क्या है 50 परसेंट का चैक बनेगा और 1090 परसेंट पैसा ब्लॉक हो जायेगा। मान लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट से डीयूडीए को एक करोड़ रूपये मिला किसी एक विधाायक का....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह लम्बा हो जाएगा।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, देखिये, मैं आपको....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब को मालूम है।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अगर आप नहीं चाहते हैं, अब इसमें जो बेसिक दिक्कत आ रही है....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह दिक्कत नहीं है। यह दिक्कत किसी ने जिक्र नहीं की।

श्री विजेंद्र गुप्ता : दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय : यह दिक्कत है ही नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ता : यह दिक्कत है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट, माननीय सदस्य प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : आप बात को सुन नहीं रहे, आप राजनीति कर रहे हैं यहां पर।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरनैल जी, दो मिनट रूकिये। सोमनाथ जी, प्लीज बैठ जाइये। इनको कह लेने दीजिए जो कहना चाह रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं। मैं अभी बात लेता हूं, दो मिनट रूक जाइये। जगदीप जी, दो मिनट बैठिय प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : मान लीजिए, मैंने एक करोड़ रूपये के कामों की गुहार की। डीयूडीए ने पचास लाख रूपये रिलीज कर दिये। पचास लाख रूपये डीयूडीए के पास है। मैं उसक बाद अगले एक करोड़ दसवें लाख पर अगर चिट्ठी देता हूं तो डीयूडीए कहता है कि आपका पैसा अभी नहीं है, आपका पैसा खत्म हो गया है। मैंने कहा कि 50 लाख का तो आपने चैक दिया है 50 परसेंट का, 50 लाख आपके पास अभी हैं। आप इस 50 परसेंट में मेरी फर्दर बुकिंग कर लीजिए। वो कहते हैं नहीं, हम बुकिंग नहीं करेंगे जब तक हमारे पास.... (610)

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप विषय को कंफ्यूज कर रहे हैं या खुद कंफ्यूज हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ता : इसका मतलब आपने कोई काम नहीं करवाया, आप चाहते ही हैं हल न निकले। आप हल नहीं चाहते।

....(व्यवधान)

श्री विजेंद्र गुप्ता : मेरे क्षेत्र के काम होते हैं एडवर्टाइजमेंट आता है और मैं वहां का विधाायक हूं, मेरा नाम वहां से हटाया जाता है।....(व्यवधान) के लिए सरकार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज दो मिनट बैठिये। विजेंद्र जी, दो मिनट बैठिये अब। जो सदस्यों ने समस्याएं उठाईं, शायद विजेंद्र जी ने नोट नहीं की। उन्होंने कहा कि नगर निगमों में ये पास हुआ कि विधाायक के फंड से लाइटें न लगें। नर निगम में ये पास हुआ कि क्षेत्रीय विधाायकों के नाम न आएं। मैं स्वयं पीड़ित हूं। इंजीनियरिंग विभाग ने, मेरे पास सबूत है, लैटर है, एल जी को लिखकर भेजा है। इंजीनियरिंग विभाग ने लिखकर भेजा है एक सिस्टमैटिक्ली कि किन-किन लोगों के इस प्लेट में नाम आएंगे। जहां मेरा नाम प्रोटोकोल के हिसाब से रखा था, मेयर ने, अपने सदन के बीच में स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेयर ने अपने साइन करके वो काटा है, आप अपनी बात कह रहे हैं। ये परंपरा शुरू की है। आपके यहां से शुरू हुई है, नगर निगम ने शुरू नहीं की।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, वैसे तो माननीय सत्येंद्र जैन जी जवाब देंगे, दो मिनट बैठिये, सोमनाथ जी बैठिये दो मिनट। पहले हम लोग यूडी को अपना लैटर देते थे, यूडी फंड देती थी। यूडी की जगह अब डूडा फंड दे रही है जिसको भ्रमित कर रहे हें। डूडा 50 प्रतिशत देती है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जो जानकारी देना चाह रहा हूं कि मैंने अगर किसी

काम के लिए 20 लाख का लेटर दिया तो डूडा मेरे 4 करोड़ में से 20 लाख रिजर्व करेगा, दो मिनट रूक जाइये, मुझे बोल लेने दीजिए, यूडी भी ऐसा ही करती थी, सिस्टम भी यही है, उसमें से 50 परसेंट इनको देगा एमसीडी को जिस भी एजेंसी को हमने काम दिया है और 50 परसेंट उस अमाउंट का तब देगा, जब वर्क कंप्लीट हो गया वो जाकर वहां लैटर ऑफ कम्पलीशन देंगे, 50 परसेंट रिलीज कर देगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे एक काम के अगेंस्ट मैंने जो 20 लाख का लैटर दिया, भई सोमनाथ जी, प्रेस बैठा है, मीडिया बैठा है, जो इन्होंने गलत बोला है, स्टेटमेंट दी है, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं कि डूडा कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट मैंने 10 लाख का लैटर दिया है या 20 लाख का दिया है उस 20 लाख में से 10 लाख दे दिया जो विजेंद्र जी ने स्टेटमेंट दी, 10 लाख उनको कंप्लीशन पर देना है वो बाकी 10 लाख जो मेरा बचा हुआ है, जब तक काम पूरा नहीं होता, कोई भी डिपार्टमेंट उस 10 लाख रूपये में से एक रूपया नहीं दे सकता और न देगा लीगली। आप मिसगाइड कर रहे हैं, इतने बड़े, विपक्ष के नेता होकर। चयि बोलिये।

श्री विजेंद्र गुप्ता : 4 करोड़ हैं न? आप 4 करोड़ एक साथ दिला दो डूडा क ो चाहे जो मर्जी कर लो आप। 4 करोड़ एक साथ नहीं मिल रहा है डूडा को, टुकड़ों में मिलता है और वो पूरा हो जाता ह ।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भाई साहब दूसरी बात आपने कही।

श्री विजेंद्र गुप्ता : आप ये तो मानते हैं कि टुकड़ों में पैसे मिल रहे हैं डूडा को, ये भी नहीं मानोगे आप।

अध्यक्ष महोदय : क्या कौन सी बात?

श्री विजेंद्र गुप्ता : यूडी के पास पूरा पैसा है, हूडा के पास किश्तों में आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान सत्येंद्र जैन जी।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय साढ़े छह बजे तक बढ़ाया जाता है अब दो मिनट शांत, सदन शांत हो जाए, प्लीज। माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं बोलने के लिए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखें। अभी सोमनाथ भारत जी ने कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के एमएलए लोगों से मिलते हैं, एमपी साहब तो पता नहीं, सातों के सातों कहां गायब हो गये, किसी को पता भी नहीं है और काउंसलर भी, उनसे लोग डरते हैं। थोड़ा सा उनसे....जाते हैं, पता नहीं कहीं नजराना न मांग लें, क्या हो जाए! तो अब कुछ भी हो सकता है। तो दरअसल क्या है उस वजह से हमारे जो एमएलए साहिबान हैं, उनके एमसीडी के जो काम हैं, वो भी लोग उन्हीं के पास लेकर आ जात हैं कि जी, हमारे

सारे काम आप ही कर दो। वो कहते हैं, ''भाई साहब, ये काम तो एमसीडी का है।'' कहते हैं, ''जी, वो तो नालायक हैं। वो तो करते ही नहीं हैं।'' तो कहते हैं, ''आप ही करा दीजियेगा।'' ऐसा अनुभव मेरा भी है। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसा अनुभव रहा है। अब अखिलेश जी ने जैसे बताया। मैं खुद इनके एरिया में गया था और वहां पर बड़ी दु:खद स्थिति थी। दिल्ली सरकार ने बड़ी मेहनत करके झुग्गी बस्तियों में जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं, सभी के अंदर टॉयलेट बनाने के लिए डीडीए से एनओसी लिया और डीडीए ने सभी के लिए इकट्ठा एनओसी दिया। काफी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। लैंड कमिशनर ने एनओसी दिया था और केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े पद पर बैठकर जो पहले इसी सदन के सदस्य थे, उनको शोभा नहीं देती कि भई, इस तरह की बात करें कि भई, आप लोग टॉयलेट ने बनायें, आप काम रूकवा दें तो इस तरह की बातें गलत हैं। कम से कम अगर काम नहीं करते, जनता से नहीं मिलते हैं तो रूकवाने वाला काम तो न करें न। इस तरह का काम ठीक नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसा काम रोक रहे हैं, करवा नहीं सकते तो रूकवाना नहीं चाहिए पर क्या करें उनका कल्चर है। कल्चर ही ये है कि काम करते नहीं हैं, कहते हैं, ''न करूंगा, न करने दूंगा।'' अपने यहां कुछ किया नहीं, दूसरों को करने दिया नहीं तो ये शुरू से लेकर आखिर तक बीजेपी 10 दस साल से कारपोरेशन के अंदर है, इनके दस काम छोड़ो, एक काम बता दें जो इन्होंने किया हो, कोई काम नहीं किया पैसे खाने के अलावा। अभी गिरीश सोनी जी ने बताया ये रोड कटिंग है अब एमसीडी वालों से पूछो 30 फुट की रोड होती है अगर तुमने पानी की पाइप भी डालनी है, कहते हैं पूरी सड़क का खर्चा लेंगे। भई, क्यों लोगे पूरी सड़क का खर्चा? पूरी सड़क का खर्चा किसलिए लोगे? जितना तोड़कर....आजकल मशीन आती

है मशीन से काट लो एक फुट का खर्चा ले लो। अब 15 फुट का या 20 फुट का या 30 फुट का खर्चा क्यों ले रहे हो। पता चला पाइप लाईन तो डली है 3 लाख की और रोड रेस्टोरेशन और कटिंग चार्जेज बन गये 30 लाख रूपये के तो ये जो चीजें हैं। अब जैसा तोमर जी ने बताया कि ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पूर्व विधायक का नाम पत्थर पर लिखवाया जा रहा है तो ये तो पता नहीं कौन सा प्रोटोकोल है, कैसा प्रोटोकाल है कि अगर पूर्व विधायक और (620) अभी राजेश जी ने जैसे बताया कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट का नाम सरकारी कार्य के ऊपर लिखा जा रहा है तो किस तरह की परंपरा ये स्थापित कर रहे हैं, यह थोड़ा समय से बाहर है। ये हते हैं कि एमसीडी के आफिसर्स को आदेश दिये गये हैं कि आप एमएलए के साथ राउंड पर नहीं जायेंगें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या करना चाहते हैं। राउंड पर तो वो काउंसलर के साथ भी नहीं जाते हैं। क्यों नजीं जाते हैं कि ये काउंसलर के पास टाईम नहीं है। अब एकएलए जाना चाहते हैं, उनके साथ कोई जाता नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि भई ये तो जायेंगे तो जनता के सामने शक्ल दिखानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। आदर्श शास्त्री जी ने बताया अभी कि आफिसर्स खुद कह रहे हैं कि जो नेता हैं, सो कॉल्ड पार्षद हैं या कांउसलर्स हैं, आफिसर्स खुद कहते हैं कि उनको काम करने से रोका जाता है। वो कहते हैं कि हमें काम करने से रोका जा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, रानी बाग के अंदर एक पार्किंग है। 2013 के इलेक्शन 2014 के इलैक्शन 2015 के इलैक्शन तीन इलैक्शन मैंने खुद देखे हैं। दो बार एमएलए के एक बार एमपी का। उससे पहले 2012 से पहले उसका उद्घाटन किया। 2013 के अंदर हमारे इलैक्शन के टाईम पर वो बहुत बड़ा मुद्दा था कि जी पार्किंग बनायेंगे, पार्किंग बनायेंगे। 2014 के एमपी

इलैक्शन में उन्होंने कहा कि पार्किंग बनेगी। 15 के इलैक्शन के अंदर फिर से कहते हैं पार्किंग बनायेंगे। उसका उद्घाटन नारियल फोड़ दिया। आज तक 2017 आ गया, अभी तक कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, इस बात की गारंटी है। मतलब इनको क्या लगता है कि काम को करना या शुरूआत करनी या सिर्फ उसका नारियल फोड़ना बराबर है। ये तो उस तरह के लोग है कि कोई भी काम नहीं किया Work not done puls some good excuses is equal to work done. अब ये जो मैथमैटिक्स था न नेताओ ंवाला, अब जनता को समझ में आने लगा है। जनता को सब समझ में आता है कि नारियल फोड़ने की संस्कृति जो है कि हर जगह नारियल फोड़ते चले जाओ, 'आगे दौड़, पीछे छोड़', करना कुछ है नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाना है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे और कब करेंगे साढ़े चार साल के बाद इनको याद आती है। आज जिस एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, वो एमसीडी पूरे पेज के विज्ञापन दे रही है। तनख्वाह तो तुम दे नहीं सकते, विज्ञापन कहां से दे रहे हो? काम तुम करा नहीं सकते, काम कराने के पैसे नहीं हैं, विज्ञापन देने के पैसे हैं आपके पास! हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किये। अक्सर हम कहते हैं, काम हो गया, बात खत्म हो गइर्ह। कुछ एमएलए मेरे साथ मिलने इकट्ठे आये। यहीं बैठे हैं सारे कहते सर, हमारे क्षेत्र में आपने इतना बड़ा काम कराया, आप आ जाइयेगा। मैंने कहा काम हो गया, सफिशियेंट है, कहते चिड़िया और कौए वाली कहीन सुनी होगी आपने। मैंने कहा, ''ये कौन सी कहानी है?'' कहते हैं, ''चिड़िया काम में लगी रहती है, काम करती रहती है। आप लोग दफ्तरों में बैठते हैं, काम करते हैं औरवहां पर कौए फड़फड़ाते रहते हैं। मैंने कहा, ''क्या करते हैं वहां आ के? वो कहते हैं, ''हमने काम कर दिया! हमने काम

कर दिया! कौन लोग है, कहते कोरपोरेटर्स, पार्षद। हर जगह आज जाकरझंडा गाड़ देंगे। मैंने कहा, ''उन पर तनख्वाह देने के पैसे तो हैं नहीं उनके पास।'' कहते, ''प्रचार करने का बड़ा पैसा है उनके पास और बड़ा एक्सपीरियेंस भी है।'' काफी सारे तो प्रचारक ही रहे हैं। उनका काम ही प्रचार करना है। तो वे प्रचार ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। तो उनको प्रचार करने से ज्यादा कुछ आता नहीं है और उनको ये शर्म भी नहीं आती कि कुछ को भी कह देते हैं कि हमने किया है, हमने किया है। अब जनता भी कहती है यार! कमाल हो गया! अभी तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं, हड़ताल हो रही थी। अब ये कहते हैं इतने बड़े-बड़े काम भी इन्होंने कर दिये। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। प्रेमबाड़ी पुल क ऊपर एलिवेटिड कॉरीडोर हमने बनाया। राजेश गुप्ता जी वहां के स्थानीय विधाायक भी हैं। जिस दिन उद्घाटन के लिये गये, मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी था, केंद्रीय मंत्री साहब को हमने बुलाया था, वेकेंया नायडू जी को उद्घाटन करने के लिये। पूरे इलाके में हजारों होर्डिंग, जिस रास्ते से गये, होर्डिंग देख के हमने कहा भई, ये लगता है, कहते हैं बीजेपी वालों ने बना दिये हैं मतलब ऐसे हालात कर रखे थे उन लोगों ने। दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट! दिल्ली सरकार के पैसे से बना! दिल्ली सरकार ने उद्घाटन किया! सब कुछ दिल्ली सरकार का! उसमें बीजेपी के होर्डिंग सारे राज्य में छाप रखे थे! तो मतलब सारे में ये कह दिया, ''अथक प्रयासों से, पता नहीं क्या क्या!'' और मुझे लगने लगाकि इस काम में तो ये बड़े एक्सपर्ट हैं और जनता को कन्फयूज कर देते हैं कि हमने कर दिया और तो और बताऊं आपको कल की एक कहानी बता देता हूं आपको। हमने मिनिमम वेजिज बढ़ाये तो एक पार्क में उनकी बड़ी चड्ढी क्लासेज चलती हैं ना? वहां पर बातें चलती हैं। वो पार्कों में चलती हैं सुबह सुबह। तो उसमें उन्होंने एक बात

चलाई। कहते हैं, ''भाई साहब, देखो मोदी जी ने मिनिमम वेजिज बढ़वा दिये।'' अरे! मैंने कहा, ''भाई साहब मोदी जी ने बढ़ाने थे अपने किसी राज्य में बढ़ा लेते ना। उनका पैसा....राजस्थान है, गुजरात है, मधयप्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। कहीं भी बढ़ा लो। अरे! दिल्ली में तुमने बढ़ाने में एकस ाल डिले करा दिया, छह महीने डिले करा दिया। अगर तुम्हें बढ़ाना था तो अपने राज्य में बढ़ा लेते। कहते, ''रोक नहीं पाये।'' कहते, ''पहले कोशिश तो बड़ी करी थी।'' कहते, ''अब यही कह देते हैं, हमने करा दिया।'' ''अच्छा! अगर कराने का इतना शौक है, मैंने तो आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी से कई सारे काम कहे थे, मैंने कहा, ''पब्लिकली कहेंगे आपने करा दिये, एक नहीं दस काम हैं।'' आप काम होने तो दो। सारा क्रेडिट आप ले लेना। हमारे को क्या है, जनता के काम हो जायें और सब पर पत्थर लगवा लेना, सब पर अपने नाम लिखवा लेना और हम अखबार में देंगे, ''हां जी, इन्होंने होने दिया, ये बहुत बड़ा एहसान किया।'' अगर हमारी दिल्ली की जनता के काम होते हैं, आपने करने दियचे, यही एहसान काफी है। हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है....अब देखियेगा. ...(व्यवधान) फोटो की माला का अभी....(व्यवधान) टाईम नहीं आया। आज अखबार के अंदर फुल पेज ऐड है और उसके अंदर विज्ञापन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फोटो एमसीडी वाले लगवा रहे हैं। मैंने कहा, ''दिल्ली भी आ रहे हैं क्या?....(व्यवधान) अब कहते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनप गये, फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की गई। अब लगता है कि पार्षद बनने की तैयारी है क्या?....(व्यवधान) मेयर नहीं पार्षद....(व्यवधान)....तो मुझे लगता है अगर आरडब्ल्यूए के इलैक्शन दिल्ली में होंगे तो तब भी प्रधानमंत्री का फोटो यूज करना पड़ेगा कि हम इलैक्शन लड़ेंगे।....(व्यवधान) आ जाइयेगा। मैं अपने सारे विधाायकों को एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो परेशान होने

की जरूरत नहीं है। जब इन लोगों को दस साल से झेल रहे हो, दस से नहीं, बीस से झेल रहे हो। ये दोनों पार्टियां एक ही हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पललू हैं। आप सिक्का ऊपर फेंकियेगा; चित्त आये या पट्ट आये, सिक्का वही रहेगा। कांग्रेस आये या बीजेपी आये, कोई फर्क नहीं है। आज भी दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन के अंदर आधाी सीटें कांग्रेस की, आधाी बीजेपी की हैं। न कांग्रेस वाले का काम रूकता है, न बीजेपी वाले का काम रूकता है। काम रूकता है, जनता का रूकता है। आप पता कर लीजियेगा। मैंने इनसे कहा....कई जगह कहा है कि भाई साहब, अब तो दो एक महीने रहे गये। अब तो पैसे खाने बंद कर दो। अगर पैसे खाने बंद कर दो, जनता हो सकता है अभी भी वोट दे दे। कहते, ''क्या बात कर रहे हो, घोड़ा घास ये यारी करेगा तो खायेगा क्या? ऊपर से दूसरी बात....(व्यवधान) चलो, गधाघास से यारी करेगा तो खायेगा क्या!....(व्यवधान) और दूसरी बात, कहते, ''भाई साहब, अब आपके चक्करों में नहीं आने वाले हम।'' मैंने कहा, ''क्या हुआ?'' कहते, ''जी, आपके चक्करों में बिल्कुल नहीं आने वाले।''. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिये, कोई बात नहीं....(व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री : देखिये, घोड़ा ही कहिए, गधाा नहीं।....(व्यवधान) मैंने कहा कि कम से कम पैसे खाने बंद कर दो। दो महीने की बात रह गई। डेढ़ महीने की बात रह गई है। बोलते हैं कि भाई साहब, इतने बेवकूफ नहीं हैं। आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। कहते हैं, ''ये आखिरी मौका है। जो कमाना है,कमा लो। उसके बाद कभी नहीं आने वाले।'' गलती से जनता ने विधाानसभा में तीन भेज दिये थे। काउंसलर तो तीन भी नहीं बनने वाले....

(व्यवधान) तो उनको अच्छी तरह से पता है कि ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहीं आने वाले नहीं है। अब आप लोगों को एक डेढ़ महीना और झेल लीजियेगा जैसे भी झेलना था। अब शिकायतें करने का फायदा नहीं है जनता को बस ये बता दीजियेगा कि ये कुकर्म इन्हीं के हैं। बस, जनता को बताने की आवश्यकता है कि जो एमसीडी है, ये बीजेपी चलाती है, ये कांग्रेस चलाती है और ये दोनों मिल के चलाते हैं। इन दोनों की मिलीभगत से चलती है और दोनों में कोई फर्क नहीं है। इनका असली काम है, सफाई करना। जो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये करते हैं, लोगों की जेब की सफाई। पैसे इकट्ठे करते हैं। किसी से पूछ लीजियेगा। हर बिल्डिंग में एक एक लैंटर पर दो-दो लाख रूपये, एक एक लाख रूपये, पांच पांच लाख रूपये लेते हैं। सबसे लेते हैं। आप ज नता से बताइयेगा अगर इनसे बचता है तो ये झाड़ू अच्दी तरह चलायें, झाड़ू जोर से चलायें और जो पिछली बार गलती हुई थी तीन दाने बच गये, तीन भी नहीं छोड़ने इस बारी। जय हिंद जय भारत। (630)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य, एक सूचना की तरफ धयान दे लें। विशेष रूप से कॉरपोरेशन के विषय में आपकी भावनाओं से मैं अच्छी तरह से अवगत हुआ हूं। स्वयं मैं पीड़ित हूं और मैंने 14 तारीख को ईडीएमसी के कमिश्नर और डायरेक्टर, लोकल बॉडिज को ऑफिस में बुलाया हुआ है, 14 तारीख को 3.00 बजे क्योंकि....एक सैकेंड ईडीएमसी के कमिश्नर, उन्होंने 3.00 बजे का 14 मार्च का समय दिया है, 4.00 बजे। आपकी भावनाओं को देखकर मैं अंदर गया मैंने फिर लोकल बॉडिज डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा कि आप दोनों कमिश्नरों को और बुला लीजिए। एनडीएमसी और साउथ दिल्ली। तो वो दोनों भी आ रहे हैं, तीनों कमिश्नर यहां होंगे। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है एक बार धयान से सुन लें, आपके जो-जो काम जहां रूके हुए

हैं, जिसे डेट पर पैसा दिया, वर्क आर्डर हुआ और काम अब तक चालू नहीं हुआ, काम की क्या पोजीशन है, वो डिटेल कृपया 14 तारीख समय है कल लेते आएं, परसों तो हम सब लोग रिजल्ट में लगेंगे। कल अगर सदन में आएंगे, लेते आएंगे तो मुझे बहुत बड़ी सुविधाा होगी। 5-7 प्वाइंट मैंने नोट कर लिये हैं जो सबने उठाए हैं। उनसे डिस्कश करके फिर जानकारी देंगे सारी....नहीं, बस तीन ये बुलाए हैं प्लीज....वो मुझे दे देना, आप लिखकर दे देना।

श्री सोमनाथ भारती : आचार संहिता लग जाएगी तब तक।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही 10 मार्च, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत-बहुत धान्यवाद और कल चाय की व्यवस्था अब जब भी सदन लगेगा 4.00 बजे चाय और बिस्कुट की व्यवस्थाय हां रहेगी। जब भी सदन की कार्यवाही होगी।

(सदन की कार्यवाही 10 माच्र, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

विषय सूची

सत्र-5 भाग (1) बृहस्पतिवार, 9 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-47

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	
2	विशेष उल्लेख (नियम-280)	
3	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	
4	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	
5	बजट 2017-18 पर चर्चा	
6	माननीय उपराज्यपाल का संदेश	
7	बजट 2017-18 पर चर्चा जारी	
8	विधायक निधि के बारे में नगर निगम पर चर्चा	